हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, मंगलवार, 1978

खण्ड 1 अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 7 मार्च, 1978

पृष्ठसंख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(7) 1

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे

गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

(7) 34

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(7) 34

शोक प्रस्ताव (7)

44

कार्य मंत्रणा समिति की द्वितीय रिपोर्ट

(7) 45

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

(7) 47

वर्ष 1978– 79 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा

(7) 48– 81

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 7 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चन्डीगढ में 9– 30 बजे प्रातः हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह ने अध्यक्षता की ।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवाल होंगे । श्री शमशेर सिंह ।

Loan/Grant Given to M. C. Narwana

***210. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total amount of Loan and grant given to municipal committee Narwana by the Government during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 togetherwith the details of the purpose for which these were given and whether the same were utilized ; and

(b) whether Government proposes to conduct elections to the M.C. Narwana ; if so, the time by which the elections are likely to be held ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन):

(क) एक स्टेटमैट (अनुबन्ध– 1) सदन के पटल स्थल पर रखी जाती है ।

(ख) जी हां । हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1 973, की धारा 277 (3) में की गई व्यवस्था अनुसार सभी नगरपालिकाओं के निर्वाचन 19 जुलाई, 1978 से पूर्व करवाने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

ANNEXURE I

The statement showing yearwise detail of the amounts of loan/ grant sanctioned to the Municipal Committee, Narwana to date : -

(1) Loan

Year	Amount Sanctioned		Purpose
	Water Supply/Sewerage	Minor Development Works	
1975-76	Nil	30,000	For construction of shops, parks and roads.
1976-77	25,000	Nil	For Water Suppy Scheme.
1977-78	Nil	Nil	

(ii) Grant-in-Aid

Year	Amout sanctioned		Purpose
	Water Supply/Sewerage Scheme	Minor Development Works	
1975-76	Nil	Nil	_
1976-77	15,000	20,000	For Water Supply Scheme/For Minor Development such as construction/repair of roads/drains, pavement of streets, community laterines/urinals, street lights, etc.
1977-78	Nil		

(iii) Utilization

Yes.

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, स्टेटमैटं से यह जाहिर है कि पिछले 3 सालों से नरवाना नगरपालिका को लोन और ग्रान्ट्स की शक्ल में तकरीबन न के बराबर रुपया मिला है । क्या मंत्री महोदय वह बताने की कृपा करेंगे कि इस साल में या अगले साख में इस नगरपालिका को और ज्यादा लोन या ग्रान्ट दी जाएगी?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, जरूर देंगे ।

Colleges in the State

***223Chaudhri Sher Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the district-wise total number of Government Colleges in the State at present ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government Colleges in the districts where there are no Government Colleges ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Rohtak 4

Bhiwani 2 (including one College of Education)

Gurgaon 2

Mahendergarh 2

Ambala 1

Hissar 1

Jind 1

Karnal 1

(b) No.

श्री देवेन्द्र शर्मा : वजीर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में कोई भी गवर्नमैंट कालेज नही है, क्या वही पर कोई गवर्नमैंट कालेज खोलने की प्रपोजल है? जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला वगैरा कालेजों के मामले में इग्नोर

निए हुए हैं, क्या वहां परं कोई प्रपोजल है कि कोई गवर्नमैंट कालेज खोला जाए?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी भजन लाल : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जैस कि इन्होंने बताया कि इन जिलों में इतने–इतने गवर्नमैंट कालेज हैं, क्या गवर्नमैंट देहातों में भी कालेज खोलने का विचार रखती है, ताकि वहां पर गरीब बच्चे पढ़ सकें?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैंबर को यह बताना चाहता हूं कि प्राइवेट कालेजिज पहले से ही देहातों में खोले हुए हैं, लेकिन अब तक यह देखा गया है कि उन कालेजिज में एडमिशन जो है, वह इतना कम है, कि उससे कालेज का चलना एक किस्म से बिल्कुल मुश्किल हो रहा है । अगर वहां पर एडमिशन्ज ज्यादा हों, लड़के ज्यादा पढने के लिए आते हों, तब तो कालेज को वायबेल बनाने के लिए वहां पर सरकार द्वारा जरूर कालेज खोला जाएगा, वरना तो अगर एक सौ या दो–दो सौ बच्चों के लिए कालेज खोला जाए, तो रस कालेज को चलाने के लिए कोई हालात ठीक नही रहते? इसके अलावा जो सरकार का फैसला है वह यह है कि ज्यादा जोर इस वक्त प्राइमरी एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन पर दिया जाएगा । हायर एजुकेशन के लिए जो बजट था, उसमें थोड़ी सी कमी करके

प्राइमरी एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ।

डा0 वृजमोहन गुप्ता : स्पीकर साहब, अम्बाला जिला में जो एक कालेज कालका में है, वहां पर सिर्फ आर्टस सब्जैक्ट हैं । मुझे यह भी पता चला है कि वहां पर एटमासफियर भी ठीक नहीं है, और साईंस सब्जैक्ट भी नही है । मैं यह समझता हु कि किसी कालेज में अच्छा एटमॉसफियर होने के लिए वहां पर साईंस सब्जैक्टस का होना लाजमी है । तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हू कि क्या कालका में साइंस कालेज खोलने का विचार है?

कर्नल राव राम सिंह : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि कालेज में एटमॉसफियर बिस्कूल अच्छा रहना चाहिए । इसके बारे में तो कोई दो राय नही है कि अगर खराब एट– माँसफियर है तो वहां पर पढाई ठीक नही हो सकती । मेरा कहना यह भी हे कि एटमॉसफियर को अच्छा करने की पूरी कोशिश की जाएगी । बाकी जहां तक अम्बाला में साईंस कालेज खोलने का सवाल है, इस समय कोई ऐसा विचार सरकार का नहीं है ।

सरदार सुखदेव सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह बताया कि प्राइवेट कालेजों में दाखिले कम होते हैं । मैं मन्त्रो महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसका कारण यह तो नहीं है कि वहां पर लोगों ने ऐसी कंडीशन्ज लगा दी हैं कि इतना पैसा दोगे तो दाखिला मिलेगा यानी रिश्वत वगैरा के वे अड्डे बना लिए

हों, इसलिए वहां पर दाखिले कम होते हों । मेरे विचार में तो अगर कोई उसके लिए दोषी है तो प्राइवेट कालेज वाले दोषी हैं, सरकार बिल्कुल दोषी नहीं है । क्या गवर्नमैंट का कोई विचार है कि रूरल एरियाक में भी गवर्नमैंट कालेज खोले जाएं?

कर्नल राव राम सिंह : जहां तक गवर्नमैंट कालेज रूरल एरियाज में खोलने का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि जब **चौधरी** भजन लाल जी ने सवाल पूछा था, उस समय उसका जवाब ' दिया जा चुका है और जो कुरप्शन की बात है दाखिले के अन्दर मैं इन्हें यह बता देना चाहता हूं कि डिग्री कालेजों के अन्दर दाखिले के लिए कोई कुरप्शन की शिकायत हमारे पास नहीं आई है । हां बी.एड. और दूसरे जो ट्रेनिंग कालेजिज हैं, उनके अन्दर कुरप्शन की शिकायतें जरूर हमारे पास आई है । उसके लिए सरकार पूरा प्रबन्ध कर रहो है कि आईन्दा ऐसी बातें न होने पाएं । जहां तक डिग्री कालेज में क्रप्शन का सम्बन्ध है, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है ।

कवर रामपाल सिंह : मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि रूरल एरियाज में जो कालेज हैं, उनमें बच्चों का नम्बर कम है । क्या मिनिस्टर साहब ने कभी इस बात का जायजा लेने की कोशिश की है कि वहां पर बच्चों की संख्या क्यों कम है? क्या ये जिस तरह जे दूसरे प्राइवेट कालेजों को फाइनैशियल 'रेड देते हैं, इन कालेजों को भी फाइनैंशियल ऐड देने भर विचार करेंगे, ताकि

बच्चों को सहूलियते भी पूरी मिले और वहां पर जो स्टाफ है, वह भी पूरा हो और उनको तनख्वाह भी ठीक मिले?

कर्नल राव राम सिंह : एक बात तो स्पीकर साहब आप मानेंगे कि अगर उनके यहां एडमिशन्ज होंगी, तो स्टाफ की पे भी ठीक होगी These go hand in glove ये दोनों चीजे हैंड इन ग्लोब चलती हैं कि वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा हो तो वे टीचर्ज को ज्यादा तनख्वाह भी दे सकेंगे, नहीं तो नहीं । जहां पर आस पास 20–25 मील तक कोई कालेज नहीं है और प्राइवेट कालेज की मैनेजमैंट उस कालेज को गवर्नमैंट को हैंड ओवर करने को तैयार है, उनको टेक–ओवर करने के लिए सरकार जरूर विचार करेगी ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेगे कि जो प्राइवेट कालेज अच्छी तरह से नही चल रहे हैं, सरकार का उन पर कब्जा करने का विचार है और अगर है तो कब तक उन पर कब्जा कर लिया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : जो प्राइवेट कालेज ठीक से नहीं चल रहे हैं, सरकार का उन पर कब्जा करने का कोई विचार इस वक्त नहीं है । प्राइवेट कालेज तो एक तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं । पिछली सरकार को कहते तो वह तो कभी की इन्हें अपने कब्जे में ले छुकी होती, लेकिन इस सरकार का उन्हें अपने

कब्जे में लेने का कोई विचार नहीं है । यहनहीं चहती कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा किया जाए ।

राव राम नारायण : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस रूरल एरिया में जैसे नाहड में आसपास कोई गवर्नमैंट कालेज भी नही है और वहां की मैनेजमैंट ने एक रैजोल्यूशन भी पास करके भेजा हुआ है, वहां के कालेज को गवर्नमैंट द्वारा टेक–ओवर करने की कोई प्रपोजल है?

कर्नल राव राम सिंह : जैसे कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है! मैं इतना जरूर मैंबर साहेबान को बताना चाहता हूं कि जिन जिलों में गवर्नमैंट कालेज बिल्कुल भी नही है, जैसे सिरसा और सोनीपत, वहां पर सबसे पहले गवर्नमैंट कालेज खोला जाएगा, उसके बाद जिन जिन जिलों में एक एक कालेज है, वहां पर एक एक और कालेज खोला जाएगा । रोहतक में तो आलरेडी 4 कालेज हैं, इसलिए वहां पर नया कालेज खोने का कोई विचार नहीं है । इसलिए मेरा कहना यह है कि उसको अभी टेक ओवर करने में टाईम लगगा ।

श्री लछमन सिंह : मन्त्री साहब ने यह कहा है कि साइंस सबजैक्ट का कोई कालेज कालका में खोलने का विचार नही है । मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जयसे

हाउस चल रहा है मिनिस्टर साहब ने नैगेटिव एप्रोच शुरु कर रखी है, उनकी पोजैटिव एप्रोच कब शुरु होगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, बी.एड. कालेज कैथल के खिलाफ यूनि– वर्सिटी के पास इनक्वायरी रिपोर्ट भी आ चुकी है लेकिन वहां पर सिर्फ एक आदमी 5– 6 लाख रुपया आए साल एडमिशन के वक्त हड़प कर जाता है । क्या सरकार का उस कालेज को लेने का कोई विचार है या नही?

कर्नल राव राम सिंह : मैं पोहलू साहब से बिल्कुल. सहमत हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए । अगर कोई ऐसी शिकायत है तो उसकी इनक्वायरी चल रही है, जब वह पूरी हो जाएगी, और इनक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही जरुर की जाएगी । सरकार यह कतई नहीं चाहती कि जनता का पैसा यूं ही कोई हड़प कर ले । मैं आनरेबल मैंबर को इस बात का यकीन दिलाता हू कि जो इनक्वायरी हो रही है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी की रिपोर्ट आती है, तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जाएगी ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब सरकार की यह नीति डिक्लेयर हुई है कि वह भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और पानी का प्रबन्ध करेंगे, तो लोगों ने स्कूलों में जो यह भ्रष्टाचार के अड्डे बना रखे हैं, कि

बी.एड. की एड– मिशन केलिए 5– 5 हजार रुपया वसूल करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नही होती? मैं इनसे एक बात और भी पूछना चाहत हूं बोहरिया बाबा रोहतक में सबसे बड़ा महन्त कहलाता है, लेकिन वह 6 हजार रुपया एडमिशन केलिए लेता है, क्या इसके जिए कोई मियाद मुकरर्र की है कि इतने पीरियड के अन्दर ऐसे लोगों की इनक्वायरी हो जाएगी, ताकि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके?

कर्नल राव राम सिंह : मैं अपने दोस्त से बिल्कुल सहमत हूं और यह यामल गवर्नमैंट को बहुत ऐक्सरसाइज कर रहा है । इस वक्त बी.एड. कालेजिज में जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, वहां पर काफी डोनेशन की शक्ल में पैसा लेने की बहुत 'शिकायत आई हैं । गवर्नमैंट इस मामले में ऐक्सरसाईजड है और पूरी इनक्वायरीज चल रही है और मैं आपको यह आश्वासन दिला सकता हूंकि उन इनक्वायरीज के होने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी । लेकिन जो इनक्वायरी होती है उसमें हमारे सामने एक कठिनाई आती है कि लिखित रूप में तो शिकायतें आती हैं ' लेकिन जब गवर्नमैंट इनक्वायरी का आर्डर करती है और वहां पर इनक्वायरी के लिए जाते हैं, तो वही लड़के जिन्हेंने छ–छ सात–सात हजार रुपया डोनेशन दिया होता है, गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते । मेरा कहना यह है कि जब कोई शिकायत आए और उसकी इनक्यायरी की जाए, तो सही हालात इनक्यायरी के सामने आने चाहिए ।

चौधरी हरस्वरुप बूरा : क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगर देहात के लोग कालेज के लिए बिल्डिग बनाकर दें, तो क्या सरकार उस कालेज को टेक–ओवर करने के लिए तैयार ।?

कर्नल राव राम सिंह : – स्पीकर साहब, यह मामला पहली दफा हाउस में आया है, अगर सदस्य महोदय यह मामला लिखकर भेजेंगे तो मैं इसको एग्जामिन करवा लूंगा कि क्या फाइनैंशियल इम्पलीकेशन्ज होंगे । मैं समझता हूं कि बूरा साहब की यह सजैशन बहुत बढ़िया सजैशन है और गवर्नमैंट पूरी तरह से इसको एग्जामिन करेगी ।

चौधरी भजन लाल : अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि देहात में इसलिए कालेज नहीं खोलते कि वहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम है और इसलिए देहात में कालेज नहीं चलते । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी जगह देहात में कालेज. खोले गए और विद्यार्थी न होने की वजह से उन कालेजिज को बन्द करना पड़ा?

कर्नल राव राम सिंह : सरकार ने देहात में कालेज खोले या नहीं खोले उसके बारे में अलग से सवाल पूछेंगे तो जवाब डिटेल में दिया जाएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया की एडशिन्ज कम होती हैं यह ठीक बात है । हरियाणा में तकरीबन 100 प्राइवेट कालेजिज हैं, और इनमें से कुछ कालेज देहात में हैं

। इन देहात के कुछ कालेजों में तो एडमिशन बहुत अच्छी हैं, लेकिन कइयों में एडमिशन 100 या 150 ही है । एडमिशन के बारे में हमने वर्कआउट करवाया है और पता लगा कि सात सौ या आठसौ अगर एडमिशन हों, तो कालेज फाइनैंशियल लिहाज से वाएबल हो जाता है ।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया है । मैंने पूछा थाकि देहात में सरकार नेकहां–कहां कालेज खोले और एडमिशन नहोने के कारण बन्द करने पड़े?

कर्नल राव रामसिंह : मैंने पहले ही बता दिया हैकि अगर इस बारे में अलग से नोटिस दिया जाएगा, तो जवाब दे दूंगा ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जिन शहरों में गवर्नमैंट कालेज भी हैं और प्राइवेट कालेज भी हैं, वहां यह देखने में आया है कि गवर्नमैंट कालेज के अन्दर स्टूडैटस ओवर–क्राउडिड हैं और प्राइवेट कालेज में लड़के कम है । क्या शिक्षा मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जो गवर्नमैंट कालेज ओवर क्राउडिड हैंऔर जहां अस्सी के सैक्शन में सौ और 120 स्टूडैट्स हैं वहां पर एडमिशन स्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि प्राइवेट कालेज अच्छी प्रकार चल सके?

कर्नल राव राम सिंह : मेरे लायक दोस्त की सजैशन बहुत अच्छी है । पिछली सरकार ने इसको कसीडर किया था और

कुछ आर्डर भी पास किए थे, लेकिन पिछली सरकार. ने उसको इस्थलीमैंट नही किया था । पिछली सरकार आर्डर तो बहूत करती थी, लेकिन इमपलीमैंट नहीं करती थी, लेकिन जनता सरकार इस मामले को फिर कंसीडर कर रही है और जो आर्डर होंगे, वह जरूर इम्प्लीमैंट होंगे ।

श्री बलदेव तायल : स्पीकर साहब, प्राइवेट कालेजों के मैनेजमैंट को टेक–ओवर कूरने के लिए एक पैनल बनाया गया था । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी हैया नहीं? अगर आ चुकी है, तो क्या मन्त्री महोदय उस पर असल करने की चेष्टा करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, प्राइवेट कालेजों को टेंक–ओवर करने के लिए कोई पैनल नहीं बनाया गया था । एक इनकवायरी कमेटी बनाई गई थी । उस कमेटी ने हरियाणा के सौ कालेजों का विजिट किया और एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई हे और उस रिपोर्ट को गवर्नमैंट कंसीडर कर रही है ।

श्री बलदेव तायल : स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह था कि जो रिपोर्ट सरकार को मिंत्री है क्या उस रिपोर्ट पर सरकार अमल करने की चेष्टा करेगी या नही?

Col. Rao Ram Singh : That report is under considration and to whatever decision the Government comes to after considering the report उसके पर पुरी कार्यवाही की जाएगी ।

(इस समय कामरेड शंकर लाल प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । आपका नाम लिया जाएगा, तब आप सवाल पूछ सकते हैं ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : स्पीकर साहब, होम साईंस कालेज आदि में जो दाखिले होते हैं, इन दाखिलों में भी काफी कुरप्शन होता है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसी बाडी बनाएगी जो दाखिला करे ताकि पैसा लेने का सिस्टम खत्म हो जाए? ऐसी बाडी बनाने का सरकार का कोई विचार है?

कर्नल राव राम सिंह : राठी साहब की यह बहुत अच्छी और बेहतरीन सजैशन है । इसके बारे में सरकार कार्यवाही कर चुकी है और अब जो बी.एड. के दाखिले होंगे, वह प्राइवेट मेनेजमैंट नहीं करेगी । गवर्नमैंट ने चार सैन्टर खोले हैं, और गवर्नमैंट एडमिशन करेगी औंर यह एनश्योर सइम। जाएगा, —कि सौ परसैन्ट कोई किसी किस्म का डोनेशन नहीं लिया जाएगा ।

कामरेड शंकर लाल : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्राईवेट कालेजों में जो प्रोफैर्सज हैं उनके ग्रेड और दूसरी सहूलियते गवर्नमैंट कालेजों के प्रोफसरों के बराबर करने का सरकार का कोई विचार है ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, यूजीसी. के ग्रेड सब कालेजों में लागू है । चाहे वे प्राइवेट हैं, चाहे गवर्नमैंट हैं ।

श्रीमती शकुन्तला भगबाड़िया : क्या मन्त्री महोदय बताने की' कृपा करेंगे कि जिस प्राइवेट कालेज को सरकार अपने नियन्त्रण में न ले सकती हो, लेकिन वहां का मैनेजमैंट उसको देता चाहता है, सरकार उस कालेज को डिप्टी कमिश्नर या किसी और अथॉरिटी के अन्डर देना चाहेगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, डिप्टी कमिश्नर या किसी और आफिसर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने से कोई फाइनैशियल स्थिति में तो फर्क पडने की सम्भावना नही है, लेकिन सरकार इस दफा एक बिल पेश कर रही है, वह आपके सामने आएगा, जो गवर्नमैंट के विचार हैं वह आपके सामने आ जाएंगे । आप उस समय बोल लेना ।

श्री टेक राम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बी.एड. कालेज भिवानी के बारे में कोई कम्पलेंट आपके पास पहुंची है और अगर पहुंची है, तो क्या ऐक्शन लिया गया है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, यह सप्लीमैंट्री इस सावल से सम्बन्धित नहीं है । गवर्नमैंट को बी.एड. कालेज भिवानी के खिलाफ कोई कम्पलेंट नही आई । बी.एड. कालेज में, मैं खुद गया था, मैने वहां विजिट किया था । उनकी सिर्फ यह शिकायत थी कि हमारे पास बिल्डिग नहीं है और न ही ठहरने की

कोई जगह है । इस वक्त वे आई.टी.आई. की बिल्डिग में एकोमोडेट कर रहे है । इसके अलावा कोई शिकायत नही आई है ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि बी.एड. की क्लासिज गवर्नमैंट कालेजों में चलाई जाएगी । क्या मन्त्री. महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो दूसरे ट्रेडज हैं, जैसे ओ.टी है, जे.बी. टी. है, इनके एडमिशन्ज भी क्या सरकार अपने हाथ में लेगी? कर्नल राव राम ??? स्पीकर साहब, एक करैक्शन मैं कर दूं कि गवर्नमैंट बी.एड. क्लासिज सिर्फ गवर्नमैंट कालेजिज में चलाएगी, यह स्टेटमैंट मैंने नहीं दी । माननीय सदस्य की यह बहुत अच्छी सजैशन है कि जैसे बी.एड. का एडमिशन सैन्टूली किया जाएगा, उसी तरह आगे से दूसरी टेरड जैसे ओटी या अन्य जो ट्रेनिंग के कालेजिज हैं, वहां पर सैन्ट्रली एडमिशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी किस्म का जो डोनेशन हे, वह खत्म हो जाए ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या वजीर साहब बताने का कष्ट करेंगे कि हमारी सरकार की आयुर्वेदिक कालेजों के बारे में जो पालिसी है, उन कालेजों की तादाद आगे से और बढ़ाई जाएगी या उनको बन्द कर दिया जाएगा, या सरकार उन कालेजों को अपने अन्डर ले लेगी? ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है? इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कालेज,

कुरुक्षेत्र के बारे में सरकार का क्या विचार है, उसको वही रखकर उसमें कुछ बढौत्तरी की जाएगी या नहीं?

कर्नल राव राम सिंह : माननीय सदस्य ने यह जो सवाल पूछा हैयह स्वास्थ्य मन्त्रालय से सम्बन्धित है, मैं अपनी कुलीग स्वास्थ्य मन्त्री, श्रीमती कमला वर्मा से विचार विमर्श करके उसका सारा जायजा आपके सामने रख दूंगा ।

श्री मूल चन्द जैन : मन्त्री महोदय ने सदस्यगणों के जवाब में कहा है कि ये सुझाव बहुत अच्छे हैं । क्या वे बताने का कष्ट करेंगे कि मैंबर साहिबान के अच्छे सुझावों पर सरकार की तरफ से कब तक अमल हो जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : बहुत जल्द, लेकिन मैं जैन साहब को आश्वासन दिलाना चाहता हूंकि जिस–जिस सुझाव पर मैंने कहा है कि ये सुझाव बहुत अच्छे हैं, उनके पर तकरीबन तकरीबन ऐक्शन हो चुका है । इसलिए मैंने उन सुझावों के बारे में कहा था कि सुझाव बहुत अच्छे हैं ।

Number of Teachers who improved their qualifications

29. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the district-wise number of teachers who have improved their qualifications during their teaching period in the primary schools of Haryana;

(b) the number of teachers who have been given work and pay scales according to improved qualifications together-with the time by which the remaining teachers are likely to be entrusted work according to their qualifications; and

(c) the number of teachers to whom seniority has been given according to their improved qualifications and length of service together-with the time by which the seniority is likely to be given to the remaining teachers ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Statement is laid on the table of the house.

(b) 904, Remaining teachers will be adjusted as and when the required number of posts of masters/mistresses are available.

(c) This matter is under consideration of the Government but no time limit can be given.

Statement

Sr. No.	Name of the district.	No. of teachers who improved qualification during teaching period in primary schools.
1	Ambala	307
2	Bhiwani	103
3	Gurgaon	322

4	Hissar	114
5	Jind	105
6	Karnal	210
7	Kurukshetra	65
8	Mohindergarh	151
9	Rohtak	167
10.	Sirsa	60
11.	Sonepat	49
	Total	1653

स्वामी आदित्यवेश : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने 1972 से 1975 तक के अदेशानुसार एक सरकुलर जारी किया था कि जो अध्यापक, सरकारी या प्राइवेट अपनी योग्यता को इम्प्रूव कर लेगा, उसको दूसरे अध्यापकों की तरह बैटर भत्ता दिया जाएगा । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे किं ऐसा जो रूल सरकार ने बनाया है, वह जेबी. टी. टीचर्ज पर क्यों नहीं लागू हो रहा हे?

कर्नल राव राम सिंह : यह जो एडजस्टमैंट है यह जेबीटी. टीचर्ज के बारे में हो रही है । जिन जे बीटी. टीचर्ज ने अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाई है, उनकी संख्या 1, 653 है, उनमें से 904 टोचर्क एडजस्ट कर दिए गए हैं और जो बाकी रह गए हैं, जैसे–जैसे वेकैन्सीज निकलती जाएंगी, उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी । इस वक्त स्थिति यह है कि जो सोशल

स्टडी मास्टर्ज, मिस्टैरसिज की वकैन्सीज निकलती हैं, उनकी 75 परसैन्ट डायरैक्ट रिक्रूटमैंट एस.एस. बोर्ड से की जाती है और शेष 25 परसैन्ट जो जे.बी.टी. टीचर्ज हैं, जिन्होंने क्वालिफिकेशन बढ़ाई हैं, उनको एडस्ट किया जाता है ।

स्वामी आदित्यवेश : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने 1972 से 1975 तक एक आदेश जारी किया था । regarding grant of personal pay to Government servants who improve their qualifications by further studying यह जो सरकार का आदेश है यह और लोगों पर लागू तो हो रहा है लेकिन जेबीटी. टीचर्ज पर क्यों नहीं लागू हो रहा, इसके क्या कारण हैं?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने जो सरकुलर यहां पर कोट किया है, मेरे ख्याल में इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है, इन्होंने जो पूछा था उसका जवाब मैंने देदिया है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं कि अगर कोई जेबीटी. टीचर या कोई और विभागीय मुलाजम पीएचडी कर ले तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरी क्लास को पढावे और उसे कालेज लैक्चरार का ग्रेड दे दिया जाये । जो क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करता है, उसको दूसरी पोस्ट पर जाने के लिए रास्ता खुला है, कि वह उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है । अगर वह सिलैक्ट हो जाता है तो उसको उस पोस्ट पर लगा दिया जाता है ।

चौधरी राम किशन : हरियाणा प्रान्त में बहुत से जेबीटी. टीचर्ज और बीए. बी.एड. टीचर्ज ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी

है और उनको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी न मिलने के कारण उनकी ऐज भी बढ़ रही है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ऐसे लोगों को शीघ्र ही कोई नौकरी दिलाने का प्रबन्ध किया जाएगा और साथ ही उन्हें ऐज में रिलैक्सेशन दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : यह एक अलग सवाल है ।

चौधरी संत कंवर : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो स्टाइपैडरी टीचर्ज काम कर रहे हैं, क्या सरकार उनको परमानैन्ट करेगी या उनको दुबारा. बोर्ड में अप्लाई करना पड़ेगा ।

कर्नल राव राम सिंह : यह मामला सरकार के विचाराधीन है, पर मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं कि उनका जो इंटैरस्ट है, उसको सरकार पूरी तरह से वाच करेगी ।

चौधरी भजन लाल : क्या मत्री महोदय बताएंगे कि स्टेट की रिक्वायरमैंट के अनुसार सब स्कूलों में टीचर्ज पूरे हैं, अगर नहीं हैं, तो कब तक यह रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएगी?

(कोई उत्तर नही दिया गया ।)

चौधरी देस राज : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा में प्राइमरी टीचर्ज की कितनी कमी है और वह कमी कब तक पूरी कर दी जाएगी?

(कोई उत्तर नही दिया गया ।)

श्री मूल चन्द मंगला : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जब हरियाणा में काफी टीचर्ज ऐक्सट्रा हैं, तब भी ये ट्रेनिंग सैन्टर क्यों खोले जाते हैं, जिनके खोलने का कोई फायदा नहीं है? जो टीचर्ज पहले ही सरपलस हैं, उनको कब तक एडजस्ट कर दिया जाएगा ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी संत कवर : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में बहुत से स्कूलों में टीचर्ज की जगह खाली है और हैडमास्टर्ज ऐम्प्लायमैंट एक्सचेंजिज के द्वारा टीचर्ज की भरती करते हैं । ऐसे स्कूलों में लोग दो–दो तीन–तीन सात्रों से ऐड–हॉक बेसिज पर टीचर्ज काम कर रहे हैं । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ऐसे लोगों को जो ऐड–हॉक पर बेसिज काम कर रहे हैं, सरकार उन को परमानैन्ट करने का विचार रखती है और जोवेकैन्सीज खाली पड़ी हुई हैं, उनको सरकार कब तक फिलअप करने का विचार रखती है?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने पिछले सात साल से रैगुलर रिक्रूटमैंट बन्द कर रखी है । क्यों बन्द कर रखी है, इसका कारण तो वो ही जानते हैं, लेकिन इस दफा हमने रैगुलर रिक्रूटमैंट शुरु कर दी है । रैगुलर रिक्रूटमैंट में एस.एस.एस. बोर्ड के सामने रिक्वीजीशन भेजनी पड़ती है । वह

फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं इसलिए इस तरह टीचर्ज की अप्वायटमैंट में देरी हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान होता है । इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब हैडमास्टरर्ज को पावर्ज दी गई है कि वह सिक्स मन्थ बेसिज पर इमीजिएटली वेकैन्सीज फिल–अप करने के लिए टीचर्ज, मास्टर्ज को एम्प्लाय कर लें । जैसे–जैसे बोर्ड रैगुलर इनकम्बैन्टस के नाम भेजता रहता है, उन 6 महीने वालोंको नोटिस दे दिया जाता है और रैगुलर टीचर्ज को रख लिया जाता है ।

चौधरी हरि चन्द हूडा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सरकार मौजूदा शिक्षा के सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ सोच रही हे?

कर्नल राव राम सिंह : अगर हूडा साहब इसकेलिए कोई सुजैशन देगे तो हम उस पर कर लेगे ।

चौधरी हरि चन्द हूडा : जो ढांचा 30 साल से चल रहा है, वह ठीक नही है इसको बदलने के लिए मैं सजैशन दे दूंगा ।

कर्नल राव राम सिंह : ढांचे की डैफिनेशन भी साथ दे देना ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन लड़के और लड़कियों ने बी.एड. कर रखी है सरकार उनको नौकरी देने का विचार कर रही है?

(कोई उत्तर नही दिया गया ।)

मास्टर शिव प्रशाद : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिन जेबीटी. अध्यापकों ने अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करली है, उनको एडजस्ट करने में प्रायरिटी दी जाएगी?

कर्नल राव राम सिंह : इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो अध्यापक दस–दस साल से काम कर रहे हैं और वे भी अभी तक. पक्के नहीं हुए हैं उनको पक्का किया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : अगर आपका मतलब एड–हॉक और स्टाइपैडरी टीचर्ज से है तो उसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं, उनका मामला विचाराधीन है और उनका इन्ट्रैस्ट हर तरह से प्रोटैक्ट रखा जाएगा ।

चौधरी हर स्वरुप बूरा : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि ज्यों ज्यों पोस्टे आती जाएंगीं, उनको प्रोमोट कर देंगे । क्या मन्त्रीजी बताएंगे कि इसके लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया हे?

कर्नल राव राम सिंह : मैंने पहले बताया है कि प्रोमोशन के लिए 25 प्रतिशत कोटा है और क्राइटेरिया यह है कि डेट आफ पासिंग बी.एड. एग्जाम से उनको सीनियारिटी दी जाती

है । 1971 तक जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव कर ली थी, वे तकरीबन 100 प्रतिशत ऐडजस्ट हो चुके हैं और जिन्होने 72 में इम्प्रूव की थी उनको जैसे–जैसे वेकैन्सी आती जाएंगी, ऐडजस्ट किया जाएगा ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि प्रोमोशन का 25 प्रतिशत कोटा है । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इस तरह से बी.एड. क्लासिज के लिए भी कोटा फिक्स होता है । या वे कम्पीटीशन में सिलैक्ट किए जाते हें?

कर्नल राव राम सिंह : मेरा ख्याल है कि इन्होंने बी.एड. में एडमिशन के लिए सवाल पूछा है । ऐडमिशन के लिए कोई कोटा फिक्स नही होता, यह तो हर एक के लिए ओपन कम्पीटीशन होता है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : मन्त्री महोदय ने क्हा है कि ज्यों–ज्यों हमारे पास जेबीटी. टीचरों की नाग आती जाएंगी, हम एस.एस.एस. बोर्ड को उसके लिए मांग भेजते जाएंगे । लेकिन अगर 50 पोस्टों की मांग आती है तो उसके लिए दस हजार एप्लीकेशन्ज आती हैं, जिस कारण टाइम भी खराब होता है और पैसा भी जाया जाता है । क्या मन्त्री महोदय कोई ऐसा फैसला करेंगे कि सारी मांग इक्ट्ठी. ही भेजी. जाए?

कर्नल राव राम सिंह : वैह जाएका सवाल ऐड–हॉक टीचर्ज को रैगुलर करने का है । मैंने बताया था कि यह मामला

विचाराधीन है । जो मांग हैं वह अलग–अलग नहीं भेजी जाएंगी बल्कि इकट्ठी भेजने का फैसला किया जाएगा ।

चौधरी ईश्वर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बी. एड. टीचर्ज जो सरप्लस है, उनको– साईंस मास्टरों की पोस्टों के अगेनस्ट एडजस्ट किया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : इस वक्त साईंस तथा मैथ मास्टरों की. कमी है और एसएस. मास्टर्ज उनकी जगह काम कर रहे है । यह अरेंजमैन्ट सैटिसफैक्टरी नहीं है, क्योकि एस–एस. मास्टर्ज साईं स और मैथ अच्छी तरह से नही पढ़ा सकते हैं, इसलिए जैसे–जैसे साईंस और मैथ के मास्टर्ज अवेलेबल होंगे । उनकी जगह उनको दी जाएगी और टैम्पोरेरी अरेंजमैंट खत्म कर दिया जाएगा ।

Water from Ravi-Beas Project

***251. Chaudhri Sant Kanwar :** Will the Minister for Irrigation and Power be plesed to state—

(a) the time by which the water from the Ravi-Beas Project is likely to be given to the state of Haryana ; and

(b) the steps being taken by the Government to construct the carrier channel in the territory of Punjab for getting Ravi-Beas water ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) रावी व्यास के फालतू पानी में हरियाणा के भाग का एक अंश पहले ही हरियाणा में लाया जा रहा है । पूरा भाग सतलुज यमुना लिंक के पूर्ण हो जाने पर ही लाया जा सकता हैं । लिंक के पूर्ण होने की तिथि इस समय बताई नहीं जा सकती ।

(बी) रावी–यास के फालतू पानी में हरियाणा के भाग को लाने के लिए पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक पर कार्य शुरू करने और उसे शीघ्र पूरा करने के लिये मामला पंजाब सरकार के साथ चलाया जा रहा है ।

चौधरी संत कंवर : मन्त्री जी ने अभी बताया कि रावी व्यास के पानी का कुछ अंश हरियाणा में लाया जा रहा है । क् इनसे पूछना चाहता हूं पिछले साल में कितना पानी लिया गया और उसका जिलावार बंटवारा किस प्रकार है?

श्री बीरेन्द्र सिंह : पिछले साल 0. 6 एमएएफ. पानी आया था ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि पंजाब के साथ बातचीत चल रही है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो चौनल पंजाब में बनना है अब तक उस पर काम शुरु हो चुका है या नहीं या वह किस स्टेज पर है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : पांच किलोमीटर की लाईन के लिए नोटिफिकेशन हो चुका है और नोटिफिकेशन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद, लैण्ड एक्वीजीशन के बाद मार्च में या अप्रैल में

पंजाब के मुख्य मन्त्री, सरदार प्रकाश सिंह बादल, उसका उद्घाटन करेंगे और चौधरी देवी लाल जी उसे प्रिजाइड ओवर करेंगे । – (तालियां)

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि पंजाब में जो कैरियर चौनल बनेगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी और जो हरियाणा में आप कम्पलीट कर रहे हैं उसकी क्या होगी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : दोनों की कैपेसिटी 75 00। 7500 एमएएफ. की है ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने कहा कि पिछले साल 0. 6 एमएएफ. पानी आया । पानी तो 1 50 एमएएफ. आ सकता था, यह क्यों नहीं लिया? गया?

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले भी बता चुका हूं कि इतना नहीं आ सकता था ।

चौधरी भजन लाल : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो चौनल पंजाब में बनेगी उसमें इंजीनियर हमारे होंगे, या पंजाब के?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जिस एरिया में काम शुरु होता है, वहां पर उन्हीं के इंजीनियर्ज काम करते हैं ।

चौधरी गुलजार सिंह : स्पीकर साहब, पंजाब में जो नहर बनने जा रही है उसके बारे में यह अफवाह है कि पंजाब

वाले ढीला काम कर रहे हैं । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच हे?

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मन्त्री महोंदय बताएगे कि जो बैपल बनाई जा रही है उसका रास्ता लम्बा पडता है तथा मंहगा भी पडता है । का दूसरा रास्ता कम नहीं पड़ता था?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो रास्ता हमने प्रोपोज किया है, वह ज्यादा सूटेबल है और वह छोटा पड़ता है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : मन्त्री महोदय को पता होगा कि आनन्दपुर हाइडल प्रोजैक्ट पर इस सारे पानी का इस्तेमाल किया जाएगा । उसमें से जो पावर मिलेगी, क्या उसमें से हरियाणा को भी कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं?

श्री बीरेन्द्र सिंह : यह प्रश्न मेन प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

Drains in the Kaithal Sub-Division

***261. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to dig out drains in Kaithal Sub-Division of Kurukshetra District to save the villages from the recent flood waters ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar

Singh) : Yes.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि कैथल सब– डिवीजन में आपने कौन–कौन सीड्रेनज मन्जूर की हैं और क्या अगली बारिश से पहले–पहले उस इलाके को बचाने की कोशिश की जाएगी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : जो ड्रेनज कैथल सब–डिवीजन के लिए हमने रखी हैं, वे इस प्रकार हैं :–

सेगा ड्रेन, जियोंग ड्रेन, थाना लिंक ड़ेन, खुराना लिंक ड्रेन, मेधा माजरी लिंक ड्रेन, बाबा लडाना लिंक ड्रेन, कसन लिंक ड्रेन, हाबरी लिंक ड़ेन, चन्दानी लिंक ड्रेन, हाबडी लिंक ड्रेन, मुन्हेडी लिंक ड़ेन तथा मानस लिंक ड्रेन ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस इलाके को बचाने के लिए अगली बरसात के आने से पहले कोई स्कीम मन्जूर की है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जिन ड्रेनों के बरसात के पहले पूरा होने की सम्भावना है, उनके नाम इस प्रकार हैं

Sanga Drain :	Land has already been acquired. Work of excavation is in progress. Likely to be completed before 33E11 June, 1978
Geong Drain :	Land already acquired. Excavation

	in progress. Work likely to be completed by June, 1978.
Pundri Drain :	Work on Pundri drain No. 1, reach RD 0-35 already completed. Reach RD 35-55 in progress and likely to be completed during this year i.e. by June, 1978.
	Land of Pundri Drain No. 2 has already been notified. Work will be taken in hand after the possession of land has been given by L.A.O.
Thana Link Drain	
Khurana Link Drain	Investigation work is in progress.
Magho Majri Link Drain	
Baba Ladhana Link Drain	
Kasan Link Drain	
Habri Drain	
Chandani Link Drain	
Habri Link Drain	Scheme is under approval.
Muner Heri Link Drain	
Mans Link Drain	Land plans prepared. Work will be taken in hand after the possession of

the land is given by L.A.O.

चौधरी ईश्वर सिंह : स्पीकर साहब, कैथल सब–डिवीजन के अन्दर गुहला को छोड़ दिया गया है । वहां पर पसल कसली लिंक ड्रेनज पहले से ही अधूरी पड़ी हुई है । – (व्यव– धान)– कहने के बावजूद भी वे नहीं बनाई गई । इनको पूरा नहीं किया गया । क्या मन्त्री महोदय इनको पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे?

श्री बीरेन्द्र सिंह : जो ड्रेन्ज हममें मन्जूर की हैं या जिन को बहुत जल्दी हमतैयार करने जा रहे हैं उन के द्वारा, हुमारे डिपार्टमैंट के ख्याल के मुताबिक सारे पानी को बाहर निकाल देंने ।

चौधरी राम किशन : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिला जीद में सफीदों के लिए जो ड्रेन मन्जूर हुई है उसकी क्या पोजीशन है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह सवाल अलग है, मैंबर साहब को शाम को बता दूंगा ।

श्री रघुनाथ गोयल : स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र जिले में काफी स्थानों पर बाढ़ आई है और जो मानसा गांव है उसका पानी अभी तक नहीं निकला है । खेतिया दबी पड़ी हैं, पैसा दे चुके हैं, सरकार इस ड्रेन को क्यों नहीं खोदती जबकि दूसरी तरफ नई ड्रेनज तैयार करनी शुरु कर दी है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, गांवों को बाढ़ के पानी से बेचाने के लिए ड्रेन्ज बन रही हैं । क्या मन्त्री महोदय मेरे हलके में भी ड़ेन बनाएंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी उदय सिंह दलाल : मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो ड्रेनज फ्लड की वजह से खुदी हुई हैं, उसके आसपास किसानों ने खाद डाल रखी है, गेहूं बो रखे हैं और अब वे काटने लगे हैं लेकिन उस मिट्टी को जो ड्रेन खोदने से पैदा होगी और किसान की फसल खराब होगी उसका मुआवजा किसान को देने के लिए मौके पर पेमैंट करने के लिए अफसरान को हिदायत देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : खुदाई शुरु करने के 15 दिन के अन्दर अन्दर पेमैंट करने की हिदायत दी जाएगी ।

राव राम नारायण : स्पीकर साहब, झज्जर तहसील में मीलों पानी भरा पड़ा है । क्या उस पानी को डी–वाटर करने की स्कीम है?

श्री बीरेन्द्र सिंह : मीलों पानी तो कही नहीं है, मैं उस इलाके में घूम कर आया हूं, कई जगहों पर जरूर पानी है । जो बहुत नीचे के एरिए हैं, वहां के पानी को निकालने का कोई चारा

नहीं नजर आता है । लेकिन कुछ स्कीमें गवर्नमैंट के अन्डर कन्सीडेरशन हैं । इन जगहों में रिजर्वायर तैयार करवाने की स्कीमें हैं परन्तु जब यहां के लोगों से पूछा गया तो वे कहते हैं कि हमारी जमीन बेशक सालों साल पानी से भरी रहे लेकिन हमारी जमीन एक्वायर नु की जाए । फिर भी सरकार सोचेगी कि किस तरह से बन्दोस्वत किया जाये ।

श्री भले राम : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हमारे पास ड्रेनज खुदवाने के लिए कितने ड्रेजर हैं और क्या सरकार और मंगवाने का इन्तजाम कर रही है?

(कोई उत्तर नही 'दिया गया ।)

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, कोटला झील में मीलों पानी भरा हुआ है । क्या मन्त्री महोदय इस पानी को डी–वाटर करने के लिए ज्यादा पावर देने का इन्तजाम कर पायेगी?

(कोई उत्तर नही दिया गया ।)

चौधरी हरस्वरुप बूरा : कुछ जगहों पर एइसे पोक्टेस हैं, जहां पानी निकालने के साधन नहीं हैं । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि वहां ड्रेनज खोदी नही जा सकती वहा से पानी निकालने का क्या इन्तजाम किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिह : फिलहाल यही हल सोचा है कि सरकार वहां रिजर्वायर बनवा देगी ।

School Buildings for Repairs

***272. Chaudhri Har Swarup Buru :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Primary, Middle and High Schools buildings to be taken over by the P.W.D. (B&R) for repair in Sub-Tehsil Meham and the time by which the alp: we said buildings are likely to be taken over by the said Department and the total number of schools repaired so far ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Total number of school buildings to be taken over by P.W.D. (B&R) = 36

(i) Primary School — 27

(ii) Middle Schools — 4

(iii) High Schools — 5

(b) It is not possible to indicate any time limit by which these will be taken over by the Public Works Department.

(c) Total number of schools repaired so far. — 14

(i) Primary School — 1

(ii) Middle Schools — 3

(iii) High Schools — 10

चौधरी हरस्वरुप बूरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सब–तहसील ड्रेंमहम में कितने स्कूल बाकी बचे हैं, जो पीडनन्यूडी. ने टेक–ओवर नही किए हैं?

कर्नल राव रामसिंह महम : सब–तहसील बड़ी खुशकिस्मत तहसील है, इसमें टोटल 50 स्कूल हैं, जिनमें से 14 स्कूल पी.डब्ल्यू डी. ने टेक–ओवर कर लिए है और अब सिर्फ 36 स्कूल टेक–ओवर करने के लिए बाकी हैं ।

Percentage for the Persons Belonging to Backward Class in the Recruitment of Services.

***240. Chaudhri Ram Kishan :** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the quota of percentage for the persons belonging to Backward classes in the recruitment of services in the State; if so, the time by which it is likely to be finalised ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh) :

At present there is no proposal under consideration of the Government to increase the quota of percentage for the persons belonging to Backward Classes in the recruitment of services in the State.

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बैकवर्ड क्लासिज के लिए जिस वक्त 2 परसैन्ट रिजर्वेशन फिक्स की थी उस वक्त क्या पापुलेशन थी और अब क्या है?

Shri Preet Singh : It is a separate question. Therefore, notice is rcquired.

श्री जयनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पल में यह वायदा किया था कि समाज के इस 1? 3 पिछड़े हुए भाग के लिए, जब जनता पार्टी का शासन आएगा, तो 30 परसैन्ट रिजर्वेशन करेगी । क्या समाज कल्याण मच्छी महोदय बताएंगे कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जाते जाते 2 परसैन्ट से बढ़ाकर 10 परसैन्ट की जो रिजर्वेशन की थी, उसको भी खत्म कर दिया गया है? क्या यह बात सही है?

श्री प्रीत सिंह : जहां तक मैनिफैस्टो का सवाल है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब गवर्नमैंट इस विषय पर विचार कर सकेगी, तो देख लेंगे ।

Drinking Water Facility

***286. Chaudhari Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of villages in which drinking water facility has been provided so far in the State;

(b) the number of villages in which the aforesaid facility is likely to be provided during the current financial year; and

(c) the time by which the scheme for providing driking water in villages in Nilokheri area is likely to be completed and start functioning ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) 984

(b) 125

(c) No date can be indicated as it depends on the availability of funds.

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में अभी बताया कि अभी तक जिन गांव में ड्रिकिंग वाटर फैसिलिटीज दी गई हें उनकी संख्या 984 है और जिन गांव को इस साल देनी हैं उनकी संख्या 125 है । क्या वे बताएंगे कि किस किस जिले में कितने कितने गांव को यह फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अलग अलग जिले की कई कई स्कीमें हैं जिनके नाम में अर्ज कर देता हूं ।

क्रमांक	जिला	स्कीमों के नाम
1.	अम्बाला	रेतवाली
		टिकरी
		नाडा साहिब
		नाला बराग रामगढ़

2. भिवानी रोहनाथ

अलखपुर

3. गुड़गांव सीकरीं

कनसाली

मंडोला

चौसा

मलाब

मोहना

अध्यक्ष महोदय, खुरशीद जी ने नाम भी गांव के ऐसे रखे हैं जिनका पढ़ना ही मुश्किल है । (विघन)

श्री अध्यक्ष : नम्बर ही बता दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : टोटल नम्बर तो 125 गांव हैं ।

एक सदस्य : 82 तक तो कम्प्लीट कर दीजिए । (विघन)

चौधरी शिव राम वर्मा : किस जिले में कितने–कितने गांव लिए गए, कृपया यही बता दें? – (विघ्न)

श्री वीरेन्द्रसिंह : मेरे पास तो इस समय स्कीमों के नाम हैं । इसमें अलग–अलग गांव के नाम नही लिखे हुए हैं । – (विध्न) –

चौधरी शिव राम वर्मा : इस साल जो 125 गांव पूरे करने हैं, उनके ही नाम बता दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : उनके नाम बताने में काफी समय लगेगा क्योंकि अभी बहुत सवाल बाकी हैं ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, अगर एक एक गांव का नाम बताना मिनिस्टर साहब को मुश्किल है तो वे यही बता दें कि इस फाइनैशियल ईयर में किस जिले में कितना खर्च होगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : किस जिले में कितना खर्च होगा यह वर्क आउट नहीं किया गया है परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब से वाटर सप्लाई स्कीम्ज शुरु हुई हैं, किसी साल में भी हरियाणा में इस साल से पहले 80 गांव से अधिक गांव को पानी नहीं दिया गया । पहली मरतबा जनता पार्टी की सरकार ने 9 महीने के अरसे में 125 गांव को पानी दिया है । – (तालियां) –

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, सरकार ने यह जो रहम की नजर बख्शी है इसके लिए तो सरकार मुबारिकबाद की पाल है लेकिन मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन

गांवों को पानी दिया जा रहा है जिनको पानी की जरूरत है या उन गांव को दिया जा रहा है जिनको पानी की जरूरत नही है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मूल चन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय यह फरमाएंगे कि करनाल जिले में जिन–जिन गांवोंकी वाटर सप्लाई स्कीम्ज मन्जूर हुई हैं उनमें काम शुरु हो गया है खास तौर पर सम्भालखा के करंस, माच्छरोली, नारायणा और पसीना गांव में?

श्री वीरेन्द्र सिंह : करनाल जिले में उकलाना और अमीन गांव छांटे गए हैं और वे शायद सम्भालखा में ही पड़ते हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : ये गांव सम्भालखा में नहीं हैं ।

चौधरी गया लाल : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जिला गुड़गांव के हसनपुर क्षेत्र में जमुना नदी के किनारे–किनारे जहां खारा पानी है कोई स्कीम इस साल शुरु की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्केयरसिटी विलेजिज में जैसा मैंने परसों अर्ज किया था, सरकार एक–एक गांव में पानी देना चाहती है लेकिन फंडज की कमी की वजह से इस किस्म के सारे के सारे 4081 से पर गांव में एकदम पानी नहीं दिया जा सकता । अध्यक्ष महोदय, इनके गांव में तो शायद, वह हसनपुर गांव ही था, दो महीने पहले मैं वाटर सप्लाई स्कीम का उद्– . घाटन करके आया था । अध्यक्ष महोदय, कोशिश यह है कि पैसा अधिक से

अधिक वहां खर्च हो जहां कंटीन्यूईग स्कीम है, जो 2 0–2 0 साल से पड़ी हुई हें और सरकार का पैसा जाया हो रहा है । उनको प्रायरिटी देकर हम पहले पूरा करना चाहेंगे । जो स्केयरसिटी विलेजिज हैं उनकी प्रायरिटी मैंबर साहबान से पूछकर फिक्स की जाएगी । हम सारे पैसे को बराबर बांट कर देना चाहते हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह पिक एंड चूज वाला काम कब तक चलेगा? क्यों नहीं ये टैक्नीकल ऐक्सपर्टस की एडवाइस के अनुसार, एरियावाइज प्रायरिटी फिख्स करते? मैं तो स्पीकर साहब बेरी के इलाके की बात जानना हूं । प्रोफैसर शेर सिंह जी वहां से आए, पंडित भगवत दयाल जी वहां से आए और आप वहां से आए हैं लेकिन इतना होते हुए भी वहां पानी पीने को नही मिलता ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब जितना पैसा होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा लेकिन एमएलए. साहेबान चाहते हैं कि उनके इलाके में एक–एक काम अवश्य किया जाए ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह जो वाटर सप्लाई स्कीम चालू की जा रही है इसके कुनैक्शन गांव में प्राइवेट तौर पर दिए जाएंगे या सामूहिक रुप से दिए जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : प्राइवेट कुनैक्शन देने की अभी पालिसी नहीं है । इसमें कुछ रि– लैक्सेशन की गई थी जिसके तहत गांव में एक–एक दो–दो आदमियों को कुनैक्शन्ज दिए गए

थे लेकिन अगर गांव वाले इस बात को प्वांयट आउट करेंगे कि वे इस बात को नहीं चाहते तो वे काट दिए जाएंगे ।

श्री हीरा नन्द आर्य अध्यक्ष महोदय अभी मन्त्री जी ने बताया कि पैसा बांट कर दिया जाएगा । क्या वे बताएंगे किवे सड़कों की तरह ही इस पैसे को बांटेंगे या किसी और तरह से बांटेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में चौधरी हीरा नन्द आर्य जी की आंखों पर कोई हरा चश्मा चढ़ गया है । सड़कों पर कल डिस्कशन है, उस समय इस बारे में इनकी पूरी तसल्ली करा दी जाएगी । – (विध्न)–

राव राम नारायण : स्पीकर साहब, साल्हावास का हल्का पूरे का पूरा ब्रैकिश वाटर का है । इसीलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां केलिए भी इन्होंने कोई स्कीम अन्डर–टेक की है? अगर नहीं की है, तो क्यों नही की हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, कांस्टीच्शुएंसी वाइज डिटेल्ज यहां नही दी जा सकती, परन्तु जहां तक साल्हावास का ताल्लुक है मेरे ख्याल में यह ब्लॉक वर्ल्ड बैक की स्कीम में शामिल है और इस बारे में मैंने राव साहब को चिट्ठी भी लिखी हुई है । नार्मल स्कीम्ज में से भी इनको पैसा देंगे ।

चौधरी हरस्वरुप बूरा : क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेगे कि मदनहेडी स्कीम जो पन्द्रह साल से इनकम्पलीट पड़ी हुई

है जो चौधरी देवी लाल जी की वजह से बन्द हो गई थी., जिसके लोगों ने कुछ पैसे, जितने सरकार ने मांगे थे, भरे हुए हैं, कब तक कम्प्लीट कर दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो जिला बैकवर्ड करार नहीं दिया गया है उसमें पालिसी यह है कि टोटल स्कीम का बारह परसैन्ट रुपया गांव के लोगों को पंचायत को भरना पड़ता है । अगर मदनहेडी के लोग 12 परमैन्ट रुपया दाखिल करेंगे तो वह स्कीम जरूर शुरु की जाएगी ।

चौधरी राम किशन : अध्यक्ष महोदय, जिला जीद के अन्दर उचाना, जुलाना और रजौद ब्लॉक में कडुवा पानी है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कलायत व्लॉक के, जहां मीठा पानी है, क्यों छाटा गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह तो साहब पहले ही छांटा हुआ था, मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि देहात को पानी देने का यह जो सिस्टम सरकार ने शुरु किया है, इसमें बादली के लोगों को भी शामिल करेंगे क्योंकि पिछले तीस साल से उस इलाके को एक भी स्कीम नही मिंत्री है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं इस बारे में पहले ही जवाब दे चुका हूं ।

चौधरी मेहर सिंह राठी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने जो बताया कि इस समय तक 984 गांव को ड्रिकिंग वाटर फैसेलिटी दी गई है, इसमें बहादुरगढ़ शामिल नहीं है । वहां पानी खारी है । इसलिए क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इस साल वहां कोई स्कीम चालू करने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, अगर हम कहीं ज्यादा स्कीमे बनाते हैं, तो बाबू मूल चन्द जैन जी को एतराज होता है । इसलिए अब तो यह सोचा गया है कि बराबर डिस्ट्रिब्यूशन कर दी जाए । –विध्न)

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Sutlej Yamuna Link Canal

***301. Shri Devender Sharma :** Will the Minister fox Irrigation. and Power be pleased to state—

(a) the stage of construction of Sutlej Yamuna Link Canal in Punjab territory;

(b) the steps if any taken to persuade the Punjab Government to complete their portion of Canal within the target period of two years; and

(c) the total expenditure incurred on the construction of Sutlej Yamuna Link Canal in Haryana

Territory upto 31-12-77 excluding payment made on account of acquisition of land togetherwith the period by which the canal is likely to be completed in Haryana territory ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) Construction of Sutlej Yamana Link Canal in Punjab territory has not been started so far. However, land acquisition proceedings have been initiated in Punjab territory.

(b) The Punjab Government is being persuaded to start the work on the portion of Sutlej Yamuna Link lying in Punjab territory and complete it expenditiously. A number of discussions have been held in this connection with the Punjab Government.

(c) The total expenditure incurred on the construction of Sutiej Yamuna Link Canal in Haryana territory upto 31-12-1977 excluding payment made on account of acquisition of land is Rs. 12.02 crores. The work in Haryana territory is likely to be completed by the end of year 1978-79.

Lift Irrigation Scheme

***337. Chaudhri Des Raj :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state that the total amount spent so far for Lift Irrigation Scheme alongwith the canalwise cost of pump in the State ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : 31–12–77 तक छ उठान सिंचाई योजनाओं पर 8344 लाख रुपये खर्व हुए हैं । जिनमें से पम्पों की कीमत 759.92 लाख रुपये है ।

नहरों अनुसार पम्पों की कीमत की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

राज्य में नहरों पर लगे पम्पों के खर्चे की सूचि जो 3 1– 1 2– 77 तक किया गया क्रमांक नहर का नाम खर्चा रुपये लाखों में

1	जुई कैनाल जुई कैनाल	35.87
2	लोहारू कैनाल ।	150.58
3	सिवानी कैनाल	100.00
4	जवाहर लाल नेहरू कैनाल	461.09
5	नगल लिपट सिंचाई योजना	0.03
6	रिवाडी लिपट सिंचाई योजना ।	6.55
	जोड़	759.92

लाख

Samples from the shops at Bus Stands

***349. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) whether samples are taken by Food Inspectors or any other agency from the shops and vends located at the bus stands in Haryana from 1976 to date and if so, the results thereof; and

(b) if not, the reasons thereof ?

स्वास्थय मन्त्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा) : ए) जी हां ।

तथा

बी) 308 सैम्पलज भरे गये और 83 में मिलावट पाई गई । 74 केस दोषियों के विरुद्ध कोर्टस में लंबित हैं ।

Work Charge Employees in the Public Health Department

***383. Shri Ran Singh Maan :** Will the Minister for Irrigation and **Power** be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of work-charge employees at present working in P.W.D (Public Health) Department and;

(b) if so, the steps being contemplated in this regard ?

सिंचाई बिजली एवं मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क तथा ख) हां । लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य शाखा) के ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने का मामला सरकार के विचाराधीन हे जिन्होंने विभाग में पांच वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली है ।

Municipal Committees in the State

***367. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Industries be pleased to state the total number of Municipal Committees in the State at present together with the number of Municipal Committees which stand suspended at present and the time by which the election to those Committees are likely to be held ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) :

29 और यह सभी 29 नगरपालिकायें, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के लागू होने से अर्थात 20 जुलाई 1973 से सुपरसीडिड हैं । हरियाणा नगरपालिका अधि– नियम 1973 की धारा 277(3) में की गई व्यवस्था अनुसार सभी नगरपालिकाओं के निर्वाचन 19 जुलाई, 1978 से पूर्व करवाने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Tubewells in Ambala District

***446. Master Shiv Parshad :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of tubewells installed in the State during the year 1977-78 togetherwith the number of

those out of them installed in Ambala District; and

(b) the number of tubewells proposed to be installed in the State during the year 1978-79 togetherwith the number of those out of them which are proposed to be installed in Ambala District ?

सिचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) कुल नलकूप 197 7– 78 के समय हरियाणा

राज्य में लगाये गये – 47

नलकूपों की संख्या जो अम्बाला जिले में लगाये गये – 12

(वी) कुल नलकूप 1978–7 9 में लगाने का प्रस्ताव है – 400

पर वाले नलकूपों में से जो अम्बाला जिले में लगाने हैं – 95

Prisoners given Remission or Released

***424. Shri Balwant Rai Tayal, M.L . A. :** Will the Minister for Industries to be pleased to state—

(a) the number of prisoners who were given remission or released after the formation of New Government;

(b) the number of prisoners out of those referred to in part (a) above who were convicted for life imprisonment

together with the time for which they have remained in prison ; and

(c) whether any complaint has been received against the said released prisoners who were convicted for life imprisonment ; if so, the nature thereof ,togetherwith the action taken by the Government thereon ?

****Interim Reply**

"SUSHMA SWARAJ

D.O. No. 37/1/78-H

Social Welfare

Jail

Dated the 6th March, 1978.

Subject —Starred Assembly Question No. 424 asked by Shri Balwant Rai Tyal, M.L.A.

Dear

I write to inform you that Starred Assembly Question No. 424 asked by Shri Balwant Rai Tayal, M.L.A. was received in the Secretariat on 28.2.78. I understand this question has been fixed for answer on 7.3.78. As some information asked for from the District Officer has not been received and as such I feel that it will not be possible to answer it on the 7th March, 1978. I shall, therefore, feel greateful if this question is fixed for answer on any date after

13th March, 1978.

Yours sincerely,

Sd/-

(SUSHMA SWARAJ)

Brig. Ran Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Focal Village Schemes

***426. Shri Bhale Ram :** Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state—

(a) the number of villages brought under focal village scheme in the State at present;

(b) the number of villages where the building of Nursery
Schools have been completed and the classes started; and

(c) whether the building of Nursery School has completed in village Butana of Baroda Constituency; if so, the time by which the classes likely to be started ?

विकास तथा पंचायत मंत्री (सरदार तारा सिंह) :

(ए) कुल 9 फोकल ग्राम ।

(बी) 4 फोकल ग्रामों में महिला मण्डल–कम–नरसरी स्कूलों के भवन तैयार हो चुके हैं, तथा इन में नरसरी कलासे' आरम्भ की जा चुकी हैं ।

(सी) फोकल ग्राम बुटाना में महिला मण्डल–कम–नरसरी स्कूल का भवन पूर्ण हो गया है, तथा इस में नरसरी कलास मास अक्तूबर, 1977 से आरम्भ कर दी गई है ।

Registration Fee on Custodian Land

***433. Shri Hira Nand Arya Will** the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the percentage of registration fee on the purchase of custodian land at present togetherwith the time when it has been enforced ;

(b) the rent which was realised on one year lease of barani custodian land together with the extent to which increase has been made in it for the last one or two years and since which date; and

(c) whether it is a fact that no registration fee was charged on the custodian land which was purchased by the Harijans and tenants on fixed price together with the time since when the same has been increased alongwith the extent to which it has been incrcased ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh) ;

(a) (i) No separate rates or percentage of registration fee on the purchase of custodian land have been

prescribed. However a statement (No. I) of the rates at present being charged is laid on the table of the House.

(ii) These rates are being charged with effect from the dates mentioned against each district as per statement (No. II) laid on the table of the House.

(b) Lease of the barani custodian (evacuee) land except for the inferrior land, is given by auction. Unauthorised occupants and authorised occupants (Other than lessees by auction) of the aforesaid land were required to pay 8 times the land revenue and 6 times the land revenue per annum respectively. Since Rabi 1973 the aforesaid rates of 8 times and 6 times have been revised to 20 times the land revenue or Rs. 40/- per crop per acre which ever is higher in case of rural land and 100 times the land revenue or Rs. 400/- per crop per acre whichever is higher in case of urban land.

(c) (i) No. In some districts it was charged from the very beginning and in some districts it was charged from the dates shown in the statement (No. II) laid on the table of the House.

(ii) No increase has been made in the rates.

(iii) Question does not arise.

Statement No. I

(Extract of Appendix I of the table of registration fees of the Haryana Registration Manual 1967)

(Section 78 and 79 of the

Act)

Article I. For the Registration of documents.

(i) In Book I, the register of non-testamentary documents relating to immovable property : -

(a) For ail optionally registerable documents except leases :-

Rs. P.

3.00

(b) For all compulsorily registerable documents (other than leases of immovable property) :—

1.50

If the value of consideration in money does not exceed Rs. 50.

exceed Rs 50 but does not exceed Rs 100 3 00

exceed Rs 100 but does not exceed Rs 200

5.00

exceed Rs 200 but does not exceed Rs 300

7.00

exceed Rs 300 but does not exeeed Rs 400

9.00

exceed Rs 400 but does not exceed Rs 500

11.00

exceed Rs 500 but does not exceed Rs 600
13.00

exceed Rs 600 but does not exceed Rs 700
15.00

exceed Rs 700 but does not exceed Rs 800
17.00

exceed Rs 800 but does not exceed Rs 900
19.00

exceed Rs 900 but does not exceed Its 1000
21.00

exceed Rs 1000 but does not exceed Rs 1500
26.00

exceed Rs 1500 hut does not exceed Its 2000
31.00

exceed Rs 2000 but does not exceed Rs 2500
36.00

exceed Rs 2500 but does not exceed Rs 3000
41.00

exceed Rs 3000 but does not exceed Rs 3500
46.00

exceed Rs 3500 but does not exceed Rs 4000
51.00

exceed Rs 4000 hut does not exceed Rs 4500
56.00

exceed Rs 4500 but does not exceed Rs 5000 61.00

For every 500 or part thereof in excess of Its 5000 5.00

Statement No. II

Details showing the dates from which registration fee was charged on the custodian land which was purchased by the Harijans and tenants on fixed price in the State of Haryana.

District	Dates
Ambala	28.1.1977
Kurukshetra	28.1.1977
Karnal	28.1.1977
Sonepat (Gohana Tehsil)	30.7.1973
(Sonepat Teshil)	October, 1975.
Rohtak	From the very beginning.
Hissar	July, 1973
Bhiwani	From the beginning.
Sirsa	1.9.1974
Gurgaon	28.1.1977

Mohindergarh	28.1.1977
Jind	28.1.1977

Lining work of water Courses

***422. Shri Jagdish Kumar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the reasons for suspending the lining work of water courses in Sirsa District togetherwith the time by which it is likely to be started?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : सिरसा जिला में बालों को पक्का करने का काम निलम्बित नहीं किया गया यद्यपि पर्याप्त धन राशि न होने के कारण इस काम की प्रगति कम हो गई है । अब काम की गति तीव हो जागेगी क्योंकि कुछ धन राशि का मिलना सम्भव हो गया है ।

Development Office

***457. Shrimati Shakuntla Bhagwaria :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the reasons for opening the Job Development Office, Employment Department together with the reasons for which it has been shifted to Chandigarh; and

(b) the benefits reached to the applicants of Haryana from this department and the progress made by shifting this office to Chandigarh ?

वित मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) :

(ए) रोजगार विभाग में जोब डिवैल्पमैंट यूनिट, गैर सरकारी क्षेत्रो में रोजगार सेवा को अधिक उपयोगी बनाने तथा बेरोजगारी की समस्या को प्रभावशाली ढंग से सुलझाने के उदद्एश्य से स्थापित की गई । इस यूनिट की स्थापना फरीदाबाद में सितम्बर, 1974 में की गई और इसका कार्य क्षेत्र गुड़गांव तथा महेन्द्रगढ़ के जिले रखे गये । इन यूनिट के कार्य–क्षे व को विस्तृत करने का निर्णय लिया गया ताकि इन दोनों जिलों की बजाए राज्य के सभी गैर सरकारी नियोजकों तथा आवेदकों को लाभ हो सके । इसके अतिरिक्त 'अपना रोजगार' को बढ़ावा देने का कार्यक्रम भी इस यूनिट को सौंपा जाना था जिसे फरीदाबाद से प्रभावशाली ढंग से निर्देशित तथा कार्यान्वित करना सम्भव नहीं था अत जुलाई, 1975 में इस यूनिट को चण्डीगढ में तबदील किया गया ।

(बी) गैर सरकारी संस्थापनाओं में अधिक संख्या में प्रार्थिर्यो को नौकरियां मिंत्री और 'अपना रोजगार' को बढ़ावा देने के काक्रर्यम की उपलब्धी अच्छी रही । जैसा कि नि– आंकड़ों से स्पष्ट है –

	1974	1975	1978	1977
गैर सरकारी क्षेत्र में भरी गई रिक्तियों की संख्या	637	1484	5006	4289

अपना काम धन्धा शुरू करने वाले

लोगोंकी संख्या — 674 5847 1762

Loss Occurred due to Floods

***453. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the estimated loss occurred due to floods in the state during the year 1977-78;

(b) the details of the facilities provided to the flood affected villages by the Government so far; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government for giving the prize to a Gram Panchayat of a

village who completes construction work on Dam by Sharm Dan to prevent the loss occurring due to the floods before the rainy season sets in; if so, the nature thereof ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh) :

(a) A statement is enclosed.

(b) Government provided immediate relief to the flood stricken villages in the shape of free rations and boats for maintaining communications. Large-scale anti malaria and anti cholera measures were taken. Similarly to protect the cattle, protective measures were taken against cattle diseases like H.S. Rinderpest, Foot and Mouth etc. Hand pumps and latrines were provided. Dewatering operations were undertaken at a very large scale. Fodder was provided at

subsidised rate. Taccavis were advanced for seed, fertilizer and cultivation through tractors. Special relief was announced for suspension and remission of land holdings tax and abiana. Recovery of Taccavi and other loans was postponed.

Government has also started work on drainage and other flood protection measures. Protective bunds are being constructed around the abadis which are likely to be affected by floods. Abadis of flood affected villages are being connected to the village approach road by a high level link road.

(c) Yes. The Government has decided that the expenditure which would have been ordinarily incurred by the Government in the construction of the protection works would be paid to the concerned Gram Panchayats as a reward.

Statement

Statement of estimated loss during 1977 floods

1.	Damage to crops approx .	Rs. 56 Crores	
2.	Damage to houses	Rs. 15	„
3.	Damage to public buildings		Rs. 2 „
4.	Damage to irrigation and drainage works	Rs. 7.45	„
5.	Damage to water works and public health installations		Rs. 0.45

„

6.	Damage to electrical installations.	Rs. 0.35	„
7.	Damage to roads	Rs. 7.00	„
8.	Loss to Transport Department on account of less receipts etc.	Rs. 1.00	„
9.	Damage to trees plantations	Rs. 0.10	„
10.	Anticipated loss of revenue on account of remission of land holdings tax and water rates.	Rs. 1.00	„

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Excessive Electricity Bills

71. Swami Adity a Vesh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Farmers who have got electric connections are being charged excessive electricity bills; if so, the reasons therefor;

(b) whether there is any proposal under

consideration of the Government to repeal the M.C.G. Rule of the Electricity Board, if not, the steps proposed to be taken by the Government to protect the farmers of flood affected areas of Mewat from the said rule ?

सिचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) यह तथ्य नही है कि जिन किसानों के पास बिजली के कुनैक्शन हैं उन से बिजली के बिल अधिक चार्ज किए जाते हैं । कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें निर्धारित हें तथा बिल इसी के अनुसार बनाए जाते हैं । जब किसानों को बिना मीटर के सप्लाई दी जाती है तो बिना धान के क्षेत्रों में 8 घण्टे तथा धान वाले क्षेत्रो में 8 घण्टे नलकूप चलने के आधार पर चार्ज किए जाते हैं ।

ऐसे कुछ. उदाहरण हैं जहां मीटर खराब होने के कारण बिल ठीक नहीं बनसे, ऐसे केस जब भी नोटिस में आते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाती है और बिलों को ठीक कर दिया जाता है ।

(ख) जी नहीं । अभी एम. सी. जी. को निरसन करने का कोई प्रस्ताव बोर्ड के विचाराधीन नहीं है । एम. सी. जी. केवल पांच वर्ष के लिए लगाई जाती है और विद्यूत कटौती या पाबन्दी के समय नहीं लगती । हाल ही में बाढ़ के कारण राज्य में विद्युत कटौती/बन्दी रही है, अत बाढ़–ग्रस्त क्षेत्रों में इस समय के लिए एम. सी. जी. नहीं लगेगी ।

अब तक जिस अवधि के लिए, विद्युत कटौती/बन्दी के कारण एम सी. जी. नहीं लगती थी तो एम सी जी. की अवधि उतने ही समय के लिए 5 वर्ष सैं आगे बढ़ा दी जाती थी । परन्तु 15—9—1977 से हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड नें एम. सी. जी. की इस अवधि को किसी भी हालात में पांच वर्ष से आगे न बढाए जाने सा निर्णय लिया है ।

Epidemic of Malaria

81. Sawami Aditya Vesh : Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state—

(a) the name of the Assembly Constituencies in which the malaria epidemic broke out during and after the recent floods;

(b) whether information about malaria epidemic is now not published in Government Gazette, if so the reasons thereof; and

(c) the Constituency-wise amount for which the medicines were distributed during the days of malaria epidemic togetherwith the Constituency-wise number of persons affected by Malaria ?

Food and Supplies Minister : (Shrimati Dr. Kamla Verma) : A statement is laid on the table of the House.

(a) Under the National Malaria Eradication Programme, the record of malaria cases is maintained for individual block and not on the basis of Constituency.

Therefore, the report regarding malaria cases and deaths during and after the recent floods is attached as Annexure 'A', for individual block.

(b) A notification under section 2 of Epidemic Diseases Act, 1897 regarding malaria was published by Haryana Government, Health Department vide their No. 3661-5HBII-77/30587 dated 21-9-77, incorporated in Haryana Governmeat Gazette No. 42, Part I, dated 18-10-77 (Page 1418).

Upto this period since the inception of National Malaria Eradication Programme, no information about malaria cases/deaths has been published in Government Gazette due to the following reasons :-

(i) The disease is not notifiable either in the country or under International Health Regulations.

(ii) The disease is an endemic one i. e. constantly prevelant since the year 1968 with seasonal variation in its intensity and has been increasing year after year not only in Haryana but throughout India and other countries.

(c) As already mentioned under the reply (a) the record is maintained for individual blocks and as such the amount for which the medicines (anti-malaria drugs) were distributed for the period July to October, 1977 togetherwith the number of malaria positive cases block-wise is enclosed as Annexure

ANNEXURE—A

Statement showing block-wise number of malaria

cases recorded in flood affected areas from July to October, 1977.

Sr. No.	District	Name of Block	July	Aug.	Sept.	Oct.	Total	No. of deaths
1.	Gurgaon	1. Gurgaon	784	1237	785	644	3450	
		Gurgaon City	338	698	585	286	1907	
		2. Faridabad	370	442	274	125	1211	
		Faridadad Comp.584		588	731	522	2525	
		3. Ballabgarh	256	129	475	35	895	
		4. Paiwal	539	—	379	219	1137	
		5. Hathin	427	752	939	196	2314	
		6. Hodal	506	947	461	158	2072	
		7. Punhana	178	275	268	77	798	
		8. F. P. Jhirka	108	522	223	136	989	
		9. Nuh	561	115	1103	175	1954	
		10. Sohna	361	611	223	179	1374	
		11. Pataudi	337	576	611	378	1902	
2.	Jind	1. Julana	1035	1369	1590	1221	5215	
		2. Jind	272	113	190	877	1452	

	Jind City	821	1222	826	958	3827
	3. Uchana	1339	1322	999	436	4096
	4. Safidon	767	2873	1371	1270	6281
	5. Narwana	1214	1174	879	681	3948
	Narwana City	378	331	303	275	1287
	6. Kalayat	1441	1529	1141	1101	5212
	7. Rajaound	1517	2573	3261	1138	8489
3. Kuru-	1. Pundri	1607	689	836	1300	4432
kshetra	2. Kaithal	789	785	1008	711	3293
	Kaithal City	145	126	517	202	900
	3. Thanesar	877	402	863	730	2872
	Thanesar City	606	1798	1003	529	4936
	4. Shahbad	734	948	883	788	3353
Narnaul	1. Narnaul	373	322	173	97	965
4.	Narnaul City	179	138	381	110	808
	2. Na	123	232	352	112	819

	ggal Chaudhry						
	3. Ateli	389	532	312	202	1435	
	4. Kanina	265	296	235	205	1001-	
	5. Mohindergarh	336	606	339	257	1538	
	M. Garh City	56	77	115	46	294	
	6. Khol	162	270	302	249	983	
	7. Bawal	294	440	404	271	1409	
	8. Rewari Jatusana	247	2	18	48	315	
	Rewari City	82	242	93	107	524	
5. Rohtak	1. Rohtak	828	657	883	432	2800	
	Rohtak City	1107	1462	1135	640	4344	
	2. Sampla	1098	704	391	473	2666	
	3. Badhadurgarh	430	416	306	195	1347	

	4. Jhajjar	1202	987	575	304	2968
	5. Kalanaur	914	1071	908	208	3101
	6. Meham Chiri	1301	1045	1086	951	4383
	7. Beri	1047	1900	713	585	4345
	8. Salawas	815	452	323	432	2022
	9. Nahar	885	1291	708	281	3165
6. Sonepat	1. Ganaur	1251	1629	1441	744	5065
	2. Mundlana	974	1106	1274	1264	4618
	3. Gohana	947	577	916	230	2670
	Gohana City	565	767	755	168	2255
	4. Kathura	1728	1833	886	281	4728
	5. Kharkhoda	2185	1528	1410	937	6060

6.	Rai	9460	969	834	428	3177
7.	Sonepat	1207	1318	830.	559	3914
	Sonepat City	572	907	450	165	2094

ANNEXURE '13'

Statement showing Blockwise malaria cases from January to December, 1977 alongwith amount spent on anti malaria drugs from July to October, 1977.

Sr. No.	District	Block/Town	No. of malaria cases confirmed microscopically from January to December, 1977.	No. of deaths	Amount spent on anti-malaria drugs from July to Oct., 1977.
1	2	3	4	5	6
1.	Ambala	1. Raipur Rani	5059		
		2. Naraingarh	4142		
		3. Bilaspur	3334		
		4. Chhachhrauli	4057		

		5. Jagadhari	5374		
		Yamun a Nagar	915	1	
		Town			
		6. Barara	4964		
		7. Ambala	6964	1	
		Ambala City	4422		
		Ambala Cantt.	3107		
		8. Pinjore	4874		
		Total	47222	2	Rs. 2,41,120/-
2.	Bhiwani	1. Bhi wani Khera	3850		
		2. Tos ham	5796		
		3. Bhi wani	6618		
		Bhiwani City	7248		
		4. Dad ri-I	5202		
		5. Dad ri-II	5015		
		Dadri City	2531		

		6. Badhra	4932		
		7. Loharu	4233		
		Total	45425		Rs. 2,25,765/-
3.	Gurgaon	1. Gurgaon	6099		
		Gurgaon City	2571		
		2. Faridabad	2850		
		Faridabad Complex	6583		
		3. Ballabgarh	267		
		4. Palwal	3019	1	
		5. Hathin	4777		
		6. Hodal	3922		
		7. Punhana	2279		
		8. F. P. Jhirka	4105		

		9.	Nuh	5636	1	
		10.	Sohna		3422	
		11.	Pataudi	3853		
		Total		51793	3	Rs. 4,91,505/-
4.	Hissar	1.	Narnaud	7071		
		2.	Hansi-I	4455		
		3.	Hansi-II	6278		
		Hansi City		1220		
		4.	Hissar-I	5102		
		5.	Hissar-II	5464		
		Hissar City		7327		
		6.	Barwala	7342		
		7.	Bhuna	5993		

		8.	Tohana	6246	
		9.	Fatehabad	5277	
		Fatehabad Town		199	
		10.	Ratia	4940	
		Total		67418	Rs. 1,95,498/-
5.	Jind	1.	Juliana	9337	
		2.	Jind	5829	
		Jind City		6336	
		3.	Uchana	10369	
		4.	Safidon	15746	
		5.	Narwana	10016	
		Narwana Town		2264	
		6.	Kalayat	13778	

		7. Raj ound	16529			
		Total	90204			Rs. 3,53,473/-
6.	Karnal	1. Kar nal	7257			
		Karnal City	13476			
		2. Gh arounda	9196			
		3. Pan ipat	5704			
		Panipat City	2739			
		4. Sa malkha	5110			
		5 Matlauda	4875			
		6, Assandh	5232			
		7. Nissing	6892	1		
		8. Nilokheri	10970			
		Total	71451	2		Rs. 1,85,680/-
7.	Kuru-	1. Pun dri	10672			
	kshetra	2. Kai thal	11537			

		Kaithal Town		1888	
		3.	Guhla	5830	
		4.	Thanesar	9620	
		Thanesar Town		7669	
		5.	Shahbad	8283	
		6.	Ladwa	9556	
		Total		65055	Rs. 2,28,429/-
8.	Narnaul	1.	Narnaul	2112	
		Narnaul City		1195	
		2.	Naggal Chaudhry	3058	
		3.	Ateli	3408	
		4.	Kaniana	3896	
		5.	Mohindergarh	4203	

		M. Garh Town	564	
		6. Khol	2243	
		7. Bawal	4149	
		8/9. Rewari Jatusana	1527	
		Rewari City	1129	
		Total	27484	Rs. 2,58,700/-
9.	Rohtak	1. Rohtak	7464	
		Rohtak City	8370	
		2. Sampla	7912	
		3. Bahadurgarh	3492	
		4. Jhajjar	8767	
		5. Kalanaur	6170	
		6/7. Meham Chiri	8584	
		8. Ber	7132	

		i				
		9.	Sal awas	5003		
		10.	Nah ar	5349		
		Total		68243	—	Rs, 2,20,610/-
10.	Sonepat	1.	Ga naur	8365		
		2.	Mu ndlana	7054		
		3.	Go hana	7301		
		Gohana City		3792		
		4.	Kat hura	7905		
		5.	Kha rkhoda	12816		
		6.	Rai	6704		
		7.	Son epat	8128		
		Sonepat City		3457		
		Total		65522	—	Rs-.

					2,99,190/-
11.	Sirsa	1.	Sirsa	5884	
			Sirsa City	5003	
		2.	Rania	4452	
		3.	Baragudha	3440	
		4.	Dabwali	5261	
			Total	24040	— Rs. 74,260/-

Uncultivated land in flood affected area

58. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Revenue be pleased to state--

(a) the constituency-wise area of land in hectares remained without sowing in flood affected area due to non-availability of fertilisers and seed;

(b) the number of farmers who have not sowed their land absolutely in flood affected areas;

(c) the relief if any being provided by the Govt. to those farmers who have not sowed their lands togetherwith the time by which the said relief will be provided; and

(d) whether no relief is being provided, if yes, the reasons thereof ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह) :

(ए) शून्य

(बी) वांछित सूचना बहुत लम्बी तथा समय लेने वाली है । इसे एकत्र करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे लाभप्रद उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी ।

(सी, डी) बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चारा, बीज, खाद तथा ट्रैक्टरों के चलाने में व्यय होने वाली राशि तकावी एवं अनुदान के रूप में समता के आधार पर दी जा रही है । इसी प्रकार मुफ्त राशन रजाइयां इत्यादि भी बार पीड़ितों में बांटी जा रही हैं । ऐसे कृषकों को जिन्होंमें बाल के कारण जमीन नहीं बोई विशेष श्रेणी नहीं माना गया हुऐ ।

Civil Hospitals

59. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state—

(a) whether there is an proposal under consideration of the Government to open the Civil Hospitals in each of the Assembly Constituencies of the State if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ; and

(b) the steps, if any taken or proposed to be taken for protecting the health of citizens affected from diseases ?

खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा) :

(क) नहीं

(ख) (1) नागरिकों के स्वास्थय रक्षा के लिये स्थापित स्टेट पब्लिक एलोपतिक चिकित्सा संस्थाओं महाऋषि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के नियन्त्रण में चिकित्सा संस्थाओं सहित) की संख्या निम्न प्रकार से है –

(1) हस्पताल	48
(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	89
(3) डिसपैसंरियां	167
(4) उप केन्द्र	743

83 अतिरिक्त उप केन्द्रों की स्थापना कार्यवाही अधीन है ।

(2) स्वास्थ्य विभाग की संभावी योजना में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों को चिकित्सा सम्बन्धी सु विधाएं उपलब्ध करने के साथ–साथ मैडीसन, छूत से फैलने वाली बिमारियों की रोकथाम, पोषाहार, स्वास्थय शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में समेकित सेवाएं उपलब्ध करने हेतु अधिक संख्या में गांवों तथा छोटे शहरों में उप केन्द्र तथा सवसिडरी प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

Storage Capacity

107. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the Government owned storage capacity of Fcod grains in the state in the year 1966 and also in March, 1977 ?

खाद्य एम पूर्ति मन्त्री (श्रीमती डा 0 कमला वर्मा) :

वर्ष 1966 में राज्य में अनाज के भन्डार के लिए उपलब्ध सरकारी

गोदामों की भन्डार क्षमता ।

31,395 टन

मार्च, 1977 में राज्य में अनाज के भण्डार के लिए उपलब्ध सरकारी

गोदामों की भण्डार क्षमता ।

135390 टन

Schools Upgraded

108. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Education be pleased to state the number of primary schools upgraded to middle classes from 1st May, 1968 to 1st April, 1977 and also the number of middle schools upgraded from Middle to High Schools during the period referred to above.

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :

1 प्राइमरी से मिडल स्तर तक अपग्रेड किए गए स्कूलों की संख्या 295

2. मिडल से हाई स्तर तक अपग्रेड किए गए स्कूलों की संख्या 303

Operated Kilometrage of Haryana Roadways Buses

109 Shri Surrender Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the total operated kilometrage of Haryana Roadways during the year 1967-68 and then in 1976-77 ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल) :

1987— 68	400.26 लाख
1976—77	1706.27 लाख

Depots, Sub depots and Bus-stands

110. Shri Surrender Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the number of Depots, sub-depots, Bus-stands and Temporary Bus stands in the State on 1-5-1968 and then on 31st March, 1977 ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal) :

The requisite information is given below :-

As on 1-5-1968

Depots	Sub-	Bus-	Temporary

	depots	stands	bus-stands
1	2	3	4
4	6	4	1
As on 31-3-1977			
10	19	11	25

शोक प्रस्ताव

श्री हीरा नन्द आर्य : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर है ।

श्री अध्यक्ष : अभी शोक प्रस्ताव है । उसके बाद आप बोलें ।

उद्योग मन्त्री (डा0 मंगल सैन) : स्पीकर साहब, बडे दु:ख के साथ मैं सदन में यह प्रस्ताव रख रहा हूं । – (विध्न)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । शोक प्रस्ताव हो रहा है ।

डा0 मंगल' सैन : स्पीकर साहब, भारत की एक महान विभूति श्री बशीर अहमद का 2 मार्च सत् 1978 को स्वर्गवास हो गया । वे संसद सदस्य थे । वे बड़े 0ंचे और पाए दर्जे के वकील थे । उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत पासकी थी । पहले वे इलाहाबाद में वकालत की प्रैक्टिस करते रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे । स्पीकर साहब, सन् 1974 में जब मीसा का कानून लाग हुआ तो उसके खिलाफ बड़ी लम्बी जंग

सुप्रीम कोर्ट में लड़ी थी । सन 1975 में जब राष्ट्रपति का चुनाव सम्बन्धी रैफैंस सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ दलील पेश की । बड़े 0ंचे दर्जे के पार्लियामैंटेरीयन' थे । वे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर हलके से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे । अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, वे संसार से चल बसे । स्पीकर साहब भगवान की गति बड़ी विचित्र है, उसकी माया को वही जानता है । मैं सदन के सामने उनके निधन पर शोक प्रस्ताव रखता हूं कि इस सदन को गहरा दुख है और यह सदन परमात्मा से याचना करती है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले और उनके परिवार को उनके बिछुडेपन की सहनशक्ति दे ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल (छछरौली) : स्पीकर साहब, जो शोक प्रस्ताव मन्त्री महोदय की तरफ से रखा गया है, मैं उसमें शामिल होता हूं । श्री बशीर अहमद जो हमारी पार्लियामैंट के मैंबर थे, बड़े काबिल वकील और पार्लियामैंटेरीयन थे । मैं उनके खानदान से हमदर्दी प्रकट करता हूं और श्रद्धांजलि पेश करता हूं । भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे ।

श्री अध्यक्ष : मैंबर साहिबान ने जो सदन में विचार रखे हैं, में भी अपने आपको उनके साथ शरीक करता हूं । आपकी तरफ से और अपनी तरफ से उनके परिवार के साथ जो हमारी हमदर्दी है, उनके परिवार तक पहुंचगा ।

अब मैं सब से निवेदन करूंगा कि आप सब खड़े हो कर उनकी याद में दो मिनट के लिए मौन धारण करें ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आरम। की बार में दो मिनट का मौन धारण किया ।)

श्री हीरा नन्द आर्य स्पीकर साहब, हमने 28 तारीख को 1 1 सदस्यों ने एक कोल– अटैनशन मोशन आपको दी थी । – (विघ्न) –

श्री अध्यक्ष : आपको चिट्ठी आ चुकी होगी । आप मेरे चौम्बर में आएं और इस बारे में तब वहां बात करे । – (विघन) –

श्री हीरा नन्द आर्य : आपका जवाब तो आ चुका है । आपने इस मामले को सबजुडिस बता कर हमारी मोशन. को रिजैक्ट कर दिया है । सब जु डिस तो वह मामला होता है । जो कोर्ट ने चल रहा हो । (विघन) –

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चौम्बर में आएं ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, वहां पर बड़ा भारी जुल्म हुआ है । आज तक गृह मन्त्री महोदय ने कोई भी स्टेटमैंट नहीं दी है । उनको स्टेटमैंट देनी चाहिए ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, सारा सदन चाहता है कि इस बारे में मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट दें । – (विध्न) –

चौधरी रण सिंह मान : स्पीकर साहब, इस तरह की कही भी वारदात हो सकती है हाउस में जवाब आना चाहिए । – (विघन) –

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा है कि मेरे चौम्बर में आकर इस बारे में बात करें । – (विध्न) – आप दोनों तीनों बात क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे चौम्बर में आकर बात करे ।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, इसके बारे में हाउस मे डिस्कशन होनी चाहिए । यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप मुझे उनसे बातें कर लेने दें । उसके बाद देखेंगे ।

कार्य–मत्रणा सभी की द्वितीय रिपोर्ट

Mr. Speaker : I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various Business.

"The Committee met at 4.00 P.M., on Monday, the 6th March, 1978, in the Chamber of the Speaker."

The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 7th, 8th, 9th, 10th, 13th, 14th and 15th March, 197 8, be transacted as follows :-

Tuesday, the 7th March, 1978 (9.30 a.m.)

1. Questions Hour.

2. Obituary reference on the death of late Shri Bashir Ahmed, M.P.

3. Presentation and adoption of Second Report of the Business Advisory Committee.

4. Papers to be laid on the table of the House.

(1) Annual Audit Report of Haryana Agricultural University, Hissar for the year 1975-76.

(2) Annual Report on the working of Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1976 to 31st March, 1977.

(3) Administration Report 1975-76, of H.S.E . B.
(5) General discussion on Budget.

Wednesday, the 8th March, 1978 (9.30 a.m.)

1. Questions Hour.

2. Laying on the Table the Report of the Rules Committee.

3. Resumption of discussion on Budget.

Thursday, the 9th March, 1978 (9.30 a.m.) L Questions Hour.

2. Non-Official Business.

3. Half an hour discussion on Starred Question No. 228 by Swami Aditya Vesh, M L. A.

Friday, the 10th March, 1978 (9.30 a.m.)

1. Questions Hour.

2. Resumption, of discusion on Budget. Saturday, the 11th March, 1978 Off-Day

Sunday, the 12th March, 1978

Holiday

Monday, the 13th March, 1978 (2.00 p.m.)

1. Questions Hour.

2. Discussion and voting on Demands for Grants on Budget.

Tuesday, the 14th March, 1978 (9.30 a.m.)

1. Questions Hour.

2. Appropriation Bill on Supplementary Estimates.

3. Appropriation Bill on Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1973-74.

4. Appropriation Bill on Budget .

5. Legislative Business.

Wednesday, the 15th March, 1978 (9.30 a.m.)

1. Questions Hour.

2. Legislative Business.

उद्योग मंत्री (डा 0 मंगल सैन) : स्पीकर साहिब, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की द्वितीय रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

Mr. Speaker : Motion moved.

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried..

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष : अभी कुछ कागजात टेबल पर रखें जायेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Sir, I beg to lay on the Table the Annual Audit Report of the Haryana Agricultural University, Hissar, for the year 1975-76, as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

I also lay on the Table the Annual Report on the

working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1976 to 31st March, 1977, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

I also beg to lay on the Table the Administration Report of the Haryana State Electricity. Board for the year 1975-76 as required under Section 75 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

Mr. Speaker : In order to enable the maximum number of Members to participate in the general discussion on Budget it would be better if those hon. Members who have already spoken on the Governor's Address may not try to catch my eye. This will help particularly the new legislators and back benchers to contribute to the deliberations of the House.

श्री शमशेर सिंह (नरवाना) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मत्री जी ने सदन के सामने 1978– 79 के लिये जो बजट पेश किया है, उसमें 28–29 करोड रुपये के करीब घाटा का अनुमान लगाया गया है, उसमें से साढे तीन करोडुरुपये के लगभग टैक्सों के जरिये पूरा करने का प्रस्ताव है । बाकी का जो घाटा है, खसारा है, उस को अनकवर्ड छोड़ दिया गया है । अपने बजट भावन में वित्त मंत्री जी ने यह बात भी कही है कि इस खसारे को? घाटे को भारत सरकार से सहायता लेकर, अपने प्रान्त के अन्दर कर्जों की अधिक वसूली करके और सरकारी खर्च में कमी करके पूरा करने का प्रयत्न करेंगे । लेकिन इसके साथ–साथ अध्यक्ष महोदय बजट पेश करने वाले रोज ही पत्रकारों से बात करतेहुए वित्त मन्त्री जी ने यह बात भी मानी है कि इस बात के

लिये कोई वचन नहीं दे सकते कि इस सान के मध्य में इस खसारे को पूरा करने के लिये और टैक्स नही लगायेगे । मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने यह जो पहले बजट में इतना खसारा अनकवर्ड छोड़ दिया है, इसका कोई सियासी मतलब है और (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।)

वह सियासी मतलब सब को मालूम है कि करनाल लोकसभा का चुनाव जल्दी ही होने जा रहा है इस कारण सरकार 25 करोड़ रुपये' का लगभग जो खसारा है, उसको टैक्सों के जरिये साल के मध्य में आर्डीनेस के जरिये से विधान सभा की पीठ के पीछे, विधान सभा की गैर– हाजिरी में यह सरकार लगाना चाहती है । (जल)

उद्योग मत्री (डाक्टर मंगल सैन) : यह आपकी सरकार की प्रथा रही है, हमारी नहीं है । (विघ्न)...

श्री शमशेर सिंह : हरियाणा की जनता को इस बात के लिये सावधान होना चाहिए कि जनता पार्टी को सरकार के पहले बजट में 25 करोड़ रुपये का जो घाटा है, वह उसने अनकवर्ड छोड़ दिया हए । वह साल के दौरान विधान सभा की बगैर मन्जूरी के आम जनता के पर भारी टैक्स लगायेगी । उपाध्यक्ष महोदय, जो टैक्सों की प्रोपोजल वित्त मन्त्री ने इस बजट भाषण में आपके सामने रखी है, इस सदन के सामने रखी है, उससे इस सरकार

का यह बिस्कूल थोथा दावा है कि वे जनता के नुमायन्दे हैं, लोगो के नुमायन्दे है, मुकम्मल तौर पर नंगा हो गया है ।

चौधरी लाल सिंह : आम ए प्वांयट आफ आर्डर सर । देखिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि फजूल की वकालत इस हाउस के अन्दर करना क्या यह कोई ठीक बात है, मुझे तो यह बात ठीक नकर नहीं आती । जहां तक जनता पार्टी के बजट का सम्बन्ध है, वह जनता खू ब समझती है और यह तो (विध्न)....

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी लाल सिंह जी, आप बैठिये ।

श्री शरशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बात करके अपने आप को ही नंगा करते हैं । जनता पार्टी की सरकार ने पैसेन्जर टैक्स में 10 प्रतिशत बढ़ौतरी करके कोई अच्छा काम नहीं किया । हरियाणा के अन्दर पहले ही बस के भाडे हमरि पड़ौसी प्रान्तों के मुकाबले में सबसे ज्यादा थे, उसको और अधिक बढ़ा कर आम. आदमी के लिये, जन साधारण के लिये बस का जो सफर है, वह बहुत महंगा कर दिया है । जनता सरकार ने ट्रकों के पर और यहां तक कि मोटरसाइकिल और स्कूटरों पर, जिसको कि सिवाय मध्यम और नीचले दर्जे के लोग ही इस्तेमाल करते हैं और कोई नही करता, टैक्स बढ़ा कर जहां यूक तरफ दरम्यानें आदमियों के पर बोझा डाला है वहां दूसरी तरफ ट्रकों के पर टैक्स बढ़ाया है, ' इस का नतीजा यह होगा कि जो आम इस्तेमाल

की चीजे है, उनके ट्रान्सपोर्टेशन करने में खर्चा बढ़ने से वह चीजे प्रान्त के अन्दर और ज्यादा महंगी हो जायेगी । उपाध्यक्ष महोदय, किसान के नाम पर मगरमच्छ के आसू बहाने वाली यह जनता पार्टी की सरकार के लिए निहायत ही शर्म की बात है । पहले ही बजट के अन्दर, किसानों के पर नहरी आवियाना का बोझ बहुत ज्यादा था, उसको भी 10 प्रतिशत और बढा दिया गया है । इससे यह सरकार, जो आने आप को किसानों की सरकार कहती थी, बिल्कुल नंगी हो गयीहै । उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी का नाम लेने वाली, महात्मा गांधी की कसम खाने वाली और छोटी दस्तकारी को, घरेलू दस्तहारी को प्रोत्साहन देने वाली जनता पार्टी की सरकार ने खादी बोर्ड के पास रजिस्टर्ड सोसाइटियों को जो सेल्ज टैक्स की एम्जैम्पशन दे रखी है, उसको वापिस ले करके, सब के सामने नंगी हो गयी है मैं वित्त मन्त्री जी से यह सवाल पूछना चाहूंगा कि एक सोसायटी में कम से कम 15 आदमी होते है और एक साल में अगर 75 हजार रुपये की एम्जेम्पशन के अन्दर वह काम करते हैं तो एक आदमी केवल 5, 000 रुपये का माल एक साल के अन्दर बना सकेगा । उतका मुनाफा अगर 10 प्रतिशत के हिसाब से लगायें तो 500 रुपये बनता है जिसका मतत्नुब यह हुआ 40 रुपया महीना तक उनको कमाई केरने की एग्जेम्पशन है । तो आप ही देखिये यह तो जनता पार्टी की सरकार हए (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के मंत्रियों ने यह बात कही कि कई बोगस सोसाइटिया बनाई हुई थी । इस बात का इस एग्जैम्पशन से कोई ताल्लुक नही है । अगर कोई बोगस सोसायटी

बनी है तो उसके खिलाफ ऐक्शन रेना चाहिए, उसको कैंसिल करना चाहिए और उन्हें तोड़ना चाहिए । यह नहीं करना चाहिए गरीब आदमियों परं या छोटी दस्तकारी के पर और ज्यादा टैक्स का बोझ लाद कर जो घरेलू दस्तकारी है, उसको प्रोत्साहन देने की बजाये । उनको बन्द करवाये । यह जो टैक्स लगाया गया है यह इस बात को जाहिर करता है कि सरकार की क्या नीति है । उपाध्यक्ष महोदय जनता पार्टी को सरकार ने बाद समय में मन्त्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि जनता पार्टी ने. जो वायदे लोगों के साथ किये थे, उनको पूरा करने के लिये सरकार पूरा–पूरा प्रयत्न करेगी । मैं आपके माध्यम से यह बात पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में और चुनावों के बाद इसके मंत्रियों ने और नेताओं द्वारा जो वायदे किये गये थे, क्या उनमें से किसी एकाध का जिक्र इस बजट के भाषण के अन्दर या गर्वनर साहब का जो एड्रैस था, उसमें किया है, उसमें कोई जिक्र नही है । जनता पार्टी ने लोगों से यह वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद वोटर को इस बात का अधिकार देंगे कि वह अपने नुमायन्दे को रीकल कर सकें,. वापिस बुला सके ।

डा0 मंगल सैन : वह तो लोक समा की बात है । कांस्टीच्यूशनल अमैंडमैंट की बात है । (विघन)

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का भी इन्होंने वायदा किया था कि अगर जनता पार्टी की सरकार पावर

में आयी तो मोहल्लों से लेकर गांव तक और छोटी– छोटी. जगह पर जनता ले के लोगों की चौकसी कमेटिया बनायेंगे । विजीलैन्स कमेटियां बनायेने. जो जनता पार्टी के लोगों और मंत्रियो के पर निगरानी रख सकें । लेकिन' आपको उपाध्यक्ष महोदय इस बात का पूरीतरह से ज्ञान है कि इन का यह भी एक वायदा था जो इन्होंने अभी तक पूरा नही किया है । विजीलैंस पेटियों के बनाने का जहां तक ताल्लुक है, आपको भी पता हैकि अमी तक किती स्तर पर भी कोई कमेटी–जनता पार्टी ने बनायी नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने चुनाव प्रणाली में सुधार करने का भी वचन लोगों को दिया था ।

डा 0 मंगल सैन : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । डिप्टी स्पीकर साहब, क्या कोई मैम्बर लोकु उमा को परिधि की बातें यहां पर कर सकता है? यह चुनाव प्रणाली में तब– दीली लोकसभा ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : चौंधरी साहब अगर आप अपने आपको बफेट तक ही कन्फाईन रखें तो अच्छा रहेगा ।

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर लोक सभा का या और किसी बात का कोई ताल्लुक नहीं है । सवाल सिर्फ यहं है कि यहां पर जनता पार्टी ने अपने घोषणा–पल में यह बातें कहीं थीं क्या इनको पूरा करने के लियें इन्होंने प्रान्तीय स्तर पर कोई उपाय इसके लिये किया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगली

बात यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के एक मन्त्री श्री मोहन धारिया हैं, उन्होंने हिन्दुस्तान की वितरण प्रणाली से सुधार करने के बारे में कहा था । जनता पार्टी ने इस वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का वाया 'किया था ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पार्टीपोलिटिक्स डिस्कस न करें । आप सिर्फ बजट पर ही बोलें ।

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वितरण प्रणाली है यह बजट की ही बात है और मैं उसी को बात कह रहा हूं । जब से जनता पार्टी सता में आई है तब से जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इसने कोई पग नही उठाया बल्कि उल्टे जनता पाटी ने ईंटों के भट्टे वालों से मिलकर–

Mr. Deputy Speaker : I would request the hon. Member to please discuss the Budget and to remain within the scope of discussion.

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार है और मैं यह बात ही कह रहा हूं । दोनो में कोई फर्क नहीं है । जनता पार्टी की सरकार ने भट्टे के मालिकों से मिलकर ईंटों से कन्ट्रोल उठाकर 150, 160 और 170 रुपए प्रति हजार के भाव से हरियाणा में ईंटें बिकवाई हैं । यह काम इन्होंने ईंटों के भट्टे वालों से मिंत्रीभगत करके किया है और दूसरी ओर सीमेन्ट जैसे वस्तु आज हरियाणा में किसी कीमत पर आम आदमी को नहीं मिलती । यह बात जनता सरकार के राज्य

मैं हुई है । जनता सरकार ने लोगों से वायदा किया था कि जनसाधारण के इस्तेमाल में आने वाली चीजे जैसे दवाइयां, मकान और कपड़ा आदि तया दूसरी चीजें जनता को आसानी से तथा सस्ती उपलब्ध करायी जायेगी, लेकिन आठ महीने या एक साल के राज के अन्दर जनता सरकार ने सिर्फ कमीशन दिए हैं और उपाध्यक्ष महोदय वे कमीशन जिनके पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, बरबाद किया जा रहा है । वे जनता की भूख को नहीं मिटा सकते, किसी के तन को ढांपने के लिए कपड़ा नहीं दे सकते ।

चौधरी संत कंवर : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट पर चर्चा हो रही हो तो क्या कोई सदस्य कमीशन की बात कर सकता है और वैसे भी यह एक जुडिशियल मैटर है । यह तो हाउस में आ भी नहीं सकता ।

Mr. Deputy Speaker : I would, for the information of the hon. Member, read out the scope of discussion today. The scope of discussion at this stage is confined to an examination of the general scheme and the structure of the budget. So, I would request the hon. Member to please confine himself to the scope of discussion.

श्री शमशेर सिंह : मैं स्कोप के अन्दर ही बोरर रहा हूं । इनके पेट में दर्द हो सकता है इनको सुनने के लिए धैर्य होना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, बजट में गरीबी को दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बजट भाषण में सरकार ने

वायदा किया है । उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में, पहली जनवरी, 1978 को 15 हजार ग्रेजुऐट, अढाई हजार पोस्ट ग्रेजुएट, चार सौ से अधिक डाक्टर, 350 इंजीनियर, 57 हजार मैट्रिकुलेट, 32 हजार मिडिल पास, नौ हजार आई0 टी0 आई0 से ट्रेनिंग लिए हुए कैंडिडेट्स, सात हजार जे 0 बी0 टी0, और 1500 शास्त्री और प्रभाकर बेरोजगार हैं और इतने लोगों के नाम एम्पलाएमैंट एक्स–चेंजिज में दाखिल हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज इतने बेरोजगार लोगोंने अपने नाम एम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज में दाखिल कराए हैं । मैं जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो उसने बजट पेश किया है उसके अन्दर रोजगार देने की जो स्कीम रखी है वह कितना बड़ा ढकोसला है, कितना बड़ा मजाक, हरियाणा के लाखों पढ़े–लिखे लोगों के साथ इस जनता सरकार ने किया है । सरकार ने बजट में कहा है कि चालू साल के अन्दर जनता पार्टी सरकार देहात के अन्दर पढ़े–लिखे नौजवानों के लिए 110 इंडस्ट्रियल यूनिट खोलेगी और एक इंडस्ट्रियल यूनिट में लगभग चार के करीब नौजवान काम कर सकेंगे, उसमें शामिल हो सकेंगे । चालू साल में एक हजार बेरोजगारों को रोजगार देंने का इनका प्रोग्राम था और अगले साल अढाई हजार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की योजना है । दोनों सालोंमें साढ़े तीन हजार नौजवानों को यह सरकार रोजगार देना चाहती है और इस तरह से लोगोंकी. आंखों में धूल झोंकना चाहती है । आज लाखों की तादाद में 'एम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिंज में बेरोजगार नौजवानों के नाम लिखे हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अन्दर प्रस्तुत हुई

एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पहली जनवरी को रोजगार के दफ्तरों में जितने नाम दर्ज हैं उनको रोजगार देने केलिए मौजूदा सरकार की जो रोजगार देने की स्पीड है, जनता पार्टी की जो रफतार है उसके मुताबिक 32 साल उनको रोजगार देने में लगेंगे । इससे बड़ी मजाक की और क्या बात हो सकती है, बेरोजगार नौजवानों के साथ इससे ज्यादा खिलवाड़ की और कोई बात नही हो सकती । उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार और अपने वित्त मंडी महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । रोज ही सरकारी गजट द्वारा नौकरियों के लिए और इन्टरव्यू के लिए 'एडवरटाइजमैंट तथा इश्तहार निकाले जाते हैं और हजारों नौजवानों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाता जै । यह बात हाउस को अच्छी तरह से ज्ञात है कि जहां पांच आसामी खाली होती हैं उसके लिए हजार या दो हजार नौजवान ऐप्लाई करते हैं । सरकार ने उसके लिए फार्म की फीस रखी हुई है और दूसरी फीसें रखी हुई हैं । बेरोजगार नौजवानो को इन्टरव्यू केलिए शहर में जाना पड़ता है और उसके लिए पचास अथवा सौ रुपए खर्च करने पड़ते हैं । इस सरकार ने अपने आठ महीने के शासन के दौरान बेरोजगार लोगों को राहत देने के लिए क्या कोई पग उठाए, क्या इस सरकार ने उन फार्मों की जो कीमत है वह माफ की है? क्या इस सरकार ने जो गरीब नौजवान इन्टरव्यू के लिए आते हैं उनको कुछ राहत दी है? इस सरकार को यह करना चाहिए कि इन्टरव्यू से एक दिन पहले का और एक दिन बाद का जहां उनको इन्टरव्यू के लिए जाना हो वहां का एक पास इशू

करना चाहिए जिससे कि वे बस में फ्री सफर करें ताकि रोजगार न मिलने की सूरत में उनके मां बाप के पर खर्चे का बोझ न पड़े । उपाध्यक्ष महोदय मेरी ऐसी धारणा एं कि जनता पार्टी सरकार या इसी तरह की कोई पूंजीवादी सरकार बेरोजगारी का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकती । यह बहुत इम्पोरटेंट मामला है और जब तक समाज के अन्दर कोई बेसिक तबदीली न की जाए तब तक यह मसला हल नही हो सकता । इस विषय पर यह जनता पार्टी की सरकार समाज को आगे ले जाने वाली सरकार नही है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ।

इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव यह है कि पूंजीवादी समाज में बेरोजगारी का सब से बड़ा कारण यह है कि एक परिवार के पास बीस रोजगार हैं । एक परिवार के पास जहां जमीन है, वहां बिजनैस भी है, पेट्रोल पम्प भी है, सरकारी नौकरी में भी उस परिवार के सदस्य हैं और कई और दूसरे काम भी हैं लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी होगा कि शहरों और गांवों के अन्दर सौ परिवारों के पास एक भी रोजगार नहीं होगा । क्या यह जनता पार्टी सरकार ऐसा करवाने का इन्तजाम कर सकती है कि जिस परिवार के पास एक रोजगार है दूसरे नए परिवार को यह –सुविधा दी जाए । यह नहीं होना चाहिए कि एक ही परिवार के पास सारे रोजगार. की –सुविधा हो लेकिन दूसरे के पास कुछ भी सुविधा न हो । इस तरह का इन्तजाम अगर आप कर सकते हैं तो

बेरोजगारी की समस्या कुछ हल होने की सम्भावना है । यह नहीं होना चाहिएं कि एक ही परिवार समाज की सारी सुविधाएं भोगे । इस तरह का इंतजाम पूंजीवादी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर के अन्दर, अगर आप ईमानदार हैं तो अपने तबके के अन्दर इस तरह की बात कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार कृषि को प्राथमिकता देने का ढिंढोरा पीट रही है और इस बात का जिकर इस बजट में भी किया गया है । मैं आपके माध्यम से इस हाउस में कहना चाहता हूं कि इस बजट में कृषि के लिये और उसकी एलायड ब्रांच के लिए कुल 22 करोड़ रुपये का इन्तजाम किया गया है । 22 करोड़ रुपया कुल बजट का 2 ण्वां भाग है । यह जनता सरकार जोकि अपने आपको किसानों की बहुत हितैषी बताती है, इनके काल में जो हरियाणा के किसानों का नुकसान हुआ है उसका रिकार्ड पिछले तीस सालों में नहीं मिलता है । यह एक बड़ी दुःख की बात है कि किसान के गन्ने के भाव, गुड के भाव, कपास और तिलहन के भाव कितनी बुरी तरह से गिरे हैं, लेकिन यह सरकार अपनी गूंगी जवान के कारण टस से मस नहीं हो रही है । अत यह कहना होगा कि यह जो जनता सरकार है यह जनता की मदद के लिये यहां नहीं आई है क्योंकि सरकार ने इस ओर कोई खास तवज्जो नहीं दी है । अन्य चीजों के भाव बढ़ते ही गये हैं, इस लिये किसानों के बीच बड़ी हाहाकार मची हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि सरकार को इस हाउस के सीनियर

मेम्बर्ज की एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए ताकि ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऐक्सपर्टों की मदद से, गन्ने, कपास और चावल व अन्य चीजों के लिये एक कविंटल की कास्ट आफ प्रोडक्शन निकाल कर भाव फिक्स किये जाये और इन सारी बातों का शीघ्र ही निर्णय हो सके । जनता पार्टी ने जिन लोगों से वायदा किया था कि भाव नहीं बढ़ाये जायेंगे उन के हार्ट बर्न हो रहे हैं । सरकार ने कहा था कि 150 रुपये गन्दम और 125 रुपये चावल का भाव देंगे लेकिन यह जनता पार्टी का राज है, यह केवल 5 रुपये किवटल ही रेट बढ़ा सके हैं और वह भी किसानों को समय पर नहीं मिला है । किसानों को अपनी चीज का आज वही भाव मित्र रहा है जोकि श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में मिलता था पर इस जनता सरकार ने अपनी ओर से क्या किया? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हू कि ये कहते हैं कि हम मजदूरों के सबसे ज्यादा हितैषी हैं, उनको मारने वाले नहीं हैं, मारने वाले तो हमारे सामने बैठे हैं । हम चाहते है कि बजट में कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे कि गरीब किसान, मजदूर को सस्ते दामों पर चीजे मिल सकें लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की तरफ कोई ध्यान नही दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जरा समय का ध्यान भी रखें ।

श्री शमशेर सिंह : तो मैं कहने जा रहा था कि इस बजट स्पीच में भूमिहीनो के लिये हरिजनों के लिये, पिछड़ी जाति के लोगों के लिये गरीब लोगों केलिये एक शब्द भी नहीं बस्ता है

और इस में जितना भी पैसा खर्च किया गया है गरीब श्रेणी के लोगों पर खर्च नहीं किया गया है, गरीब लोगों के लिये ऐसे कोई साधन उपलब्ध नहीं किये गये है । उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में जिन्दगी की जरुरी चीजें जो हैं उनको उपलब्ध कराने की बात कही गयी है । इस बारे में दो लफजो में आपको बता देना हूं कि इस सरकार की पालिसी क्या है कि जो उप– भोक्ता है उसके लिये कीमतें ज्यादा और उत्पादक के प्रिये कीमतें नीची, इन दो शब्द में ही सारा विश्लेषण हो सकता है । इससे वातक और कोई जन साधारण के लिये नीति नहीं हो सकती । इस सरकार के राज में सरमायेदारों को भी पूरा उत्साहित किया जा रहा है । इस बारे में मैं जरा रोशनी डालना चाहता हूं । श्री एच0 पी 0 नन्दा जो कि एस्कोर्ट कम्पनी केमालिक हैं उन्होंने जुताई कें लिये 50 ट्रैक्टर एक महीने के लिंपे दे दिये और इस बात का बड़ा प्रचार भी किया गया कि जो सरमायेदार है, उनके हृदय. भी बदल– गय हैं, उसके बदले में अब नन्दा साहब ने क्या किया इस' साल जनवरी से उसी एक टैरक्टर की कीमत दो हजार रुपया बढ़ा दी है और इस जनता विरोधी सरकार के जू तक नही. रेंगी । सरकार ने इस ओर ध्यान देने का कोई प्रयत्न नही किया कि यह कीमत क्यों बढ़ाई गयी है? इस तरह कहने का मतलब यह है कि 50 टैरक्टर देकर किसानों का खू न चूसा गया । उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की जो पालिसी है वह मजदूर दुश्मन पालिसी है । इस बजट में मजदूरों के लिये आंसू बहाने के सिवाये और कुछ नहीं दिया गया है फिर सरकार कहती है कि समझौते के द्वारा मजदूरों का फैसला करा

रहे हैं, आज यह बात सा रे हिन्दुस्तान में ज्ञात है । इस बारे में पार्लियामैंट में एक काल अटैन्शन मोशन भी आ चुका है । उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में मजदूरों में कितना दम है, आज यहां जिस तरह से मजदूर गरीब किसान कुचले जा रहें हैं इसका रिकार्ड कही और नहीं मिलता पिछले महीने की' 12 तारीख का मामला है, सोनीपत में इडको फैक्टरी में जहां पर कि मजदूर हड़ताल पर थे, वहां के मालिक ने अपने 100 गुण्डों के सहारे मजदूरों पर हमला करवा दिया । मजदूरों की रहने की कालोनीज में जाकर उन गुण्डों ने लोगोंको मारा, उनकी औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया, एक आदमी मर भी गया, 20 जख्मी हुये और 70 के करीब जेल में बन्द कर दिये गये पर जो कातिल था, मिल का मालिक उसके खिलाफ कोई ओक्शन नहीं लिया गया, उस पर कोई मुकद्दमा नहीं बनाया गया । (विघ्न)

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मजदूरों के हक में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या इनको आंसू बहाने का अधिकार है? इससे मैं इन्कार नहीं करता कि वहां पर घटना घटी लेकिन यह मामला सब–जूडिस है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले पर बोलने के लिये उन्हें अला0 न किया जाए ।

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मामले की मैरिटस और डी–मैरिटस के बारे में नहीं कह रहा हूं । जहां तक ऐडमिनिस्टेरशन का ताल्लुक है मैंतो वह कह रहा हू । मैं कहना

चाहता हूं कि वहां पर 150 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया यह मामला कोई सब– जूडिस नहीं है ।

चौधरी लाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि जिस कांग्रेस सरकार ने झूंडों के पीछे मजदूरों की नसें काटी हों उसकी ये वकालत कर रहे हैं । उस सरकार ने मजदूरों का नाश कर दिया । (शोर एव विध्न)

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा इनको कन्ट्रोल में रखे इस तरह से तो मेरा टाइम जाया हो जाएगा । तो उपाध्यक्ष महोदय, उसी रोज सुबह दस बजे वहां से पुलिस हटा ली गई जोकि एक महीने से वहां पर बैठी थी ताकि मालिक गुंडों की मदद से मजदूरों का कत्ल कर सकें । जैसे मैंने बताया कि 150 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया और हमारे जो श्रम मन्त्री हरियाणा के हैं उनके आदमी उन मजदूरों की जगह भरती कर लिये गये । यह रिकार्ड की बात है मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूं । इसके अलावा सोनीपत ही अकेली जगह नहीं है, फरीदाबाद में भी मज दूरों पर मुकदमे बनाए गए, उनको पीटा गया । जो मालिक हैं उन्होंने सिक्योरिटी गार्डज के नाम पर बेशुमार गुंडे रखे हुए हैं जोकि बैड क्रैक्टर्ज हैं और उनके पास नानायज हथियार हैं । इसी तरह से हिसार टैक्सटाइल्ज मिल्ज में पिछले एक महीने से भूख हड़ताल चल रही है । वहां पर ट्रेड यूनियन के लीडरों को मजदूरों से मिलने नहीं दिया जाता । इसी तरह हिसार में जिन्दल फैक्ट्री में मजदूर कैपटिव तौर पर रखे हुए हैं उनको कारखाने से

बाहर नहीं जाने दिया जाता और अगर किसी को जरुरी काम के निए जाता होता है तो उरे वीर में पूरी गारद के साथ ले जाया जाता है । ये सारी बातें जनता पार्टी सरकार के राज में जोकि सरमायेदारों और कारखानेदारों की सरकार है और मजदूरों की दुशमन है, के टाइम में हो रही है । ला रैड आर्डर की स्थिति के बारे में सारे हरियाणा की पोजीशन आपको मालूम है जब से जनता सरकार आई है तब से कोई भी आदमी, कोई भी स्री और चाहे कोई भी बच्चा हो उसकी इज्जत महफूज नहीं है । रेशुमार चोरी, –कत्ल और हर तरह की वारदातें बइ गई हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं जबानी जाते नहीं कहना चाहता बल्कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, तीन मार्च को–

श्रीमती शान्ति देवी : क्या आप रिवासा कांड को भूल गए. (शोर एवं विघन)

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो गृह मन्त्री हैं उनको बताना चाहता हूं कि इसी महीने की तीन तारीख को बात है कि करनाल जिले के उगरा लेड़ी गांव में एक नौकूला खा नाम का गरीब तेली परम्परा के अनुसार वहां रह रहा है । उसका परिवार पिछले 50 साल से बीस किल्ले जमीन मुजारे के तौर पर काश्त करना आ पा है और अदालत से भी उसने बेदखली की स्टे ले रखी है लेकिन तीन मार्च को गुंडों ने तेली और उसकी बीबी तथा परिवार को तलवार तथा गंडासों से चपेटे' मारी । गुंडों के खिलाफ अभी तक कोई कार्य– वाही नही की गई । इस बात

का आम चर्चा है कि एक मन्त्री की इस केस में बड़ी भारी दिल–चस्पी है कि मुल्जमों के खिलाफ केस दर्ज न हो । यह कोई एक ही उदाहरण नहीं है बल्कि ऐसे अनेकों उदाहरणे हैं । ऐसे ही 28 नवम्बर 1977 को थाना हांसी के सौरखी गांव के हरिजन नौजवान को करनाल के थाना उरलाना में लाकर कत्ल. कर दिया गया । बाद में यह केस बनाया गया कि उसने पुलिस से मुकाबिल। किया । जब उतने जवान के बाप ने शोर मचाया तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया । इस तरह की मिसालें सैकड़ों की तादाद में दी जा सकती है।

आज यह सरकार सिविल लिबर्टी की बड़ी भारी बाते करती हैं । आपको पता है कि पिछले दिनों आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों को किस तरह से इस जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने पीटा और लाठी चार्ज किया । उससे पहले हमारी असैबली बिल्डिग के सामने हरियाणा के व्यापारियों पर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ और उनको किस तरह से विक्टेमाइज किया गया यह सब आपको मालूम है । इसी तरह से हमारे जो दूसरे तबके हैं चाहे वे मजदूरों के हैं या शहर 'के दूसरे तबके हैं उन सबका इस सरकार ने पुलिस के जरियें दमन करने का तहैया किया हुआ है और लोगो के खिलाफ झूठे मुकदमें बना कर पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है । हजारों की तादाद में सरकारी कर्मचारियों तथा कांग्रेसियों के मकानों पर छापे मार कर यह सारी बाते की गई हैं । इस सरकार ने अपने विरोधियों के खिलाफ जो

मुकद्दमें बनाये और मकानों की तानाशियां करवाई उसमें कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे मुकद्दमा बन सके और इसी बिनाह परवे लोग अदालतों से बरी हुए । इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय,' एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति के खिलाफ पंखा और आइस बाक्स की चोरी करने का मुकद्दमा बनाया गंदा । यह तो उसी तरह के मुकद्दमें हैं जैसे अंग्रेजों के राज में जूती और लोटे की चोरी के मुकदमें बनाये जाते थे । शिव कुमार के बाप को थाने मे बुला कर मारा गया । तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार सियासी बिनाह पर ऐसे मुकद्दमें बना रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने का वचन दिया था कि जो कमेटियां हैं उनके चुनाव करवाए जाएंगे । लेकिन आठ महीने गुजरने के बाद भी उनके वायदे वायदे ही रह गये हैं । आज जितने भी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, पंचायतें हैं या पंचायतें समितियां हैं या जो कोप्राप्रेटिव के सारे अदारे हैं इन सब में नौमिनेशन हो रहा है या हो चुका हे । किसी भी अदारे का चुनाव नहीं करवाया जा रहा है । इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार का नारा दिया है उसकी तरफ मैं आपके द्वारा हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस सरकार ने श्री राम शर्मा कमेटी किस तरह से बनाई और किस तरह से उसको तोडा गया और फिर किस तरह से उसको बनाया गया । आज हरियाणा मे इन पर किसी को भी विश्वास नहीं है । ये सियासी तौर पर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना

चाहते हैं । जब उस कमेटी ने इनके खिलाफ और इनकी पार्टी के औहदेदारों के खिलाफ शिकायत की तो उस कमेटी को तोड दिया गया और बाद में हमारी विधान सभा के जो माननीय सदस्य उसमें थे उनको' हटा कर श्री राम शर्मा जी की अध्यक्षता में एक विजीलैस कमेटी बनाई । इनको पता है कि शर्मा जी की उमर ज्यादा है और वे बेचारे इतना ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे इसलिये इन्होंने उनको फिर यह काम सोप दिया । इन्हेंने बताया कि पब्लिक लाईफ से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये बड़े जोत से कदम उठाये जा रहे हैलेकिन दूसरी तरफ इम्प्रूवमैंट ट्रस्टस हैं जिनको डाक्टर मंगलं सैन और इनकी पार्टी भ्रष्टाचार के अड्डे बताती थी लेकिन आज वे मन्त्री बन गए हूँ और आज उनमें सारे संधियों को चेयरमैन और मैंबर बना लिया गया है । बी0 एम0 डी0 जाँ 'नोने सोच करके इनको सारे के मारे ट्रस्टों का चेयरमैन और मैंबर बना दिया है उपाध्यक्ष महोदय आज इन इम्प्रूमेट ट्रस्टों में बड़ी भारी करपशन चल रहीहै आज जो

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : उपाध्यक्ष महोदय यह गलत बात कह रहे हैं ।

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाना में इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों के चेयरमैन और मैंबर बनाना यह बजाते–खुद करप्शन है और दूसरी कोई बात नही है । ये सारी बातें हो रही हैं । दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक लाईफ को

श्री उपाध्यक्ष : आप बजट पर ही बोले पार्टीज की बात न करे ।

कंवर रामपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है कि बोलने के लिये कोई समय निर्धारित किया जाए क्योकि सभी मैंबरो ने बोलना है । क्या आप सब को बराबर समय देंगे या लीडर के हिसाब से देंगे । इनको बोलते हुए पौना घन्टा हो गया है ।

श्री शमशेर सिंह : मैं तो बतौर मैंबर के बोल रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन बजट पर बहस चलेगी, अगर मेरे भाई मुझे कहने का समय देंगे तो मैं अपनी बात जल्दी ही खम कर लूंगा । मैं कह रहा या कि पब्लिक लाईफ को जाता पार्टी ने बेईमानी. से, कुरपशन से वीशियस करने का जो काम शुरू कर रखा है, यह बन्द किया जाए और आफिस आफ प्रौफिट एम0 एल0 एज0 को न दिए जाएं । एक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पांच विधायक हैं जिनको कारपोरेशनज और बोर्न के चेयरमैन बनाया गया । यह बेईमानी की बात है और रिकार्ड की बातें है । क्या सरकार का यही इखनाफ है? डिप्टी स्पीकर साहब, एक के0 बी0 दत्ता हैं जो बदनाम आदमी है लेकिन उनको हरियाणा ऐक्सपोर्ट कार्पोरेशन का चेयरमैन लगाया और यह काम डा0 मंगल सैन की सरकार ने किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : जो आदमी हाउस में अपने आपको डिफैड नहीं कर सकता, आप उसका नाम न ले । Particularly his name should not be mentioned.

श्री शमशेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिन का मैंने नाम लिया है, ये एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के चेयरमैन है । इन्होंने जब अपनी कैबिनेट बनाई तौ उनके आफिस पर 50 हजार रुपये खर्च किर, 35 हजार रुपये की नयी कार ली, और भी बड़े बड़े घपले किए । यह बड़ी बेशर्मी की बाने' हैं जो सरकार कर रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, आपको मैमोरैडम मिला होगा लेकिन मुझे नहीं पता इनको इस मैमोरैंडन के बारे में कुछ सुनाई दिया या नही दिया । इस तरह से, कुरप्ट लोगों को, जो बदनाम आदमी' हैं, उनको हरियाणा सरकार चेयरमैन या एम0 डी0 बनाकर खजाने का पैसा बरबाद कर रही है, यह सरकार के गलत कामों का एक दूसरा उदाहरण है ।

उपाध्यक्ष महोदय, चार रोज पहले, जब हाउस में मेरे– भाई श्री मांगे राम जी बोल रहे थे तो डा0 साहब और मुख्य मंत्री जी ने उनको जबरदस्ती बार बार बैठाने की कोशिश की । उन्होने इस बात का दावा किया कि हरियाणा सरकार तहसीलदार और अफसरों की मार्फत चंदा, फंड स्वाल– सेविंग का रुपया किसी सूरत में इकटठा नही रही । मैं आपकी मार्फत इस सरकार को नाम और तारीख बता कर उदाहरण देना चाहता हूं कि किन–किन लोगों मै चंदे के नाम ग्र, फण्ड के नाम पर, स्माल सेविंग के नाम

पर पैसा एकट्ठा किया । सरकार का यह दावा बिल्कुल झूठा है, सरकार ने हरियाणा में लाखों रुपये के टारगेट फिक्स किए हैं कि एक एक तहसीलदार, एक एक अफसर इतना इतना पैसा इकट्ठा करेगा । पटवारियों के द्वारा, ई0 टी0 ओ0 के द्वारा, इन्सेक्टरों के द्वारा लोगों पर नाजायज दबाव डाल कर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है । जिन लोगों के मुकद्दमें अदालत में चल. रहे हैं उन से चन्दा लेकर मुकद्दमों का फैसला उनके हक में किया । मैं उन केसिज के नाम बताने चला हूं ।. (व्यवधान)

वित्त मत्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : जिन से पैसा लिया है वे मुकद्दमें बताएं, इसी हाउस में बताएं, हम चौलेंज करते हैं, यह गलत बात है । ऐलीगेशन तो आपने लगाए हैं, मुकद्दमें भी बताएं (व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह : तहसील नरवाना को स्माल–सेविंग का 75 लाख का टारगेट दिया गया है. (व्यवधान) मैं नाम बता0ंगा, अगर नहीं बता0ंगा तो आपके सामने खड़ा नही रहूंगा । एक रोज नरवाना के पोस्ट आफिस में 27–28 फरवरी को, अढ़ाई लाख रुपया, व्यापारियों पर नाजायज दबाव डाल कर ई0टी.0ओ0 ने जमा करवाया और 1 मार्च को अढाई लाख रुपया निकलवा लिया । इसके साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार नरवाना ने रजिस्ट्री इन्तकाल करते समय, स्माल सेविंग में जो रुपया जमा करवाया, जिस आदमी से रुपया लिया उसका नाम है भगवानदास सपुन श्री राजा राम, बुडैन है । 31 जनवरी, 1978 को

इनसे 500 रुपया चंदा जमा करवाकर इन्तकाल न किया । नहीं तो यह कहा था कि रजिस्ट्री फेंक दी जायेगी । दूसरे आदमी हैं बासूराम, उचाना खुर्द । इनसे 12 जनवरी को 200 रुपये लेकर के रजिस्ट्री की । तीसरे व्यक्ति हैरेडू खानपुर । इनके पास 500 रुपया देने के लिए नही था और यह रुपया खडियाराम ने अपनी जेब से जमा करवाया । इस गरीब ने 500 रुपये के एवज में 100 रुपया जमा करवाया । चौथ हैं श्री बनबारी., सकना 'बिठमडा । इन्होंने एक भार रुपया रहन की रजिस्ट्री करवाने के लिए दिया । इस तरह सरकार. ने चंदे के रूप में लोगों से नाजायज पैसा इकट्ठा किया । अब मैं मुकद्दमों का नाम लेने चला हूं । चतरा बनाम समाकौर, उचाना खुर्द द्रुरुस्ती गिरदावरी', इसका फैसला 3 मार्च को हुआ । 3 मार्च, 197 हु को 500 रुपया लेने का वायदा करके फैसला किया । दूसरा केस है जग्गा अमर सिंह बनाम कासी । इनको कहा गया कि 5 हजार रुपया जमा करवाओ तब इन्तकाल हो सकता है नही तो रजिस्ट्री फैक दी जाएगी । तीसरा केस है कुलेक्टर अग्रेरियन नरवाना सरकार बनाम तेलू पुत्र कुन्दन, सकना मटौर, सरप्लस केस । इस केस न फैसला तब हुआ जब एक ह गार का फिक्स डिपोजिट, डाकखाने में जमा कर गया । यह मुकद्दमा है । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रिश्वतकी बात नहीं की, चंदे की बात की है । यह सरकार जबरदस्ती मुकद्दमे के नाम पर फण्ड जमा करवाकर फैसला करती है । (घंटी) मैं एक दो मिनट में ही खत्म करता हूं । मैं सरकार के भ्रष्टाचार कीऔर कछ मिसाले दे सकता हूं, अगर आप मुझे टाईम देंगे । फरीदाबाद में

केपरीवाल एक कारखानेदार है । इन्होंने मुख्य मन्त्री के नाप का ठेका ले रखा और खुल्लमखुल्ला लोगों के काम करवाता है । श्र कनु का पता सारे फरीबाद को है, इन्होंने काम करवाने का ठेका ले रखा है, सरेआम काम करवाता है । डिप्टी स्पीकर साहब, जब हम गै बता दिया है और सरकार मो नोटिस में ला दिया है तो आज के बाद हम देखेंगे कि सरकार उसका क्या इन्तजाम करती है । इसके अलावा मुख्य मन्त्री के एक रिश्तेदार डी0 सी0 हैं । उनको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाने की योजना है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या स्कीम है, क्या इरादे हैं, सरकार पब्लिक लाईफ से कुरपशन को किस तरह खत्म करना चाहती है । इसके बाद सरकर के जो सरकारी अफसर चीफ सैक्रेटरी से लेकर नीचे तक के हैं और जो हमारे भाई यहां एम0 एल0 ए0 साहेबान बैठे हैं, इनका काम है ऐडवाईज करना बहु इनका स्टैचुटरी फंक्शन है । अलग से ऐडवाईजर अप्वांयट करने की क्या जरूरत है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी जो ऐग्जैक्टिव है, जो हार्डली क्वालिफाईड हैं, टेरड हैं, उन से सरकार किस किस्म का काम लेना चाहती है? क्या ये ऐडवाइजर नहीं हैं? क्या डा0 मंगल सैन या दूसरे चौधरी साहब पुलिटिकल सर के ऐडवाइजर नही हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि आप इनको डीमोरेलाइक करना चाहते हैं, सरकार डींमोरेलाइज करना चाहती है । पुलिटिकल और एग्जैक्टिव ढांचे को सरकार तोड़ना चाहती है । उपाध्यक्ष महोदय, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ऐक्सपीरिएंस नही है वे

पुलिस के ऐडवाइजर हैं । कितनी अजीब बात है! जो व्यक्ति एस0 पी0 रहा है आज वही आई0 जी0 को ऐडवाइज करेगा और जो एस0 ई0 (नहर) है वह चीफ इंजीनियर को ऐडवाईज करेगा । यह तो ठीक है । लेकिन सरकार ने जिस तरह से सारी ऐडमिनिस्ट्रेशन का मजाक उड़ाया है, उसका कोई जवाब नहीं है । (घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाइल्ड अप करके एक मिनट में बैठता हूं । मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और यह कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, यह सरकार के खिलाफ कोई द्वेष की बात नहीं है, यह एक फैक्ट है कि आज हरियाणा सरकार का हरियाणा की जनता में कोई इम्पैक्ट नहीं है, आज हरियाणा की जनता को यह पता नहीं है कि इस सरकार में किसको अधिकार है, इस सरकार मे किसका हुक्म चलता है यह कैसे फंक्शन करती है? इसलिए मैं यह कह सकता हूंकि यह सरकार पैरेलाइज्ड है । आज हरियाणा में ऐडमिनिस्ट्रेशन. नाम की कोई चीज नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, बितनै डिवैल्पमैंट के काम थे वे सारे के सारे स्टैन्ड–स्टिल ही नहीं हैं बल्कि खराब हो रहे हैं । जौ सड़के टूट चुकी थी वे बन नहीं रही. हैं, जो और काम थे वे भी नहीं हो रहे हैं । आज चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे हरिजन हैं, चाहे गरीब है, हर तबके को सख्त मायूसी हुई है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, एक वार्निग के साथ मैं कथना स्थान लूंगा कि अभी भी टाईम है, अमी भी वक्त है, अमी भी सिर के पर से पानी नहीं

गुजरा है आप संभल जाएं । अगर मुख्य मन्त्री जी समझते है कि उनके मंत्री ठीक नही है तो इन मंत्रियों के इस तरफ और उस तरफ बहुत से काबिल आदमी बैठे हैं उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और अगर इनको जरूरत हो तो टैमरेरी तोर पर, पर्मानैंट तौर पर रो नहीं, चौधरी पोहलू को भी हम दे सकते हैं ताकि हरियाणा की सरकार ठीक ढग से चले । (हंसी) इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने केलिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : कंवर राम पात्र सिंह ।

कामरेड शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नर के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने के लिए चार दिन का समय है, आप अवश्य बोल लेना ।

कामरेड शंकर लाल : दूसरे दिन भी मुझे नही बोलने दिया गया, तीसरे दिन भी नही बलिंने दिया गया । मेरे पर पता नही क्या नाराजगी है? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बार समय बांट कर दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए । कंवर राम पाल सिंह ।

कंवर राम पाल सिंह (घरौंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच के पर मेरे अपो– जिशन के साथी शमशेर सिंह जी ने कुछ बातें हाउस में रखी हैं लेकिन इस सरकार ने जनता की भलाई के लिए, अच्छे कामो के लिए जो प्रोविजन रखे हैं या कोई अच्छे कदम उठाये हैं उनकी सराहना में एक लफज भी नहीं कहा । मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया । अपोजिशन का, उपाध्यक्ष महोदय, यह मतलब नही होता कि सरकार के अच्छे कामों को भी वह क्रिटिसाईज करे । इन भाइयों से मैं यह प्रार्थना करूँगा कि ये ऐसे अच्छे कामों की सराहना भी किया करे । जो क्रिटिसिज्म ये करते हैं उसके साथ साथ यदि ये कंस्ट्रक्टिव सजैशंज भी दें तो एक बहुत अच्छा माहौल पैदा होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर सबसे पहले पे क– पर सरकार ने इकनामिक प्रोग्राम, ऐग्रीकल्चर में सुधार और अनएम्पलायमैंट को दूर करने के बारे में जो कदम उठाए हैं उनका वर्णन किया है । गवर्नर ऐड्रैस में भी यह बात क्लीयर है और बजट स्पीच में भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब नेड्स बात को अच्छी तरह क्लीयरकिया हैकि ज्यों द्राई इस सरकार ने कार्यभार संभाला, कुदरत की तरफ से बड़ी आफत आ पढ़ी । फ्लड का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि फलड के अन्दर हरियाणा का कितना हिस्सा तबाह हुआ । उसके लिए सरकार ने कितने अच्छे अच्छे कदम उठाए । उन लोगों को रिलीफ देने के लिए कितने कष्ट हमने उठाए, मंत्री साहेबान ने, हमारी पार्टी के मैम्बर साहिबान ने और

दूसरे कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर किस तरह रिंग बन्धो पर काम किया, रिलीफ वर्क में हिस्सा लिया, उसका कोई जिक्र मेरे भाई ने नहीं किया । एक लफज भी इस बारे में उन्होंने नही कहा । (विध्न)

उपाध्यक्ष महोदय. कमीशनों की बात इन्हेने बड़े जोर से कही । इन्होंने कहा कि सस्कार कमीशंज के पर बहूत पैसा खर्च कर रही है लेकिन रिवासा कांड के पर जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उनके बारे में उन्होंने कुछ नही कहा । इन्होंने यह नही कहा कि सरकार ने एक कमीशन बिठाया जिसने दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने लाकर रखा है । कमीशन ने बड़े साफ लफजों में यह बात लोगों के मामने रखी है कि पुरानी सरकार के समय मैं किम किस्म की गलत से गलत बातें की गई । इमके बारे में मेरे भाई ने यह नही कहा कि यह सरकार ने बहत अच्छा काम किया है । सरकार की इस बात की, कि ऐसे गलत काम करने वाले सरकारी कर्मचारी या उमके सहयोगी के खिलाफ मुकद्दमें चलाए जाएंगे, और सजा दी जाएगी, भी इन्होंने सराहना नहीं की । (विध्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं फिर फलड की तरफ आता हूं । जैसा मैंने पहले अर्ज किया फ्लड के बारे में सरकार ने जो काम किया है और आगे इस बजट के अन्दर फ्लडज को रोकने केलिये सरकार ने जो बजट का काफी बड़ा हिस्सा ररवा है, उसकी कोई सराहना नहीं की गई । यह बात यहां अवश्य को जानी

चाहिए थी. । उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सरकार के नोटिस में अवश्य लाना चाहता हूं कि फ्लड रोकने के लिए जो काम किया जा रहा है वह बड़ी स्लो–स्पीड से चल रहा है जबकि बरसात का सीजन आने में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है । सिर्फ दोतीन महीने बाकी हैं । जून के लास्ट में और जुलाई के शुरू में बरसात आरम्भ हो जाती है । एक बात और मैं सरकार के ध्यान लाना चाहता हूं । इस दफा तो गुड़गांव और सोनीपत का इलाका तबाह हुआ है लेकिन अगली दफा करनाल की भी बारी आ सकती है । इस सम्बन्ध में मैं ड्रेनेज महकमे को दो चिट्ठियां लिख चुका हू कि जमुना की तरफ खास ध्यान दिया जाए । इस बार बरसात मैं जमुना ने जो अपना रुख बदला है, उसके कारण इसने लगभग 6 सौ 7 सौ एकड जमीन को इरोजन कर लिया है, खड़ी फसलें तबाह हुई हैं और पुरानी तथा नई जमुना का मेल होने में केवल अढ़ाई–तीन किल्ले और कई जगह पांच–छ किल्ले का फासला रह गया है । मेरी इत्तलाह के मुताबिक वहां कुछ लेबर गई थी, कुछ पत्थर भी फैकने शुरू हुए थे लेकिन अब ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है । पता नहीं सरकार ने उस लेबर को वापस बुला लिया है और मैटिरियल भेजना भी बंद कर दिया है पता नहीं क्या बात है? इसलिए मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि यदि अमी से जमुना का प्रबन्ध न किया गया तो इस साल तो हम सोनीपत और गुड़गांव के बारे में सोच रहे है, अगले साल करनाल का एरिया भी तबाह हो जाएगा । इससे जहां जनता को नुकसान होगा वहां सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी । वहां एक

डाईवर्शन यदि इस तरह की आ गई त ओं उस डाईवर्शन को बदलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ यू 0 पी0 वालों ने अपनी साईड पत्थर से पक्की कर दी है । पानी उधर नहीं जा सकता । पानी हमेशा उधर जाता है जिधर उसको कच्ची जमीन मिले और कटाव कर सके । ड्रेनेज के बारे में मैंने एक सवाल भी दिया था लेकिन मैं उसे पुट नहीं कर सका । उसके बारे में भी मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो जवाब मुझे मिला है उसे मैं समझ नहीं पाया । वह ड्रेन 'पी' ड्रेन के नाम से मशहूर है । मइकमें ने जवाब दिया है कि वह पूरी तो हो चुकी है लेकिन सफाई का काम बाकी है । इस बारे में मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब भी उन्हें समय मिले वे मेरे साथ चलें । मैं उन्हें दिखा दूंगा कि वहां कोई काम नहीं हुआ है । कम्पलिशन तो क्या । खुदाई का काम भी नही हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में सवालों के जवाब में यहां काफी जिक आया और बड़ा क्लीयर जवाब मन्त्री महोदय की तरफ से हाउस के सामने आयाथा । मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे की कमी होते हुए भी सड़कों की तरफ काफी ध्यान दिया गया है । लेकिन मैं सरकार से यह दरख्वास्त जरूर करूंगा कि जिस तरह से अब तक सउको के बनाने में उन्होंने एक दो जिलों की तरफ खास ध्यान दिया है । इस बार तो जो हो गया सो हो गधा लेकिन आइन्दा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सड़कों का अगरने– साल जे'।. भी' बजट बनाना हैं, उसमें बैकवर्ड

एरिया का खास ध्यान रखे । मिनिस्टर साहब ने भीं यहा कहा है कि हम सब के बराबर लाना चाहते हें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं फरना चाहते । जो भी बैकवर्ड एरिया हैं । उनके बराबर लाना चाहते हैं । अगले साल जो यहां हाउस में बजट आए, उसमें बैकवर्ड एरिया मं दो या तीन परसैन्ट सड्कों पर फालतू खर्च करना चाहिए । वहा पर भी रें किलोमीटर सड़के फालतू बननी चाहिए, लेकिन जे । दूसरे इला के है, उसका आप बिस्कूल ता महरूम ना करें । डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके जरिए सदन में यह भो सुजैशन दूंगा कि जा स्पैशली' ऐर्से रोडज हैं, जो दो–दो था तीन–तीन मील के लिंक रोड़ हैं, उनको पहले बनाया जाना चाहिए। बजट स्पीच मैं कहा तो न गया है सि ऐसे रोडज के प्रैफेन्स दी जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और तहसील हैड–क्वर्टरज पर जाने के लिए लोगों को काफी सतर तब करना पड़ता हैं, लेकिन मैं मन्त्री महोदय के नोटिस में खासतौर से यह बात नाना चाहता है कि जब. मेरे अपने हल्से में ऐसी हालत है, तो हो सकता है दूसरे हल्कों में भी यही हालत हो । अगर दो दो तीन तीन किलोमीटर की लिंक रोडज बना दो जाएं तो लोगों को 15–2 0 किलोमीटर का सफर न करना पड़ेगा । उस सफर से वे बच जाएंगे ।

डिप्टी सोकर साहब अबमैं एजुकेशन के बारे में एक दो बात कहूंगा । एजुकेशन डिपार्टमैंट में एक ही आदमी ने उसकी एडमिनिसेशन भी सम्भाली हुई है और उसका सुपर विजन भी वही

करे रहा है । इन दोनों कामों का एजुकेशन महकमा पूरी तरह से इन्तजाम नही कर पा पा है । जिस तरह से बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, फैसेलिटीज मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं । मैं सरकार आपके जरिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि सुपर– विजन और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग कर दी जाएं ।

अब मैं बिजली बोर्ड के वित में भी कुछ कहना चाहता हू । मेरी तरफ अभी से मैंबरान ने इशारा शुरू कर दिया है लेकिन जब **चौधरी** शमशेर सिंह जी बोल रहे थे, तब किसी ने कोई इशारा नहीं किया। मुझे तो बोलते हुए अभी पांच मिनट ही हुए हैं, अभी से आपने बैठने का इशारा शुरू कर दिया । बिजली के बारे में यहां मुख्य मन्त्री महोदय ने गवर्नर साहब के एड्रैस पर एलान किया था कि बिजली के फलैट रेट्स किए जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि बिजली बोर्ड के कुछ इंजौंनियर्ज उनसे पूरी तरह से सहमत नही हैं । उनका म्यू है कि यह ठोक नही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका ऐसा व्यू क्यों बना हुआ है । मैं आपके जरिए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि फ्लैट रेटस का जो ऐलान किया है, उसको जल्दी से जल्दी लागू करें और इजीनियर्ज की बातों की ओर ध्यान न दें । मेरी दूसरी सुजैशन यह भी है और मुझे खादशा हो रहा हए कि अगर फलैट रेट्स हो भी जाए, तो कल को बिजली वाले ऐसा न करदें कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा बिजली देनी शुरू कर दें और गांवों के लोगों को जो लाइन जाती हैं उनको पीछे से बन्द कर दे । बिजली वाले यह कहना शुरू कर

दें कि पीछे से सप्लाई पूरी नहीं आ रही हैतो इसलिए बेचारे गरीब किमान की जरूरत को पूरा करने के लिए पावर के मिनिमम आवर फिक्स करें, जिस तरह से फलैट रेट्स फिक्स हो कि इतने पैसे देने पड़ेंगे । इसी तप से मिनिमम आयर भी फिक्स करने पडेंगे कि किसान को इतने घंटे बिजली देंगे । अगर हाता या दो–दो हफ्ता लाइन ही बन्द करदे और किसान से पैसा ले लिया जाए, तो इससे बड़ी परेशानी होगी । ऐसा नही होना चाहिए । जिस प्रकार से किसान को मीटर रीडर से, बिल कलर्क से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वे उनको दूसरे फंदे में न फंसा दें । बिजली को बन्द कर दें और गरीब किसानों को पैसा पूरा का पूरा देना पड़े । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा । फ्लैट रेट लागू करने से पहले इन चीजों के बारे में फैसला अवश्य कर लिया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, शूगर केन की कीमतों के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है । कल भी मिनिस्टर साहब ने काफी लम्बी स्टेटमेंट हाउस में दी है । उन्होंने यहां हाउस में बताया है कि मिल मालिकों को शुगर की प्राइस घटने के कारण गन्ने के रेट्स घटाने पड़ रहे हैं । सन 1962– 63 में भी यही देखा गया था । उस टाईम पर पंजाब सरकार होती थी । इसी सरस्वती मिल के जब घाटा पड़ा था तो गवर्नमैंट ने उसके सबसिडी दी थी लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब चीनी की कीमते बढ़ जाती हैं, तो क्या ग्रोअर को, मिल मालिक अपने

प्रोफिट में से कुछ पैसा देते है, या कभी सरकार नेरू दिलाया है? अब हमारी सरकार की तरफ से स्टेटमैंट आई है कि मिल मालिकों को राजी किया जा पा है कि वे किसानों को 13.50 रुपए क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट दें । सरकार लेवी शुगर की प्राइस बढ़ाकर मिल मालिकों को खुश करना चाहती है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट को और शुगर मिल के मालिकों को सरकार हर तरह से खुश करना चाहती है । उनको हर प्रकार के घाटे से बचाने की कोशिश कर पी है । क्या सरकार ने कभी किसानों के लिए भी सोचा है? मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से किसानों की सरकार कही जाती है, किसानों का भला करने के लिए बनी है तो उनका भला होना चाहिए । फर्टीलाइजर की कीमों बढ़ी यानी पहले से डबल हो गई । अगर वे घटाई गई तो कभी दो परसैन्ट कम हुई, तो कभी आया परसैन्ट कम हुई । इस रेशो के हिसाब से कीमते घटीं । इसी हिसाब से किसानों को खुश किया जा रहा है । दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों पर सेल्स टैक्स– 1 5 परसैन्ट बढ़ा, तो उनको एकदम से 5 परमैन्ट कर दिया गया । उनकी यूनियन है, प्लेटफार्म है, प्रैस है, वे एजीटेशन कर सकते हैं लेकिन किसान के पास कोई भी चीक नहीं है न यूनियन है, न प्लेटफार्म है, न कुछ और है । उसके पास तो केवन विधायक हैं, जो जनता ने या उन्होंने चुन कर भेजे हैं । विधायको का यह कह कर कि वे उनका पूरी तप से साथ दें । हमारी सरकार. ने अपने बजट के अंदर टैक्स लगाए हैं, रक

तरफ तों यहां कहा गया है कि किसान सरकार की रीढ़ की हड्डी है दूसरी ओर सरकार उन पर टैक्स लगा रही है । उनके अन्नदाता कहा गया, क्ये को आगे बढ़ाने वाला कहा गया लेकिन साथ ही उनका गला जा रहा है । मैं अपनी सरकार से यह अर्ज करूंगा कि वह जो आवयाना बड़ा है, पैसेन्जर टैकस बढ़ा है, यह सब गरीब किसानो पर बढा है । बसो के अंदर गरीब किसान सफर करता है । कोई भी बढा आदमी अफत इंडस्ट्रियलिस्ट तो वो कार में चलता है, बस में कोई नहीं चलता है । बस में तो शरीर किसान और मजदूर चलता है । यह टैक्स किस पर लगा? गरीब किसान और मजदूर पर लगा आबयाना किस पर बड़ा? किसान पर बढ़ा । अगर किसी फैक्ट्री पर टैक्स बढ़ता है तो फौरन रेट्स बड़ा दिए जाते है । जिस रेशेय से टैक्स बढ़ते हैं, उससे भी ज्यादा भाव बढ़ा दिए जाते हैं. लेकिन किसान की चीजों– की कीमते नहीं बढ्ती हैं, वे यों की यों ही रहती हैं । एक कुम्हार भी अपने बरतन बेचता. है, तो वहू भीं कीमत लगाकर बेचता है, परन्तु किसान अपनी पैदावार की ढेरी लगाकर रख देता है उसका भाव भी कोई और ही करता है । किसान की चीजों की कीमतें फिक्स कर दी जाती हैं, क्योंकि वह तो दूसरों के भरो–से पर है । म डी' में कीमत किसी और ने लगानी है । जिस साल बम्पर क्रॉप हो जाती है तो आठ–आठ और दस–दस दिन तक मंडी में फसल यों की यों पड़ी रहती है ।

किसानों पर टैक्स लाया गया है इस पर दुबारा गौर किया जाना चाहिए, उसके न मारा जाए, । उसके लिए न कोई प्रैस. है और न ही कोई प्लेटफाम' है–, जिससे वे कुछ कह सके । न बेचारे किसी प्रकार का एजीटेशन कर सकते हैं । उन्होंने तो इस सदन में मैंबर्ज भेजे हुए हैं । अगर वे कुछ करना चाहते हैं, तो मैं सरकारे से प्रार्थना करूंगा कि इस टैक्स को वापिस लिया जाये । इन शब्दो के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपने मुझे बोलने के कितु टाईम दियॉ ।

श्रीमती शान्ति देवी (कलियाना) : डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को बधाई .देना चाहती हूं कि उन्होंने 97 स्कूलों को प्राइमरी से मिडल बनाया है और 29 स्कूलों को मिडल से हाई बनाया है । लेकिन इस बजट कौ देखने से पता लगता है कि सब से कम पैसा सरकार ने एजुकेशन विभाग को दिया गया है । मेरी सरकार से अपील है कि जैस कि पिछल दिनों हरियाणा में बाढ़ आयी, उसमें हमारे हरियाणा के कि किसान बरगद हो गयें लेकिन साथ ही उस बाढ़ का प्रभाव स्कूलों की बिल्डिगों पर भी पड़ा है । हमारे स्कूलों की बिल्डिगे जिसमें हमारे बच्चे बैठते हैं, वे भी तहस नहस हो गई हैं । आज के दिन उनकी मुरम्मत का भी हमारे सामने एक अहम सवाल है । इन हालातों को देखते हुए एजुकेशन विभाग को और अधिक पैसा मिलना चाहिए था ।

दूसरे मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी कहना चाहती हूं । इस बजट स्पीच के अन्दर और इस विधान सभा के अन्दर एक शब्द भी उनके बारे में भी. सदस्य ने नहीं कहा हैं । कभी यह जनता सरकार इस भूल में हो. कि सरकारी कर्म–चारियों का उसमें कुछ भी योगदान नहीं है याँ कम था, यह बा त हमें दिमाग से बिलकुल निकाल देनी चाहिए । हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को' एक किस्त बड़ी रेग कर दी है । हमारें प्रान्त में सब स्टेट्स वेय बाद यह किस्त दी गई है और वह भी सितम्बर की बजाए जनवरी से दी एं । मैं आपके जरिए सरकार से पुरजोर अपील करुगी कि हरियाणा सरकार को भी उसी तज से किस्त देनी चाहिएं जिस प्रकार से हमारे पड़ौसी प्रान्त पंजाब और हिमाचल ने सितम्बर के महीने से दी है दूसरी बात मैं कर्मचारियों के विषय में यह भी कहना चाहते। हूं कि कितने दिनों से हरियाणा सरकार का कर्मचारी यह देख रहा है क हमारे ग्रेड रिवाइज किये जायेगे । केन्द्रीय सरका र ने तीसरा पे–कमीशन सन् 1974 में लागू किया था परन्तु मैं इस सरकार से यह कहना चाहती हू कि शायद यह बिल्कुल ही आँखें मूंद गयी है । इस सरकार को ध्यान ही नहीं आता है कि सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ देना है, उसका भी कुछ देय है । इसी–लिये मैं अपनी सरकार से. यह अपेक्षा रखी हूं कि इस जनता सरकार के उन. कर्मचारियों कें इतने बडे योगदान को भूलना नहीं चाहिए और थर्ड पे–कमीशन तुरन्त लागू करना चाहिए दूसरी बात मैं किसानों के बारे में कहना चाहूंगी' । मैं यह बात मानती हूं कि. मेरी सरकार,

हमारे मुख्य मन्त्री महोदय वास्तव ये किसानों के और गरीब मजदूरों के रहबर हैं लेकिन क्या मैं सच्चाई के साथ यह पूछ सकती हूं कि 10 प्रतिशत का जो वाटर टैक्स इन्होंने किसानों के पर लगाया है क्या यह उसके साथ ज्यादती नही है? आज किसान जिसकी कोई यूनियन नही है, वह किसान जिसके लिये कोई लड़रू ने वाला नही है, उसके पर आप इस तरह से टैक्स बढ़ा रहे हे'।– इस सरकार ने पिछली दफा 15 प्रतिशत सेल्ज टैक्स के पर सरचार्ज बढ़ाया था, लेकिन बाद में घुटने टेक दिये और फिर उसे घटा कर 5 प्रतिशत करना पड़ रहा है । इसलिए मैं मुख्य मत्री महोदय से और इस सरकार से– यह उम्मीद रखूंगी कि वह पुरानी परम्परा को, पुरानी पद्धति को छोड़ करके जो भी निर्णय ले वह सोच–समझकर कर ले । यह जो किसानों और मजदूरो के पर 1 छ प्रतिशत वाटर टैक्स बढ़ाया गया है, इसके'। हम बिस्कूल बर्दाश्त नहीं करेंगे । यह जनता मंच से मैं कह रही हूं । इसके लिए मुझे कितना ही संघर्ष करना पड़े, कितना ही कुछ करना पड़े, मैं अगले कदम के बारे में भी सोच सकरी हू । लेकिन मैं यह बात यहां पर स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं इसको बिस्कूल भी बर्दाश्त नहीं करुंगी ।

अगली बात मैं बसों के बारे में कहूंगी । जैसे स्कूटर के पर भी टैक्स बढाया गया है मेरे पास गाडी नहीं है । मैंने एक स्कूटर जरूर लई लिया हए । तो' मुझे जब भी कहीं जाना होता है, उसका. गाम करती हू । गरीब, जिसके पास एक साइकिल है

उस बेचारे को कई–कई कोस पार करके जाना पडता है । बसों के पर भी टैक्स बढाया गया है, जिसके पर हमारा गरीब मत–तर बैठ कर जाता है । मैं अपनी सरका र से. यह कहूंगी कि पहली. सरकार कांग्रेस सरकार ने ते'।. उन गरीबों औंर मजदूरों पर जुल्म किया था और किराया दुगना बढ़ाया दिया था, लेकिन मेरी जनता सरकार को कम सेकम उन लोगों पर कुछ तो रहम करना चाहिए । मेरे विचार में जो बसों के पर टैक्स बढ़ाया गया है, इसका कोई औचित्य नही है और सरकार को इसे वापिस लेना चाहिए ।

इसके अलावा एक और बात मैं अपने ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब से आपके द्वारा कहना चाहूगी। हा0स में बड़ी बहस होती है और मेरा नम्बर नही आता, सवाल मैं पूछ नही पति एक बात के बारे में मैं सपष्ट निर्णय जानना कहूंगी और वह बास है शिक्षित बेरोजगारी के बारे में। मानती हूं कुछ ऐसा तबका है जो मौका फरोश है और अवसरवादी है, उन्होंने जब 1973 के अन्दर अध्यापक आन्दोलन हुआ तो उसका लाभ उठाकर भर्ती होना शुरु कर दिया । मेरी सरकार भी आज वही करना चाह रही है जो बंसी लाल करना चाहा करते थे । वह यह चाहते थे कि ये मेरे जो पिल्ले हैं जो मैंने पाले हैं, उनको मैं रैगुल्लर कर जा0ं लेकिन लोग मीसा में जेलों में गये मुसीबते सही, न मालूम कितनी–कितनी यातनाएं सहीं, कितने जुल्म सहे, घरों से बाहर चले गये घर से बेघर हे।. गये लेकिन उन अध्यापकों को रेगुल्लर नहीं होने दिया । मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगी कि वह

ऐसा कोई नियम बनायें कि जितने भी सैशनवाईज या जो आउट आफ जौब अध्यापक बैठे हैं उनको सैशन–वाईज रैगुलर किया जाये ताकि जब सरकार उनको ट्रेनिंग देती है, कई–कई हजार रुपया एक मैट्रिक पास और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रैजुएट की ओर निंग पर खर्च करती है किसी को साल लगता है तो किसी को दो साल लगते हैं लेकिन 1 1 साल से मेरे अध्यापक भाई आंखें फाड़–फाड़ कर देख रहे हैं कि वह दिन कब आयेगा जब मुझे भी रैगुलर सर्विस मिलेगी या– मैं भी सर्विस में आ जा0ंगा । कितना दुर्भाग्य है, मेरे देश के साथ–कितना खिलवाड है शिक्षा के साथ इस जनता सरकार में भी और आज तक इस जनता सरकार ने भी ऐसा कोई निर्णय नही लिया जिससे कि वे बेरोजगार भाई भी यह सोचे कि उनका भला भी यह सरकार सोच रही है । वे भाई सब का घूट पीये बैठे हैं कि कब वह दिन आयेगा जब जनता सरकार हमें संभालेगी? बंसी लाल सरकार ने त उन्हें एक तरफ करके रखा था । इसलिए अब उम्मीद करती हूं कि सत अनुसार यानी सैशन–वाईज, शिक्षा मन्त्री महोदय मेरी बात को समझ लें, उनको रैगुलर किया जाए, चाहे उनमें से एक सौ भाई रैगूलर हों या दो सौ रैगुलर हों लेकिन वह सब कर जायेगे इस बात से । अधिक न कहते हुए मैं आपसे एक बात ओर कहना चाहती हूं । जैसे **चौधरी** शमशेर सिंह जी कह रहै थे, हम उसका मजाक उड़ा रहे थे कि बंसी लाल बरबाद क्यों हुआ था । आप छपी अच्छी तरह से जानते हैं, वह इसलिए बरबाद हुआ क्योंकि वह सच्ची बात किसी की भी सुनना नहीं चाहता था । मैं मानती हूं कि जुल्म किए है, अत्याचार

किए हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी लेकिन अगर उन्होंने कोई कसर नही उठा रखी तों उसका अन्जाम भी ले लिया. है । अगर हम भी उसी के कदमों पर आगे बढ़ेंगे तक सच्ची बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो जनता हमें चार साल के बाद बकशेगी नहीं । वही मंच हमारे लिए भी तैयार होगा । इसलिए मैं चाहती हूं कि आप सब की बात सब के साथ सुनें । यह ठीक है कि सच्ची बात कडवी जरूर लगती है, लेकिन हमें सुननी चाहिए । ऐसी मेरी प्रार्थना है । धन्यवाद ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने बजट के पर आज बहस हो रही है । मैं इस पर कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हू । बजट के दो पहलू होते हैएक पहलू वह है जिस आईटम के पर खर्च किआ जाए और दूसरा पहलू यह होता है कि वह आमदनी किधर से आयेगी । कुल मिलाकर हम देखें तो यह बजट बड़ा सन्तोष जनक, सुखद और प्रशंसनीय है परन्तु जहां तक दों–एक बातों का सम्बन्ध है वह इसमें अगर न होती तो अच्छा होता । एक तो 10 प्रतिशत आबियाना जो बढ़ाए। है और दूसरे जो 1 0 प्रतिशत पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया है, पार्टी के अनुशासन में रहते हुए पार्टी में होने के नाते मैं इसकी पुरजोर ताईद करूंगा लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि जो एक–दो बाते मैं कहूंगा सरकार उनके बारे में जरूर सोचेगी । उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बजट के अन्दर 17 करोड़ रुपये का घाटा छोड़ दिया था । वह हमने पूरा किया और

फिर इस तरह से 26 89 करोड़ रुपये का घाटा हे । इसके अलावा हमने 100 करोड रुपया' जो अभी फलड की वजह से खर्च किया, वह भी इसमें शामिल है । 32 करे रुपया वह भी इसमें शामिल है जो नये विकास कार्यो पर लग रहा है । इस वजह से हम समझते हैं कि इतना घाटा हो रहा है लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, जो हमारे वित्त मन्त्री जी ने स्टेटमैंट दिया, उसके मुताबिक जो देहात के पर 7 0 प्रतिशत पैसा खर्च किया जायेगा, उसको देखते हुए मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह बजट कुल मिलाकर एक इएहाती बजट है और एक अच्छा बजट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातों पर खास तौर से बोलना चाहता हूं । एक तो जो दस प्रतिशत आबयाना बढाया गया है, उस पर और दूसरे जो' दस प्रतिशत पैसेन्जर टैक्स बचाया गया है, उसके'। किस तरह से मीट आउट करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, हम इस घाटे को सैन्ट्रल गवर्नमैंट से मदद लेकर पूरा करेंगे यह उसमें जोड़ा जा सकता है । जहां 20. 89 करोड़ रुपए का इस समय घाटा हुऐ उसके अन्दर यह 2 8 करोड़ का घाटा और जोड़ा जा सकता है और सैन्टर से मांग कर पूरा किया जा सकता है । दूसरी तरफ मैं यह बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हम रोज बसों से सफर करते हैं और हमारे कंडक्टर भाई कई दफा बिल्कुल टिकट नहीं काटते । अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे और यह कर दे कि जो कंडक्टर टिकट न काटे उसको सस्पैड न करके सख्त सजा दे,. तो ठीक रहे । अगर कोई

केस इस प्रकार का सरकार के नोटिस में आए, तो उस कंडक्टर को टरमिनेट कर दिया जाये ऐसा करने से जो एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह रुक सकेगा । जनता पार्टी के घोषणा पल के अन्दर भी था कि आने वाली सरकार यानी जनता सरकार सादगी का सबूत देगी ।

मिनिस्टर साहिबान माफ करेंगे आजकल रों–जाना जो पार्टियां हो पी हैं और हम भी उसके अन्दर शामिल होतें हैं और' उन पार्टियों में जो खर्चा होता है, वह सादगी का कोई अच्छा सबूत नहीं है । हमारे मिनिस्टर साहिबान सादगी का एक अच्छा नमूना पेश करें औरये पार्टियां बन्द होनी चाहिएं और हम फजूल के खर्च न करें । इस गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहूंगा । पिछले साल सारे हरियाणा के अन्दर जो बाढ़ आई औरपिछले सौ साल का रिकार्ड उस बाढ़ ने तोड़ दियाऔर उसके लिए हमारी सरकार ने जो कुछ किया उसकी मैं ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहता और न ही दुहराना चाहता हूं, क्योंकि बजट के अन्दर उसका पूरा विवरण है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाढ़ को रोकने के लिए जो 138 करोड़ रुपए की स्कीम जो एक मास्टर प्लान की शक्ल में है, यह एक बड़ा सराहनीय कदम है और मुझे उम्मीद है कि इसको बहुत जल्दी लागू करके किसान को बाढ़ से बचाया जा सकेगा ।

बजट के अन्दर कृषि को प्राथमिकता दी गई है । इससे साबित होता है कि हमारी सरकार ने जो वायदा किया था कि कृ

षि को प्राथमिकता दी जाएगी, देहातों को उठाया जाएगा,– उस दिशा में यह एक पहल है । इस बजट में जो 70 प्रतिशत सिंचाई ओर बिजली पर खर्च किया जाएगा उससे भी पता चलता है कि देहात के अन्दर, जब बजट पर पूरा लागू हो जाएगा, पूरी इनक्लाब आएगा । पिछली सरकार का कु ल बजट 148 करोड रुपए का था और इस सरकार ने '1 44 99 करोड़ केवल माल सिंचाई और बिजली पर खर्च करने के लिए प्रोविजन रखा है । इससे साबित होता हैं कि देहात की तरफ इस सरकार का विशेष ध्यान है । सरकार जो एक सौ स्प्रिकलर सैट्स लगाने जा रही है । इससे यह लाभ होगा कि जो 0ंचें–0ंचे टिब्बे हैं जहां पानी नहीं पहुंचता, वहां भी सिंचाई हो सकेगी ।

कृषि केबारे में मैं एक बात खासतौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे किसान की जिन्दगी के साथ जो तीस साल तक एक खिलवाड़ होता रहा वह खेल हम न करें और इसके लिए मैं सर्कार से अर्ज करूगा कि किसान की हर फसल के भाव पहले ही तय होने चाहिएं । उसे पता लगना चाहिए कि उसकी फसल का भाव क्या तय हुआ है ताकि उसके मुताबिक वह फसल बो सके। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसान की किसी भी उपज के पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए । यह सरकार से मेरी गुजारिश है । डिप्टी स्पीकर साहब, महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह ने कहा कि भारत का भविष्य देहात के भविष्य पर निर्भर करता हैऔर अगर हम देहात का भविष्य सही

मायनों में उज्जवल कर देंगे, तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन किसी भूखे को केवल नारे देने से बात नहीं बनती, उस भूखे को तो रोटी चाहिए । इसलिए मैं अपनी सरकार से जरूर गुजारिश करूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि किसान की फसल के भाव जरूर तय करने चाहिए और अगर मार्केट में भाव कम हो जाएं, तो सरकार इस पोजीशन में हो कि वह उन कमोडिटीज को खरीद सके, स्टोर कर सके । डिप्टी स्पीकर साहब, रोजगार के बारे में वित्त मन्त्री ने अपने बजट के अन्दर बताया है । यह बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने नौजवानों के नए नए रोजगार के नए–नए अवसर प्रदान करने के लिए जो हमारी औद्योगिक नीति है उसे पूर्णतया बदल दिया है और उन्होंने कहा है कि हम कुटीर उयोग और लघु उयोग की तरफ ध्यानदेंगे । चौधरी चरणसिंह ने कहा हैकि आर्थिक समस्या का समाधान एक मात यही है कि लधु उद्योग आरम्भ किए जाएं, और छोटे किसानों को पर उठाया जाए, लघु उद्योगों को इहातों में बढ़ाया जाए । इसमें कोई शक नही कि हम रोजगार को बढावा देगे और इस चालू वर्ष में हमारी सरकार 1 10 इंडस्ट्रियल यूनिट खोल रही है । मैं अपने महम इलाके के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वह इलाका पिछले तीस साल सेइग्नोर होता रहा है । वह गररूबि इलाका है । वहां के नौजवान इस काबिल नहीं है कि अपनी फैक्ट्री खुद लगा सके । सरकार से मेरा निवेदन है कि वहां विशेष तौर पर फैक्ट्री लगाई जाए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और उस इलाके से बेरोजगारी दूर हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा । शिक्षा में मूल परिवर्तन लाने के लिए हमारे बजट के अन्दर एक प्रोविजन है और उसमें यह कहा गया है कि 10+2+3 का फार्मूला है, या प्रणाली हे उसको लागू किया जा रहा है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय शिक्षा को बदलनेके लिए प्रणाली को बदलना जरूरी नही है । शिक्षा का अर्थ किताब नहींहै, बल्कि शिक्षक है, 'जब तक शिक्षक की हालत ठीक नहीं होगी, शिक्षा प्रणाली चाहे 10+2+3 वाली रखी जाए, या पहले वाली रखी जाए, अथवा कोई और प्रणाली रखी जाए, जब तक शिक्षक का स्तर, शिक्षक का सट्टेस ठीक ढंग से समाज के अन्दर नही होगा, कुछ नही हो पाएगा । जैसे पहले टीचर और टौट के सम्बन्ध होते थे, जो एक पाक रिलेशन होता था और जब तक वह रिलेशन नही होगा कोई बात बनने वाली नहीं है । वह रिलेशन कैसे कायम होगा, आप इस वात को सोचे । आज उनकी तनख्वाह में कितनी डिसपैरिटी है, कोई सिक्योरिटी आफ सर्विस नही है । रू पी. पैटन के ग्रपर वे टीचर मांग कर रहे हैं । जैसा कि श्रीमती शान्ति देवी ने कहा कि उन लोगों को पता ही नही है कि ओवर एज होने के एक दिन–पके भी वे नौकरी पा सकेंगे या नहीं । इन बातों को देरवते हुए शिक्षा के अन्दर मूल परिवर्तन तभी हो सकता है, जब शिक्क की ओर हम ध्यान दें उन विशेष बातों के लिए जैसे तनख्वाह मेडिस्परिटी है, सिक्योरिटी आफ सर्विस है और यू. पी. पैटर्न जो वे चाहते हैं ।

जहां तक ट्रांसफर पालिसी का सम्बन्ध है, उसके बारे में दो बातें माननीय शिक्षा मन्त्री के नोटिस में लाना चाहता हू कि ट्रांसफर के मामले में जो छरू स्टेशन्ज माने हैं, और उनके गांव के स्टेशन को अवाइड किया है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन छरू स्टेशन्ज में अपना गांव भी शामिल किया जाये और टैस्ट के तौर पर देखा जाये । अगर यह पालिसी कामयाब न हो, तो दो साल के बाद उसको तबदील कर दिया जाय । दूसरी बात यह है कि बहुत से टीचर पांच छरू साल एक स्टेशन पर रहते हैं और उसके बाद दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर करा लेते हैं, लेकिन हाउस रैन्टल एरिया वही बना रहता है सिर्फ स्टेशन. चेंज होता है और कई ऐसे टीचर्ज हैं जिन को हाउस रैन्ट कभी मिलता ही नहीं है और न ही उनको हाउस रैन्टल एरिया में तबदील किया जाता है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि एक आदमी को चार साल तक हाउस रैन्टल स्टेशन पर रखा जाए, और चार साल के बाद किसी दूसरे टीचर को जिसको हाउस रैन्ट नहीं मिलतां, वहां पर तबदील किया जाये ।

स्पोर्टस के बारे में कहा गया है । इसमें कोई शक नहीं कि स्पोर्ट एजुकेशन का एक इंटेगरल पार्ट है । किसी भी नेशन का करैक्टर प्ले ग्रा0ंड में बनता है । इस पर मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि रोहतक के अन्दर एक स्टेडियम बनाने का सरकार विचार करे, जिससे स्पोर्ट को बढ़ावा मिले ।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में स्कूलों के अपग्रेडिंग के बारे में जिकर किया गया है, इसके बारे में मैं सरकार की सराहना किए बगैर नही रह सकता कि सरकार ने जो 97 स्कूल्ज अपग्रेड किए है, उनके अपग्रेड करनेरू के लिए कोई पैसा वगैरह नहीं लियाहै जैसा कि पिछली सरकार के वक्त से चला आ रहा था, इसलिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि यह जो कदम उसने उठाया है, वह बड़ा ही प्रशंसनीय एवं सराहना योग्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मेरी एक प्रार्थना है अपनी. जनता सरकार से कि महम का जो इलाका है, उसके अन्दर एक किलोमीटर तक कर्जे भी कालेज नही है । सस्कार का शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है, अत. सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और एक कालेज महम में अवश्य ही खोलना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो मिनट औत लेना चाहता हूं ताकि अपनी सारी बातों को इस हाउस में रख सकू ।

इससे आगे मैं नशाबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी केन्दीय सरकार की पालिसी है कि अगले चार सालों के अन्दर तमाम भारतवर्ष के अन्दर नशाबन्दी कानून लागू कर दिया जाएगा और पूर्ण रूप से नशाबन्दी होगी, इसलिए मेरी अपनी सरकर से भी दरख्वास्त है कि ग्रामों का उत्थान तब तक नही हो सकता जब तक कि वहां पर पूर्ण रूप से नशाबन्दी लागू नहीं की जाती । देहातों के लोग नही पनप सकेंगे । उपाध्यक्ष महोदय,

शराब गईने के बाद इन्सान इन्सान नहीं रहता, इन्सान इन्सान से भी नफरत करने लगता है, यहां तक कि शराब पी कर इन्सान भगवान. से भी नफरत करने लगता है । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि नशाबन्दी कानून को जल्द से जल्द देहातों में भी लागू किया जाए । हमारे सामने केवल यही एक लड़ाई है कि हम इस को जितनी जल्दी खत्म कर सकें, करें । देहाती भाइयों की शराब पीने से जो हालत हो जाती है उसका यहां जिकर करना चाहता हूं जैसे किसी ने कहा है–

जिन्दगी मौत नजर आती है,

रौशनी स्याह नजर आती है,

बात मैं सुबह की करुं कैसे

सुबह भी शाम नजर आती है ।

शराब पीने से मैं समझता हूं कि आदमी अपनी सुध बुध बिल्कुल ही खो देता है और उसको किसी तरफ भी कोई ध्यान नही रहता, अत मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस कानून को लागू कर सरकार गरीब किसानों को, गरीब देहाती भाइयों को बरबादी से बचाए ।

इसके साथ सरकार ने जो वृक्षों के बारे में कदम उठाया है, वह बड़ा ही सराहनीय है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । अन्त में मैं परिवहन के बारे में अपने विचार

रखना चाहता हूं । मैं अपने चीफ पार्लियामैंटरी सक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करुंगी कि महम के अन्दर कोई बस सटैण्ड नहीं है, वहां पर एक बस स्टैण्ड अवश्य बनाया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बो लने का समय दिया ।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस में बजट पर डिसकशन हो रही है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । बड़ी खुशी की बात है कि इस बजट को पिछले साल के बजट से 42 प्रतिशत की वृद्धि करके पेश किया गया है और इसेमें विशेष रूप से बिजली और सिंचाई आदि की व्यवस्था के लिए 68 परसैन्ट पैसा किसानों की भलाई केलिए खर्च किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि पिछली बार हरियाणा के पर प्रकृति का प्रकोप रहा है, बाढ़ से काफी नुक्सान हुआ है और इसके लिए सरकार को मेहनत करनी पड़ी, काफी साधन जुटाए गए जिसके लिए यह सरकार काफी धन्यवाद की पात हैं, लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यह जनता सरकार किन लोगों के सहारे पर यहां पर आई है । जिन लोगों ने सरकार को यहां बनाकर भेजा है, हमने उन के साथ बड़े वायदे कर रखे हैं लेकिन हमने अभी उन वायदों को पूरा करने के लिए उसमे कस्म नहीं उठाए जितने कि उठाने चाहिएं थे ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक् सदस्य चौधरी खुरशीद अहमद' जी पदासीन हुए ।)

हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने जब वे अपने हल्के में गए थे, तो उन्होंने वहां जाकर यह वायदा किया था, ऐलान किया था कि सवा छ एकड़ भूमि के जो गरीब किसान हैं, उनको मालिया से माफी दे दी जाएगी । तो मैं सरकार को उस वायदे का ध्यान दिलाता हूं कि उस वायदे को पूरा किया जाए । इसके साथ–साथ यह भी कहूंगा कि सरकार ने कई कर भी लगाए हैं । जैसे शराब के पर 20 प्रतिशत कर से बढ़ाकर 40 परसैन्ट कर दिया है, बिस्कूल ठीक है, चाहे 100 परसैन्ट कर दो, इसमें कोई बुराई नही है, क्योंकि शराब पीना एक गरीब आदमी, किसान की समस्या नही है, यह तो ऐशो–आराम करने केलिए एक फिजूलका खर्चा है । लेकिन सरकार तो किसानों पर टैक्स लगाने जा रहीहै, पहले जमीन की हद 30एकडू के लगभग थी, लेकिन अब सरकार ने 18 एकड़ कर दी है । मेरा सुझाव है कि जिसके पास 18 एकड इरीगेटिड लैण्ड है, या ज्यादा है, उस पर तो बेशक कर लगा दिया जाए, क्योंकि 18 एकड़ वाला तो किसान नहीं जमींदार है, और जमींदार पर कर बढ़ा दिया जाए, तो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जिन के पास दो–दो तीन–तीन किस्से जमीन है, उनके पर यह कर नहीं लगना चाहिए जिससे कि गरीब किसान दुखी न हो, और उसका भला हो सके । कल्लर भूमि होने पर किसानों को 50 से 75 परसैन्ट तक सबसिडी दी गई है । यह तो सरकार का

सराहनीय कदम हूं इससे लिगनों की पैदावार अधिक बढ़ेगी, इसलिए इसके साथ–साथ सरकार से मैं एक दरख्वास्त करुंगा कि जो रेतीले इलाके हैं, उन इलाकों को भी सबसिडी दी जाये, जिससे कि किसान आनी पैशवार बड़ा सकें और उस किसान का भला हो । इसके साथ–साथ सरकार की तरफ से जो गाड़ी वगैरह पर टैक्स लगाया गया है,ट्रकों पर, स्कूटरों पर, वह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, उनको तो दाल रोटी की पड़ी हुई है, जो ट्रकों वाले हैं, उनके लिए 1 00, 2 00, 400 रुपए कर के देना कोई मुश्किल बात नहीं है, यह सरकार का एफ सराहनीय कदम है । इससे आगे चेयरमैन महोदय, हमें पता है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने एच.सी.एस. वालों के ग्रेड बढ़ाकर आईएएस. आफिसरों से ज्यादा कर दिए, कोई बुरी बात नहीं है पर मेरा सरकार से सुझाव है कि जो छोटे मुलाजिम हैं, जिनके और कोई साधन नहीं हैं, उनकी ओर भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए । मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर सरकार छोटे मुलाजिमों को कोई और साधन नहीं जुटा सकती, तो उन लोगों से वापिस लेकर छोटे कर्मचारियों को दिया जाए ।

यह काम इस वक्त नहीं होगा क्योंकि आज ब्योरोक्रेसी शासन पर हावी है । लेकिन यह सवाल समाज सुधार का है अगर पिछली सरकार गरीब छोटे मुलजिमों का ध्यान ब्योरोक्रेसी की तरह रखती तो वह सरकार बदल नहीं सकती थी। उस सरकार के पीछे बड़े बड़े पूंजिपति और सारी डयूरोकेसी थी लेकिन फि र भी इन

गरीबों की हिम्मत से रातों रात वह सरकार का तखता पल्ट दिया गया हाउस से. बहुत से माननीय सदस्यों ने किसान को उसकी उपज का ठीक भाव देने के लिये बातें कही । अगर किसान की उपज का भाव बढ़ा भी दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह उस समस्या का हल नहीं होगा और मुलाजिमों की तनखाहें बडा दी जाएं तो भी समस्या का हल नहीं होगा । किसान की अगर कास्ट आफ प्रोडकशुन देखी गए 'तो उसके हिसाब से उसको भाव नहीं मिल सकता । किसान मुनाफा नहीं मांग रहैं। है वह तो अपना चर्चा ही मांगता है जोकि उसे नहीं मिलता है । जो मुनाफा होता है वह तौ बिचौले खा जाते एं । इसलिये सरकार इस काम के लिये एक ऐसी कमेटी बनाये जो किसान 'की उपज का भाव. तय करे । वह कमेटी एक तरफ जो चीजें कारखानो में पैदा होती हैं उनकी कास्ट आफ प्रोडकशन का हिसाब लगाये, दूसरी तरफ ' खेतों में पैदा होने' वाली चीजों को कास्ट आफ प्रोडकशन निकाले और तीसरी तरफ मुलाजिमों की तनखाह का हिसाब लगाये । यह हिसाब लगा कर तीनो की रेशों निकली जाए । इस चीज– से रोज रोज के झगड़े खत्म हो जाएंगे । न तो तनखाह का झगडा रहेगा और न ही किसान के भावों का झगड़ा रहेगा । मैं समझता हूं कि जब तक यह रेशो तय नही होती, तब तक किसानों तथा दूसरे वर्गों का भला नहीं हो सकेगा । इसके बाद सरकार ने जो शराब बन्दी का कदम उठाया है वह ' बहुत अच्छा कदम है । मैं चाहता हूं कि चाहे दूध के रेट बढ़ा दिये जाएं लेकिन शराब बन्दी जरूर लागू होनी चाहिये । शराब से हमें अब तक तो लगभग 25

करोड़ 'तक की सालाना आमदनी होती रही है जिससे कि डिवैल्पमैंट के काम होते थे वे काम चाहे कुछ 'देर कई लिये बन्द करने पड़े लेकिन यह जो शराब का कलंक है यह गरीब किसानों के 'पर बड़ी भौरी साजिश है । यह साजिश लोगों की विचारधारा को उनके आचरण को बिगाडने के लिये इस्तेमाल की जौ रही है । जब तक किसी देश या प्रदेश के लोगों कॉ आचरण ठीक नही होगा तब तक उस देश या प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता । आज लोगो को जो पैसा अपने परिवार की भलाई के लिये खर्च करना चाहिये वह धंसा' शराब पर खर्च हो रहा है और अगर शराब बन्दी हो जाती है तो यही पैसा किसान की जेब में जाएंगा । मैं सांयरू साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि शराब बन्दों का मसला केवल हमारे द्वारा भाषण देने से ही हल नहीं होगा बल्कि यह तो तभी हल होगा अमर हम वास्तव में यह सोचते हैं कि यह समाज पर कलंक है । इस चीज को देखते हुए कमं से कम इस सदन के सदस्यों को तया उच्च अधिकारियों को यह 'प्रण लेना चाहिये कि हम आगे से शराब नहीं पीएंगे

श्री सभापति : मैं आनरेबल मैबंर्ज से एक दर्खास्त करूंगा कि जब कोई भी मैंबर बोल रहा हो और किसी सदस्य को अपनी सीट से उठ कर दूसरी सीट पर जाना हो तो चेयर और बोलने वाले के दरिम्यान से उसे नही गुजरना चाहिये । यह सभी नोट कर ले ।

श्री हीरा नन्द आर्य : चेयरमैन सील, इससे आगे सरकार ने बेरोजगारी की खत्म करने के लिए जो कदम उठाया है यह बहूत ही अच्छा कदम है लेकिन यह खास इतना आसान नहीं है इसके लिये जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि तनखाहों का 1 और 5 की रेशो का क्राइटेरिया तय किया जाए । इसके साथ साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाउंगा कि

श्री सभापति : आप अब वाइंड–अप करे ।

श्री हीरा नन्द आर्य : चेयरमैन साहब, मैंने एक काल अटैनशन मोशन' भी दिया था जिसमें बहालगढ में कुछ मालिकों द्वारा गुड़ इकट्ठे करके मजादूरों पर हुमले का जिक्र था । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है विरू आज तक किसी कैं खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही' की जाये । इसके अलावा एमरजैसी के दौरान जिन लोगों के खिलाफ स्ट्राइकों में हिस्सा लेने के लिये ऐक्शन त्रिया गया था, उनमें से आज भी ऐसे आदमी हैं जिनको अभी तक नौकरी में बहाल नहीं किया गया है । जैसे एक परमा– नन्द नाम का व्यक्ति है जोकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफैसरों का प्रैजीडैट था उसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है और भी ऐसे बहुत से मसले है जिनके लिये अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है । इसके बाद मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाउंगा कि एक तरफ तो किसानों के लिये खाद की समस्या है और दूसरी तरफ जब छोटे गरीब आदमियों

को लोन दिया जाता है उसको जबरदस्ती खाद दी जाती है । इसका मैंने पिछले सैशन में भी जिक्र किया था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है । मैं सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि किसानों के साथ किसी तरह की जवदस्ती नहीं होनी चाहिये । ऐसा करने से तो जिस भावना से उसे लोन दिया जाता है वह बेमायने हो जाता है ।

इसके बाद मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा । सरकार ने जो स्कूल अपग्रेड किये हैं वे बहुत थोड़े किये हैं लेकिन एक बात है कि कोई भी अच्छी चीज अगर थोड़ी भी हो तो वह अच्छी ही रहती है । हरियाणा में इस वक्त दो यूनिवसिटियां हैं और मैं समझता हूं कि अगर दो यूनिवर्सिटियों का अच्छी तरह से इंतजाम न किया जा सके तो बनिसबत दो के एक ही यूनिवर्सिटी अच्छी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि दो यूनिवर्सिटियों पर खर्च न करके एक ही यूनिवर्सिटी अच्छे इन से चलाई जाए इसलिये जो रोहतक में यूनिवर्सिटी है उसको बन्द कर दिया जाए और वह पैसा जो उस पर खर्च होता है वह लड़कियों की शिक्षा के लिये खर्च किया जाए । सरकार स्कूलों को अप–ग्रेड करेगी । स्कूल किस तरह अप–रेड करेंगे, जैसे एम. एल. ए. कहेंगे' और एम. एल. ए. कैसे कहेंगे, जैसे लोग कहेगे और लोग कहां कहेंगे जैसे जहां लड़के ज्यादा होंगे । इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि रोहतक यूनिवर्सिटी को बन्द करे और उस पर जो पैसा खर्च होता है वहां खर्च करें जहा लड़कियों के स्कूलों

की मांग हो और पिछड़े हुए इलाकों की मांग हो ताकि सही मायनो में नीचे से शिक्षा का.. स्तर ठीक हो और स्कूलों से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके लोग यूनिवर्सिटी में कामयाबी हासिल कर सकें ।

चेयरमैन साहब, आपकी मारफत सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार ने जो रवैया अपनाया है. जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने जाहिर किया है कि सड्कों के सिलसिले में बहुत भेदभाव बरता गया है और भी कई बातें देखने वाली हैं जिनमें भेदभाव बरता गया है जैसे पानीपत शूगर मिल है । इन में पिछले साल लोगों को नौकरियों पर लगाया था और आज उनको नौकरियों से इसलिए हटाया जा रहा है, क्योंकि वे भिवानी जिले के थे । मैं समझता हूं कि अगर यही क्राइटेरिया अपनाया गया, यही रवैया रहा तो मैं खास तौर पर मन्त्रिगण का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि यह सोच वही सोच है जो बंसी लाल के राज में थी । अगर इस तरह से रवैया होगा तो जनता मुआफ नहीं करेगी । हमने जनता के सामने जो वायदे किए हैं उन को पूरा करना चाहिए । अगर बंसी लाल ने उनको नौकरियां दे दीं तो उनको हटाना नहीं चाहिए । जब हम बंसी लाल की तानाशाही से लड़ सकते हैं तो इनसे भी लड़ना जानते हैं । इसमें दो राय नहीं है ।

हमार, मुख्य मन्त्री महोदय के तीन–चार ऐडवाईजर हैं । मैं सरकार का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं इनकी

योग्यता पर सन्देह नहीं करता, इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि हरियाणा के लोग, हरियाणा के ऐडवाइजर, हरियाणा के लिए ईमानदार हो सकते हैं और जो बाहर से लिए हैं वे उधार निए हैं और वे उधार जैसा ही काम करेंगे । हरियाणा की सर्विसिज में दूसरे लोग भी योग्य हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं । इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसे एडवाइजर जिनका हरियाणा में हक है, हरियाणा के लिए दिलचस्पी है उन को लगाया जाए क्योंकि लोगों में इस बात की रिजैंटमैंट है । चेयरमैन साहब, आपने जो समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और सरकार से दरख्वासत करता हूं 'कि जो वाटर रैंट का टैक्स लगाया गया है, इस पर सरकार दोबारा गौर करे और मुझे उम्मीद है कि सरकार सही और जनवादी फैसला करेगी ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई) चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मैं बजट की जनरल डिसकशन पर बोलना चाहता हूं । मैं ऐसी ऐसी सुजैशन्ज पेश करना चाहूंगा जिमसे हरियाणा की काया पलट हो सकती है । चेयरमैन साहब, नहरी पानी हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है । अगर हरियाणा की सारी जमीन को नहरी पानी मिल जाए तो अकेला हरियाणा आधे हिन्दुस्तान को अनाज दे सकता है, सप्लाई कर सकता है । चेयरमैन साहब, पिछली सरकार की बुराइयां तो खूब देखीं लेकिन एक–आध अच्छाई को भी

देखर? चाहिए । पिछली सरकार ने क्रैश प्रोग्राम के तहत सारे हरियाणा में बिजली दे दी भी, हो सकता है कोई रह प्राध गांय वाकी रह गया हो । मैं वोह मिनिस्टर चौधरी रेशे नात से गर्का कला कि वे ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके तहत हरियाणा में एक साल के अन्दर अन्दर नहरी पानी दिया जाए, एक खूड भी बारानी न रहनी चाहिए । सूखे खेत हरे भरे हो जाएं । हमारे पास पैसे की कर्म। नही है, हरियाणा में ऐसे ऐसे पैसे वाले भाई बैठे है जो बहुत पैसा दे सकते हैं । सेठ भी बैठे हैं, सिर्फ सेठ ही नहीं दे सकते बल्कि किसान भी, जमींदार भी पानी के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं । पैसा लेने के बाद एक स्पैशल सैशन बुलाकर सारी मन्जूरी दे देंगे लेकिन एक भी खूड नहरी पानी के बगेर नही रहना चाहिए । आज. द्र। हिस्से में नहरी पानी लगता है और 2/3 जमीन सूखी पड़ी है । इस तरह सूखी जमीन से हरियाणा का सुधार नहीं हो सकता । आप फौरी तौर पर ऐक्शन लें, इसमें हरियाणा की भलाई है ।

चेयरमैन साहब, जहां तक फ्लड का ताल्लुक है, हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने काफी ड्रेनज मन्जूर की हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो दूसरी मदें हैं उन से रैसा काटकर इन जरूरी–जरूरी मदों में, जो बेयर नसैसिटी की मद्दें हैं, इनमें डाल दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा नहरी पानी के लिए और फलड की रोकथाम के लिए लगाया जाए । आप देख रहे है, फ्लड से हरियाणा की कितनी बुरी हालत है? बच्चे डूब कर मर गए,

छतों के नीचे दब कर मर गए, जानी–माली नुक्सान हुआ और सारी आबादी तबाह हो गई । गरीब हरिजनों के मकान गिर गए । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि फ्लड की यह बीमारी हमें अगले साल देखनी न पड़े, इसलिए कैश प्रोग्राम बनाकर इस बीमारी को खत्म करें । चेयरमैन साहब, फ्लड के पानी का जिक्र भी हाउस में आया कि मीलों तक पानी भरा पड़ा है । इस पानी को इकट्ठा करके बड़े बड़े तालाब बताए जाएं और उन तालाबों में मछलियां पाली जाएं । इससे सरकार के सामने जो बेरोजगारी की समस्या है वह भी हल होगी, पानी बढ़ेगा और आमदनी बढ़ेगी ।

चेयरमैन साहब, हरियाणा के लिए बिजली का होना बहुंत जरूरी है । जो बिजली बोर्ड बना है, उस पर सारे हरियाणा का पैसा खर्च होता है, जनता का पैसा खर्च होता है । इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कोई आजाद चीज नही है । इसमें जो अप्वायंटमैंट्स की जाती हैं उस में बोर्ड के मेम्बर हेराफेरी करते हैं । इसलिए चेयरमैन साहब, आपके जरिए हाउस से और मिनिस्टर साहब श्री वीरेन्द्र सिंह से प्रार्थना करूंगा कि बिजली के महकमें पर जो पैसा खर्च हो वह जायज हो, उसके सही ढंग से इस्तेमाल किग्रा जाए । यह लोगों के खून पसीने की कमाई है । मुझे अफ्सोस से कहना पड़ता है कि सही इस्तेमाल नहीं होता । मेरे मुकाबले में, इलैक्शन में जनता पार्टी ने एक आदमी को खड़ा कर दिया था जिसको जनता ने बुरी तरह से हरा दिया । उनको बिजली के तार के बारे में, बल्लब के बारे में, खम्भे के बारे में

कुछ पता नहीं लेकिन सरकार ने उसको बिजली बोर्ड का मेम्बर मुकर्रर कर दिया । बिजली बोर्ड का मेम्बर कोई टैक्नी– कल आदमी हो टैरड अफसर हो जो कुछ न कुछ बोर्ड का सुधार कर सके । सिर्फ नौकरी देने के लिए बिजली बोर्ड का मेम्बर बनाना बहुत बुरी बात है । चेयरमैन साहब, इनके बारे में हाउस में बार बार जिक्र आया है । मेम्बर बनने के बाद दो तीन महीन्ए के अन्दर मेरे उस भाई ने जो मेम्बर बना था, एक नई कार खरीद ली और घर में टलि– विजन लगा लिया । (विध्न)

Mr. Chairman : I would request the hon. Member not to count the assets of the person who is not present in the House.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : शुक्रिया चेयरमैन साहब । मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि बिजली बोर्ड का पैसा मिसयूज न किया जाए और कोई बात नही है । (विघन)

चेयरमैन साहब, बिजली के जो कुनैक्शन दिए जाते है उसमें बहुत हेरा–फेरी होती है । यह सरकार कुरप्शन रोकने की कोशिश तो कर रही है लेकिन फिर भी कुरप्शन पार्टी से पैदा हो ही जाती है । मुझे बड़े अफ्सोस से कहना पड़ता है कि यह जो मैम्बर हैं वे एक महान नेता के, जो कि सैन्टर में बहुत बड़े वजीर हैं, झूठे रिश्तेदार बनते फिरते हैं । इसलिए चेयरमैन साहब, मैं **चौधरी** ओम प्रकाश जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात को उनके नोटिस में ले आएं । (विध्न) चेयरमैन साहब, बिजली के

कुनैक्शन देने के बारे में मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए एम. एल. एज की एक कमेटी बनाई जाए जो इस काम को हर तहसील में जाकर सुपरवाइज करे ताकि लोगों को नम्बरवार कुनैक्शन मिल सकें । इससे जनता फजूल की हैरानी से बचेगी, उसे रिश्वत नही देनी पड़ेगी और उन्हे उनका हक ईमानदारी से मिलेगा ।

चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए हाउस– में बताना चाहता हूं कि इस देश में खेती बाड़ी का अदा–धरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अदायरा है । हरियाणा में मेरे भाई कहते है कि 85 फीसदी लोग इस पर निर्भर है लेकिन मैं कहता हू कि 100 के 100 फीसदी लोग खेती पर गुजार कर है क्योंकि किसी का सम्बन्ध डायरैक्टली है और किसी का इनडायरैक्टली है । जो लोग न्दरों में बसते हैं उनका भी खेती के बगैर गुजारा नही चलता । इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, वे देश की रीढ की हड्डी है । उनकी बहु–बैटियां बच्चे–बच्चियां, माता–पिता, मिट्टी के साथ मिलकर दिन रात काम करते हैं लेकिन उनको उनकी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिलती । इसलिए चेयरमैन साहब, मैं आपकी नारफत चौधरी साहब से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से यह कानून है कि फैक्टरी में अगर घाटा पड़ जाए, फैक्टरी अगर तबाह हो जाए, फैक्टरी अगर जल जाए तो उसको सारे का सारा पैसा सरकार देती. है उसी तरह से यदि किसान की पैदावार खराब हो जाए, उसे किसी तरह से नुकसान

हो जाए, तो उस सारे के सारे नुक्सान को सरकार को कम्पनसेट करना चाहिए । (विघन) यह बात भी ठीक है कि हमारी खेती बाड़ी का, हमारी फसल का बीमा होना चाहिए ताकि अगर नुकसान हो तो बीमा कम्पनी उसे पूरा करे ।

चेयरमैन साहब, यहां पर कल जिक्र आया कि लूगर मिल बन्द पड़ी है जबकि किसानों का गन्ना सूख रहा है । जिन किसानों का गन्ना उस मिल ने लिया था उन्हें अब तक पैसे नही मिले । चेयरमैन साहब, ईख की किसान खून पसीने से सींच कर एक साल तक सेवा करता है लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एक मिल मालिक उसको लेने में मजबूरी जाहिर कर रहा है । मैं आनरेबल मिनिस्टर को यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा का बच्चा–बच्चा आपके साथ है । क्या सारी कानून की ही बात देखनी डेए? आप प्रैक्टिकल बात को भी देखें । मेरे हल्के में इस बार बड़े ओले पड़े हैं । वहां सारी खेती को ओलों ने तबाह कर दिया है । चेयरमैन साहब, अफ्सोस की बात है कि जिस देहात में फ्लड आया था और सावनी की फसल मारी गई थी उसी देहात को ओलों ने तबाह कर दिया । उन गांव के नाम इस प्रकार हैं, देबण' । साउरन, तीतरम, हरसोला, पाई, सोंगल, सितला, सिसमर, खे डी सिकन्दर, मुन्नरहेडी, बुच्ची, रसीणा, आदमपुर, पिलणी, जठेडी, काकोत, जाम्बा, खेड़ा शेरन और प्योंदा । इसी तरह के और भी कुछ इला के हैं जो ओलों ने तबाह कर दिए हैं । इसलिए चेयर–मैन साहब, मैं वजीर साहब से कहना चाहता हूं कि जितनी भी

फसल तबाह हुई है उपका सारे का सारा पैसा सरकार को देना चाहिए जैसा कि यह फैक्टरी वालों को देती है । इसके अलावा फौरी तौर पर इमदाद के रूप में उनको घास और अनाज दिया जाए तथा उनक मुकम्मल मालिया माफ किया जाए । मिनिस्टर साहब को इस बात का आज ही हाउस में इलान कर देना चाहिए ।

चेयरमैन साहब, ऐनीमल हसबैन्डरी डिपार्टमैंट का काम बहुत जरूरी काम है । चूंकि मैं इस महकमे का वजीर रह चुका हूं इसलिए मैं इसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं । (विघन) इसके बारे में लोगों को आजकल शिकायत यह है कि हिसार में जो सांड पाले जाते हैं उनको पूरा दूध नहीं मिलता जिसकी वजह से वे अच्छे बछड़े पैदा नहीं कर सकते । इसलिए सरकार को चाहिए कि उनको ज्यादा दूध दिलाने का इन्तजाम करवाए ताकि वे अच्छे बछड़े पैदा करने में कामयाब हो सकें । (विघन)

श्री सभापति : कहीं रखवाली करने वाले तो दूध नहीं पी जाते?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : चेयरमैन साहब, मेरी यह भी प्रार्थना है कि इनसैमिनेशन सैन्टर हर हल्के में खोले जाएं ताकि क्रौस बिडिंग की फैसिलिटिज गांव– गांव में दी जा सकें । (विघन)

चेयरमैन साहब, इसके साथ साथ मैं सरकार से एक और प्रार्थना करूंगा और मैं समझता हूं कि डाक्टर मंगल सैन जी मेरे से सहमत होंगे । आजकल आपने देखा होगा कि जो ग0 माताएं ड्राई हो जाती है उनको कई लोग घरो से निकाल देते हैं और आज वे स्लाटर हाउस में जा रही हैं । इनका इन्तजाम अवश्य किया जाना चाहिए । अगर हर जिले में एक एक ड्राई कैटल फार्म खोल दिया जाए तो इससे एक तो उनका बचाव हो सकता है और दूसरे सरकार को इससे काफी आमदनी हो सकती है । (विघन) जिस वक्त वे दूध के काबिल हो जाएं! लोग उन्हें दुबारा ले जा सकते हैं । उनके मरने के बाद उनकी चमडा और हड्डियां भी बिक सकती हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि हर जिले में एक एक ड्राई कैटल फार्म इसी बजट सैशन से चालू कर दिया जाए । (विध्न) इसके अलावा, चेयरमैन साहब, मैं यह चाहता हूं कि एक एक गांव में

एक एक गौशाला खोली जाए । ग0शाला का जो खर्च होगा या आमदनी होगी वह पंचायत के जिम्मे लगाई जाए । मेरा नारा तो, चेयरमैन साहब, यह है कि हर गांव में एक कन्या पाठशाला, एक ग0शाला और एक व्यायामशाला इसी बजट सैशन से शुरु कर दी जाए और इनकी आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब पंचायत के जिम्मे लगा दिया –जाए । (हंसी)

चेयरमैन साहब, डेरी– डिवैल्पमैंट के बारे में भी. मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं । मेरे ख्याल में ग्रीन रैवोल्यूशन

तो हमारी' स्टेट में बहुत आ रहा है, इसके जरिए लोगों में काफी खुशहाली आ रही. है लेकिन मेरी' प्रार्थना यह है कि यहां वाईट रेवो– ल्यूशन भी आना चाहिए । कैथल में एक ऐसा यूनिट चालू किया जाए जिसके जरिए किसान अपना दूध बेच सकें । इस तरह का यूनिट हर शहर में होना चाहिए ताकि हर आदमी अपनी रोजी कमा सके ।

चेयरमैन साहब, कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के बारे में भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं । जिस तरह हांसी में स्पीनिंग मिल चालू की गई हे इसी. तरह की. मिलें और जगह भी. चालू की जानी चाहिए । इससे मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि आज किसान को उसकी कपास का पूरा भाव नहीं मिलता । (विध्न) इस तरह की मिल हर तहसील में खोली जाए ताकि लोगों को उनकी पैदावार का पूरा पूरा भाव मिल सके ।

चेयरमैन साहब, लैड डिवैल्पमैंट बैक हरियाणा की बड़ी सेवा कर रहा है । लेकिन इसके बारे में चौधरी साहब से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जहां रहन जमीन छुड़ाने के लिए पैसे दिलवाए जाते हैं वहां जमीन खरीदने के लिए भी पैसे दिलाने चाहिए ।

चेयरमैन साहब, हमारी सरकार ने छोटे छोटे कारखाने खोल कर बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की है । लेकिन चेयरमैन साहब मैं कहना चाहता हूं कि इस बेरोजगारी को मुकम्मल. तौर पर न तो ये खत्म कर सकते हैं और न आगे आने

वाली सरकार कर सकती है । फिर भी हें प्रार्थना करूंगा कि यह जो आप 110 या 103 यूनिटस लगा रहे हैं इन्हे बराबरी से लगाएं । यहां बार बार कहा जाता है कि सड़के केवल सिरसा और हिसार में जा रही हैं । यही शिकायत पहले थी कि **चौधरी** बंसी लाल केवल अपने इलाके में डिवैल्पमैंट के काम कर रहे हैं । वही शिकायत यदि जनता सरकार के समय में आनरेबल **चौधरी** देवी. लाल. जी के होते हुए हो तो बड़ी माडी बात है । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो कोई भी काम हो वे सारे के सारे 90 हल्कों में हो । सरकार की सेवा का पैमाना हमारे पास एक ही हो सकता है कि यदि सारे के सारे 90 हल्कों में खर्च बराबर बराबर किया जाए तभी लोग सरकार के साथ होंगे, सभी एम. एल ए. इनके साथ होंगे । किसी को हार्ट बनिन्ग नहीं होनी चाहिए । सारे हरियाणा में हमारी रिश्तेदारी हैं । कहीं किसी का छोरा व्याह रखा है तो कहीं किसी की छोरी व्याही हुई है (विघ्न) चौधरी साहब, मैं भी हिसार जिले में ब्याहा हुआ हूं । (हंसी) चिन्ता की कोई बात नहीं है, संबको बराबर का हक मिलना चाहिए । चेयरमैन साहब, अब सड़कों का सवाल है । **चौधरी** वीरेन्द्र सिंह का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक सड़क तो मेरे हल्के में भी मंजूर कर दी है उसका नाम है थुआ से छातर । इस सड़क को इसी बजट में रखा है लेकिन मेरे अपने हल्के में दो–तीन सड़कें और हैं जो कि मैन रोड्स से गांव को नहीं मिलाती हैं । एक तो खेडी सम्बलवाली दूसरी राहड़ा और तीसरी सीसवाली है, इन तीनों हड़को को जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए । दूसरी बात यह

है कि जो सड़कें फ्लड से डैमेज हुई 'हैं उनपर बड़ा सलो काम हो रहा है । उनपर भी जल्दी से जल्दी काम कराया जाना चाहिऐ ।

चेयरमैन साहब, चौधरी जगन नाथ जी तो मेरे पक्के दोस्त हैं । उनसे भी आपके जरिए रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि कैथल डिपो की कुल 134 बसें मंजूर हैं । उनमें से 40 बसें आउट आफ आर्डर हैं । रोड़ खाली पड़ी रहती हैं वहां पर बसें नहीं चलती हैं । गुहला मेरे अपने हल्के में लोग बसों की छतों पर बैठ कर चलते हैं । एक आदमी छत से गिर कर मर गया । इसलिए आपके जरिए निवेदन करता हूं कि मेरे अपने हल्के में 40 बसें नयी चलाई जानी चाहिएं और जो बसों को घाटा है इसको पूरा किया जाये । पेहवा के अन्दर बस स्टैन्ड नहीं है । वहां पर भी बस स्टैन्ड जरूर बनाया जाये । ट्रांसपोर्ट विभाग को बहुत बड़ी आमदनी है इसलिए आसानी से बनाया जा सकता है ।

अब एजुकेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । सब से खुशी की बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लड़कियों की एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने तरीका नहीं बताया कि किस तरीके से बढ़ाया चाहते हैं? तरीका मैं बताता हूं । हरियाणा प्रान्त में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए । हरेक लड़की को कम से कम पांच जमात जरूर पढ़ाया जाना चाहिए । मेरी सरकार से दरखास्त है कि हर गांव के अन्दर इसी साल से कन्या पाठशाला चालू कर दी जाये ताकि लड़कियों

को तालीम मिल सके । मैं तो यह कहूंगा कि पांच जमात तक हर लड़की की तालीम कम्पलसैरी कर दी जाये । हरिजन से ब्राह्मण तक सब लड़कियां पढ़ें । जो भी स्कूल अपग्रेड किये जा रहे हें वे सब हल्कों में किये जायें । पाई हल्के के अन्दर भी मिडल स्कूलों को हाई स्कूल किया जाये । जो भी स्कूल अपग्रेड किया जाये वह मेरी सलाह से किया जाये । जो स्कूलों में हैडमास्टर्ज हैं उनका इम्तहान न लिपा जाये । वे बच्चे पडाने का काम करें या इम्तहान दें । उनका रिजल्ट अच्छा है तो उनको प्रमोट कर दिया जापे या इन्क्रिमेट दे दी जाये । जिन को रिजल्ट खराब हूं उनको ससपैन्ड़ कर दिया जाये ।

चेयरमैन साहब, मैं कर्नल साहब से और डा0 मंगल सैन से दरखास्त करूंगा कि कैथल के अन्दर जाट हाई स्कूल को एक आदमी ही लूट रहा है । हमारे होम मिनिस्टर साहब को अच्छी तरह से पता है कि जब सिविन में गोली चली तो मैं अकेला ही आदमी था जिसने मुकाबला किया था । मुझे प्रेजिडेन्टशिप से पुलिस ने– जब्रदस्ती निकाल दिया था । मेरे विरोध के बाद भी उसको कुर्सी पर जब्रदस्ती बैठा दिया । अगर उसकी कोई मैनेजमैंट कमेटी हो तो बात ठीक है लेकिन अकेला आदमी सारी जनता को लूट रहा है । वहां एक साल में पांच–छ लाख रुपया चन्दे का जमा हो जाता है, बह सारा पैसा खा रहा है । मैं आपके जरिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसको हटाया जाये । उस स्कूल के अन्दर बी. एड कलासीज भी हैं । कैथल में गवर्नमैंट को

एक कालेज भी बनाना चाहिए और एक स्टेडियम भी बनाया जाये ।

चेयरमैन साहब, अब मैं हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हू । आप पहले हैल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं । हैल्थ डिपार्टमैंट से लोगों को दवाइयां नही मिलती हैं । दवाईयों का प्रबन्ध ठीक प्रकार से होना चाहिए । हररू मरीज को दवाई बाहर से लानी पड़ती है । जब रोहतक के अन्दर मैडिकल कालेज बना तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि लोगों को आराम मिलेगा लेकिन उसके बारे में लोगों का विचार है कि यह तो सलाटर हाउस है, कसाइयों का हत्था है । इस बारे में मेरा विचार है एक कमेटी बनायी जाये जो उसके काम को देखे । वे जो लोगों का ट्रटिमैंट करते हैं वे ठीक तरह से नहीं करते है । दूसरे वहां पर जो ऐडमिशन दिया जाता है उसमें भी काफी गड़बड़ है । जो लड़के हमारे हरियाणा के डाक्टर ऑफ मैडिशन्ज और डाक्टर ऑफ सर्जरी में ऐडमिशन लेना चाहते हैं उनको नहीं मिलता है । वहां पर जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं वे बाहर के लोगों को ऐडमिशन दे देते हैं लेकिन हरियाणा के जवानों को नहीं देते हैं । जो भी ऐडमिशन होता है उसमें हरियाणा के लोगों को लिया जाना चाहिए, बाहर की स्टेट के लोगों को न लिया जाये । हरिजनों के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । छोटी उम्र की हमारी बहु–बेटियां हैं उनको सड्कों पर मजदूरी करने से बन्द किया जाये और जो दूसरे तबके कें लोग हैं उनको इजाजत दी जाये । इनकी

मजदूरी बहुत कम है उसको बड़ा कर कम से कम 10 रुपया किया जाये ।

एक बहुत जरुरी बात और कहना चाहता हूं जिस पर सारा तोड है । बाते तो बहुत लम्बी–चौड़ी हैं लेकिन मैं आपके जरिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि हरियाणा की गरीब जनता को खचें से बचाने के लिए जो हरियाणा के बीच में शहर पड़ता है वहां पर तीन जजों का एक सरकिट बैन्च बनाया जाये । हरियाणा का और पंजाब का हाईकोर्ट तो यों का ये। रहे परन्तु एक अलग से सरकिट बैम्ब खोला गये ताकि रियाज। के गरीब लोगो को इतना पैसा यहां याने पर न खर्च करना पडे ।

श्री सभापती : अब आप खत्म करें । आपका टाईम हो गया है ।

श्री जगजीत सिंह पोहलू :. चेयरमैन साहब, इस बजट में जो हरियाणा की जनता पर टैक्स लगाये गये उनके बारे में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं । एक तो मैं पैसेन्जर टैक्स की पुरजोर मुखालफत करता हूं । यह पैसेन्जर टैक्स गरीबों पर पड़ता है । यह आम आदमी को देना पड़ता है । चेयरमैन साहब, यह मेरा तोड़ है कि किसान के पर जो आबयाना बढाया है यह बड़ा भारी गलत काम हुआ है । आबयाना बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । किसान हरियाणा का निर्माता है, वह इस देश की रीड की हड्डी है । किसान का बेटा छाती तान कर अपने मुल्क को बचाने के

लिए फौज में भर्ती होता है । अपने मुल्क की सेवा करता है, दूसरे मुल्कों के हमलों से रक्षा करता है । किसान का ही बेटा है जो ऐसा करता है और किसी की हिम्मत नहीं है । अगर उसको हम अच्छा खिलायेंगे तो वह दूसरे मुल्क का मुँह तोड़ देगा लेकिन बड़े अफ्सोस के साथ कहना पड़ता है कि चौधरी बंसी लाल की सरकार ने पहले ही किसानों को तबाह किया हुआ था । उन्होंने पहले ही लन्ड पर टैक्स लगाया हुआ था लेकिन अब उनपर और जुल्म किया जा रहा है । पहले ही चालीस–पचास रुपये किले के देने पड़ते अब और भी बढ़ा दिया है । चेयरमैन साहब कमाल की बात तो यह है कि मेरी जनता सरकार जो गरीब किसानों से वोट ले कर आयी है । यह हल की तस्वीर से वोट ले कर आयी है । आप इस पैम्फलेट में देख सकते हैं कि उसके पांव में जूता नहीं है, कोई शरीर में कुर्ता नहीं है, धोती भी पूरी नहीं है । उसके सिर पर मेरी तरह से तुर्रहा (पगड़ी) नहीं है । उस गरीब किसान ने कन्धे पर हल उठाया हुआ है । तो मैं सारे हाउस से दरखास्त करूंगा कि ''जटा पगड़ी सम्भाल भाई'' वाली बात है । जनता सरकार जो इस साल एलान करके आयी थी उसके मुताबिक चलने का प्रयत्न करे । मैं इस बजट की पुरजोर मुखालफत करता हूं । चेयरमैन साहब मैं आपका एक–दों मिनट और लेना चाहता हूं । मैं अब तो सिर्फ सुजैशन देना चाहता हूं कि जनता सरकार की आमदनी कैसे हो । जो टैक्स बढ़ा है उसको कैसे घटाया जाये?

Mr. Chairman : The House stands *adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 8th March, 1978.

13.00 बजे

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 8th March, 1978)